

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

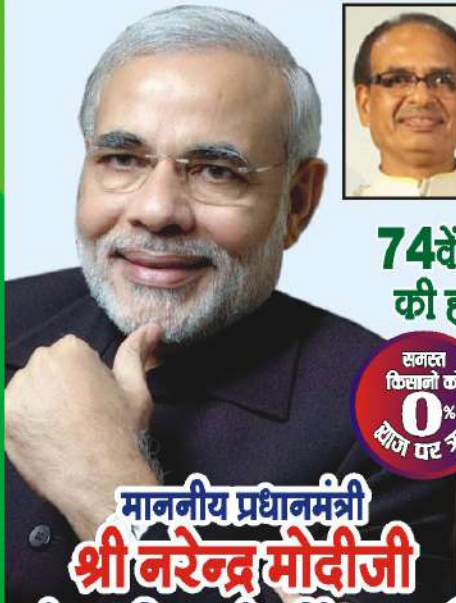
» वर्ष : 10 » अंक : 11 » सितंबर 2020 » मूल्य : 40 रु.

Email : hariyalikeraste2010@gmail.com

सीमा पर बिगड़ते हालात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को
जन्मदिवस की शुभकामनाएँ





74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

समस्त
किसानों को
0%
ब्याज पर ऋण

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी

की जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ



स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण ○ खेत पर रोड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड ○ कृषि यंत्र के लिए ऋण ○ दुग्ध डेयरी योजना



श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री ओ.पी. गुप्ता
(प्रशासक एवं उपायुक्त)



श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री विशेष श्रीवास्तव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

संजय

श्री बालकृष्ण शर्मा (शा.प्र. नागदा) श्री शिव हरदेनिया (शा.प्र. भेरूगढ़) श्री भेरूलाल पाटीदार
श्री नेपालसिंह डोडिया (पर्य. नागदा) श्री बलवीर चौहान (पर्य. भेरूगढ़) (शा.प्र. रुनिजा)
श्री रमेशचंद्र विश्वकर्मा (पर्य. नागदा) श्री गोपाल साधू (पर्य. भेरूगढ़)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. रामगढ़, जि.उज्जैन
श्री फिरोज खान (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. हिर्डी, जि.उज्जैन
श्री नेपालसिंह डोडिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. बड़ागाँव, जि.उज्जैन
श्री ईश्वरसिंह सिसोदिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बोरखेड़ा भल्ला, जि.उज्जैन
श्री राजेश नायक (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
झिरव्या शेख, जि.उज्जैन
श्री शादाबुद्दीन कुरैशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. रुपेटा, जि.उज्जैन
श्री रविन्द्र कुमार शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख स.संस्था मर्या.
पिपलियाहामा, जि.उज्जैन
श्री कन्हैयालाल शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. बनबना, जि.उज्जैन
श्री भगवानसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. रोहलखुर्द, जि.उज्जैन
श्री उदयसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. रुनिजा, जि.उज्जैन
श्री गोपाल रणछोड़ (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. टूटियाखेड़ी, जि.उज्जैन
श्री अशोक पोरवाल (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. सोडंग, जि.उज्जैन
श्री सज्जाद कुरैशी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. खेड़ावदा, जि.उज्जैन
श्री कैलाश यादव (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. झांसाखेड़ी, जि.उज्जैन
श्री अजयसिंह पवार (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. रुई, जि.उज्जैन
श्री ओमप्रकाश चौहान (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बालोदा लक्खा, जि.उज्जैन
श्री शंकरलाल पांचाल (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. पिपसा माता, जि.उज्जैन
श्री भैवरसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. कालियादेह, जि.उज्जैन
श्री सुरेन्द्र उपाध्याय (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. भाटपचलाना, जि.उज्जैन
श्री ओमनारायण सिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. बेरखा, जि.उज्जैन
श्री रमेशचंद्र विश्वकर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. उज्जैन, जि.उज्जैन
श्री दीपक बैरागी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. बादरबेला, जि.उज्जैन
श्री भैवरसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सहकारी संस्था
मर्या. भाटीखुड़ा, जि.उज्जैन
श्री टीकमसिंह सिसोदिया (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
गोयला बुजुर्ग, जि.उज्जैन
श्री नानकरामजी (प्रबंधक)

**समस्त संस्थाओं के
प्रशासकों की ओर से**



राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

» वर्ष : 10 » अंक : 11 » सितंबर 2020 » मूल्य : 40 रु.



- » विशेष संरक्षक : जूनापीठाधीश्वर
आचार्य महामंडलेश्वर अनन्त श्री विभूषित
स्वामी अवधेशानंद गिरिजी महाराज
- » संरक्षक : विष्णु नारायण त्रिपाठी
- » प्रधान संपादक : बृजेश त्रिपाठी

- » प्रबंध संपादक : अर्चना त्रिपाठी
- » सलाहकार मंडल :
व्ही.जी. धर्माधिकारी (सेवानिवृत्त सचिव एवं आयुक्त सहकारिता)
एल.डी. पंडित (सहकारी विशेषज्ञ)
सुशील मिश्र (पूर्व अपर आयुक्त सहकारिता)
मणिशंकर उपाध्याय (कृषि विशेषज्ञ)
एम.एस. भटनागर (कृषि रत्न, बीज विशेषज्ञ, सलाहकार बीज संघ)
सुरेशचंद्र ताम्रकर (वरिष्ठ पत्रकार)
डॉ. आर.ए. शर्मा (पूर्व डीन, कृषि महाविद्यालय, इंदौर)
डॉ. वी.एन. श्रॉफ (कृषि वैज्ञानिक)
यशोवर्धन पाठक (व्याख्याता जबलपुर)
पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक' (अध्यक्ष, म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद्)
डॉ. राजीव शर्मा (प्रोफेसर एवं कवि, इंदौर)
डॉ. भरत शर्मा (समाजसेवी)
हरप्रसाद मोदी (वरिष्ठ पत्रकार, झाँसी-ललितपुर)
अरुण के. बंसल (फ्यूचर पॉइंट प्रा.लि., नई दिल्ली)
पं. रत्न वशिष्ठ (ज्योतिषाचार्य एवं कथावाचक)
लेफ्टिनेंट कर्नल अजय (वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य)
कैप्टन (डॉ.) लेखराज शर्मा (ज्योतिषाचार्य)
- » विशेष संवाददाता
इंदौर-उज्जैन संभाग : परीक्षित शर्मा (मो. 7999692727)
भोपाल संभाग : आलोक मालवीय (मो. 9806750146)
होशंगाबाद संभाग : धनराज मालवीय (मो. 9827744248)
छत्तीसगढ़ (रायपुर) : पी.एल. चुरहे (मो. 7389652211)
- » प्रकाशक : बृजेश त्रिपाठी
306/ए-ब्लॉक, सहनाई-॥ रेसीडेसी, कनाडिया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 8989991569, 9752558186
- » लेआउट-डिजाइन : नितिन पंजाबी (मो. 9893126800)
ई-मेल : nitinpunjab15@gmail.com
- » मुद्रक : वी.एम. ग्राफिक्स
कै-29, एल.आय.जी. कॉलोनी, इंदौर

3

एल.ए.सी. पर
बिगड़ते हालात



6

चौथी क्रांति के
जरूरी हथियार



9

किसानों की मेहनत से सफल
होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान



13

वायुसेना का
आत्मबल बढ़ा



21

आलू की उन्नत खेती



27

जंगल और वन्य प्राणियों के
रक्षक आदिवासी समाज



30

सार-समाचार



60

केबीसी की शूटिंग
शुरू





किसान रेल एक सार्थक पहल

पिछले माह देश में पहली किसान रेल का शुभारंभ हुआ। किसान रेल चलाने की घोषणा वित्तमंत्री ने पिछले बजट में की थी। पहली किसान रेल की शुरुआत महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच हुई है। यह सप्ताह में दो बार सोमवार और शुक्रवार को चलेगी। यह एक तरह की पार्सल ट्रेन है जो किसानों की उपज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। अगर किसान स्पेशल द्वारा 50 फीसद फसलों का भी परिवहन किया जाता है तो इससे लगभग 45 हजार करोड़ रुपये की हानि को रोका जा सकेगा। यह ट्रेन सुपर फास्ट गति से चलेगी जिससे फसलों को तुरंत गंतव्य तक पहुँचाया जा सकेगा। वर्तमान समय में सुपरफास्ट परिवहन के अभाव में फल और तरकारियाँ समय पर पहुँच नहीं पाती थीं और इनके सड़ने से किसानों को काफी हानि होती थी। उनकी सारी मेहनत और बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि पर किया गया खर्च व्यर्थ चला जाता था। किसान स्पेशल भारतीय रेलवे के इतिहास में एक नई इबारत साबित होगी। प्रधानमंत्री ने 2022 तक हमारे किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निश्चय ही किसान स्पेशल इस लक्ष्य की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। किसान स्पेशल में केवल फल और सब्जियाँ ही नहीं, दूध, मांस, मछली जैसे खाद्य पदार्थों की भी ढुलाई होगी। महाराष्ट्र के नासिक इलाके में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती होती है। यहाँ से देश के अनेक भागों में प्याज पहुँचाया जाता है। अभी तक इसके लिए केवल सड़क परिवहन का ही उपयोग होता रहा है, जो महँगा तो पड़ता ही है, साथ ही गंतव्य तक माल पहुँचाने में देरी का सबब भी बनता है। देरी की वजह से बीच रास्ते में ही प्याज सड़ने लगता है और इस प्रकार किसान तथा व्यापारी दोनों को नुकसान उठाना पड़ता है। समय पर आपूर्ति नहीं होने से अनुत्पादक इलाकों में अभाव की स्थिति निर्मित हो जाती है और भाव बढ़ने से उपभोक्ता भी परेशान होते हैं। केन्द्र सरकार की इस योजना

के तहत अब देश के विभिन्न भागों में किसान स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएँगी। जाहिर है इससे कृषि उपज एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना अत्यंत सुगम हो जाएगा। यह कदम काफी पहले ही उठाया जाना चाहिये था। बहरहाल, जब जागे तब ही सवेरा। भले ही देर से सही, यह प्रयास अच्छा है और किसान, उपभोक्ता, व्यापारी सभी के हित में है। आईसीएआर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी ने अपनी एक रपट में कहा था कि हर साल लगभग 92 हजार करोड़ रुपये के खाद्य पदार्थ समुचित परिवहन के अभाव में खराब हो जाते हैं। इनमें दूध, मांस, मछली, अंडे, फल और सब्जियाँ शामिल हैं। ये ट्रेनें वातानुकूलित डिब्बों वाली होंगी जिससे इन खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाया जा सकेगा। केन्द्र सरकार इसी तरह की ट्रेनें देश के अन्य भागों में भी चलाएगी। किसान इनमें अग्रिम बुकिंग करा सकेंगे। इन ट्रेनों के चलने से चौबीस घंटे में महाराष्ट्र से उत्तरप्रदेश के प्रयागराज तक आम, अंगूर और केला आसानी से पहुँचाया जा सकेगा। पहली किसान स्पेशल का लाभ देश के चार राज्यों महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार को मिलेगा। मध्यप्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर, इटारसी, जबलपुर, सतना शहर इस ट्रेन से जुड़ जाएँगे। शीघ्र ही देश के अन्य भागों में भी ऐसी ट्रेनें चलने पर अन्य शहर व गाँवों के कृषक व्यापारी भी लाभान्वित होने लगेंगे। देश के जिन भागों में रेल नेटवर्क नहीं है वे फिलहाल तो सड़क परिवहन द्वारा अपनी उपज निकटवर्ती रेलवे स्टेशनों तक पहुँचाएँगे। लेकिन सरकार को समूचे देश के किसानों तक किसान स्पेशल ट्रेनों का लाभ देने के लिए रेल नेटवर्क के विस्तार को अंजाम देना जरूरी है, तभी यह प्रयास पूरी तरह सार्थक सिद्ध होगा।

सुजय विपरी



एलएसी पर बिगड़ते हालात

हर्ष वी. पंत » रणनीतिक निदेशक, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन

बीती 29 और 30 अगस्त की रात को भारतीय और चीनी सेना यानी पीएलए में एक बार फिर मुठभेड़ हो गई। इस बार जंग का अखाड़ा बना पैंगोंग झील का दक्षिणी किनारा। यह वह इलाका है, जो अभी तक मौजूदा टकराव से अछूता रहा। इससे पता चलता है कि आखिर वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर हालात कितने तल्ख हो गए हैं। भारतीय सेना पीएलए के मंसूबों को ध्वस्त करते हुए उन ऊंची चोटियों पर काबिज हो गई, जहां से उसे बढ़त मिल सके। नई दिल्ली ने बीजिंग के समक्ष स्पष्ट कर दिया है कि एलएसी पर चीन द्वारा भारी संख्या में सैन्य अमला जुटाने के बावजूद भारत अपने रणनीतिक लाभ की स्थिति को नहीं छोड़ने वाला। वहीं मॉस्को में चीनी रक्षा मंत्री की मनुहार के बाद उनसे मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने चीनी समकक्ष को दो-टुक लहजे में कह दिया कि भले ही भारत की प्राथमिकता वार्ता के जरिये मसलों को सुलझाने की है, लेकिन नई दिल्ली राष्ट्र की क्षेत्रीय अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

जहां लगातार दावे-प्रतिदावे किए जा रहे हों, वहां भारत का नया रुख एलएसी पर भविष्य को भी रेखांकित करता है। अदेशा

है कि भारी-भरकम सैन्य जमावड़े वाली सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच अक्सर छोटी-मोटी झड़पें होती रहेंगी। इसका पता गत दिवस की उस झड़प से लगता भी है, जिसमें चीनी सेना की ओर से गोली चलाई गई।

एलएसी पर हालात तनावपूर्ण ही बने रहने के आसार हैं। यहां होने वाले संभावित टकराव भारत-पाक के बीच एलओसी पर अक्सर होने वाली तनातनी की याद दिलाएंगे। कुल मिलाकर अब यही नई परिपाटी बनती दिख रही है। इस साल अप्रैल-मई में जबसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा है, तबसे हालिया टकराव के बीच एक ब्रिगेड स्तरीय फ्लैग मीटिंग की बात सामने आई है। हालांकि इसके नतीजे को लेकर अनिश्चितता और अस्थिरता का भाव ही अधिक है। वैसे भी दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच कई दौर की वार्ता के बावजूद इस संकट के दूर होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। ऐसी आशंकाएं बढ़ रही हैं कि एलएसी पर हल्की-फुल्की मुठभेड़, गोलीबारी और घात लगाकर किए जाने वाले हमलों में इजाफा होगा, जैसा कि हम कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच देखते आए हैं। ऐसे में पीएलए के किसी भी मंसूबे को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना को उसी हिसाब से पर्याप्त तैयारी रखनी होगी। इन कदमों के अतिरिक्त रक्षा प्रतिष्ठान को सीमा के आसपास पर्याप्त सुरक्षा बलों की तैनाती पर भी ध्यान देना होगा, जैसा कि पीएलए ने भी किया है।

चीन ने इस साल मई से ही लद्दाख सीमा पर सैन्य जमावड़ा बढ़ाकर अपनी स्थिति को मजबूत किया है। इसी कड़ी में चीन ने तिब्बत स्वायत्तशासी क्षेत्र यानी टार में जिन सैन्य साजोसामान की खेप बढ़ाई है, उनमें हेलीकॉप्टर गन, हेलीकॉप्टर गन और एयरक्राफ्ट आदि शामिल हैं। 29-30 अगस्त के टकराव के साथ-साथ चीन ने और धमकाने वाले अंदाज में कैलाश-मानसरोवर क्षेत्र में भी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल बेस पर 2,200 किमी तक मारक क्षमता वाली डीएफ-21 बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं। यह ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और करनाली जैसी उन नदियों के मुहाने पर है, जो देशों की सीमाओं से परे बहती हैं। इनमें से करनाली तो गंगा की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डीएफ-21 भारत के भीतरी शहरों को भी निशाना बना सकती है। यह मिसाइल किसी भी पारंपरिक हमले की स्थिति में एक अहम कवच मुहैया कराती है। ऐसे में भारत को जवाबी कार्रवाई के लिए प्रतिरोधक क्षमताओं के साथ सामरिक जमावड़ा बढ़ाना होगा।

भारत अभी तक विशुद्ध रूप से रक्षात्मक रणनीति का पालन करता आया है। ऐसे में इससे जुड़ी कमियों को दूर करते हुए जवाबी हमले की सटीक रणनीति तैयार करनी होगी। वैसे 2013 से ही भारतीय सैन्य बलों ने एलएसी पर जमावड़ा बढ़ाकर सीमित आक्रामक नीति अपनाई है। अब भारत को अपेक्षाकृत लंबी अवधि के संघर्ष के लिए स्वयं को तैयार करना होगा। इसमें

एक ऐसे दौर में जब भारत एलएसी पर नए दस्तूर का सामना कर रहा है, तो उस स्थिति में वह पुराने रणनीतिक ढांचे पर भरोसा नहीं कर सकता। यह अच्छा है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता तो उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्हें बीजिंग के समक्ष यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे किसी भी विकल्प पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह संतुलन साधने की नाजुक कवायद भले हो, लेकिन आवश्यक अवश्य है।

स्थानीय स्तर पर लचीलापन अहम भूमिका निभाएगा। मिसाल के तौर पर भारतीय सेना और वायु सेना को नागरिक हवाई अड्डों का भी प्रभावी उपयोग करना चाहिए। हमले के बाद उससे उबरने की अचूक रणनीति भी तैयार करना निर्णायक होगा। अपनी हवाई क्षमताओं को इस प्रकार विस्तार देना होगा कि जिन स्थानों को निशाना बनाने की अधिक आशंका हो, उन्हें जल्द से जल्द दोबारा तैयार किया जा सके।

अब इसकी आशंका अधिक है कि चीन भारतीय जमीन पर अपनी नीयत और खराब करता रहेगा। अतिक्रमण उसे सबसे असरदार विकल्प लगेगा, जैसा कि लद्दाख में उसने किया भी। भारतीय सेना भी जिस मोर्चे पर बढ़त की स्थिति में होगी, वहां हरसंभव तरीके से ऐसी कोशिशों का प्रतिकार करती रहेगी।

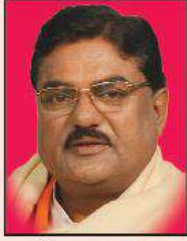
ऐसे में चीनी सैन्य सनक से निपटने के लिए भारत को कुछ अलहदा विकल्प भी तलाशने होंगे। यदि एलएसी के हालात भी एलओसी जैसे बन जाएंगे, तो बहस परमाणु शस्त्रों की ओर भी बढ़ जाएगी। अलहदा रणनीति में आक्रामकता का भाव शामिल करना ही होगा। भारत को अडिगल चीन और उसकी सेना को यही संकेत देने होंगे कि तनाव बढ़ने से उसे फर्क नहीं पड़ने वाला। यह न तो भारत के लिए आसान विकल्प है और न ही ऐसा कि चीन को इसकी कोई कीमत न चुकानी पड़े, परंतु दशकों से चीन की पारंपरिक चुनौती के आगे अपनी अपेक्षित क्षमताओं को न बढ़ाने के चलते भारत के समक्ष विकल्प सीमित होते जा रहे हैं।

एक ऐसे दौर में जब भारत एलएसी पर नए दस्तूर का सामना कर रहा है, तो उस स्थिति में वह पुराने रणनीतिक ढांचे पर भरोसा नहीं कर सकता। यह अच्छा है कि भारतीय नीति निर्माताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि चीन अपनी आदत से बाज नहीं आता तो उनके पास सभी विकल्प खुले हुए हैं। उन्हें बीजिंग के समक्ष यह भी स्पष्ट करना होगा कि वे किसी भी विकल्प पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह संतुलन साधने की नाजुक कवायद भले हो, लेकिन आवश्यक अवश्य है। खासतौर से अगर भारत उस थकाऊ बहस से बाहर निकलना चाहता है कि उसके पास चीन के खिलाफ कोई सैन्य विकल्प नहीं है अथवा विकल्पों की तो भरमार है, लेकिन उनमें किसी का रहस्य प्रकट नहीं किया है। ●





श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

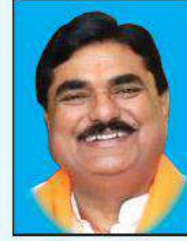
श्री जितेन्द्र शर्मा
(भारसाधक अधिकारी)

श्री मदनसिंह अखाड़े
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
गौतमपुरा, जिला इंदौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ठेरे पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौर एवं समय पर भुगतान पाएँ।

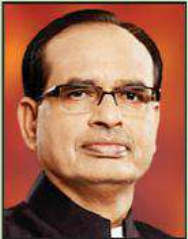


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री रवीश श्रीवास्तव
(भारसाधक अधिकारी)

श्री प्रभुलाल भिलवाड़ा
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सांवेर, जिला इंदौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हमाल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हमाल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री अंशुल गुप्ता
(भारसाधक अधिकारी)

श्री संतोष मंडरे
(प्रभारी सचिव)

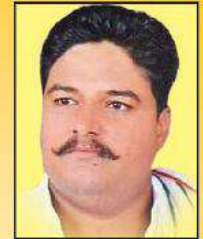
सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
महू, जिला इंदौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



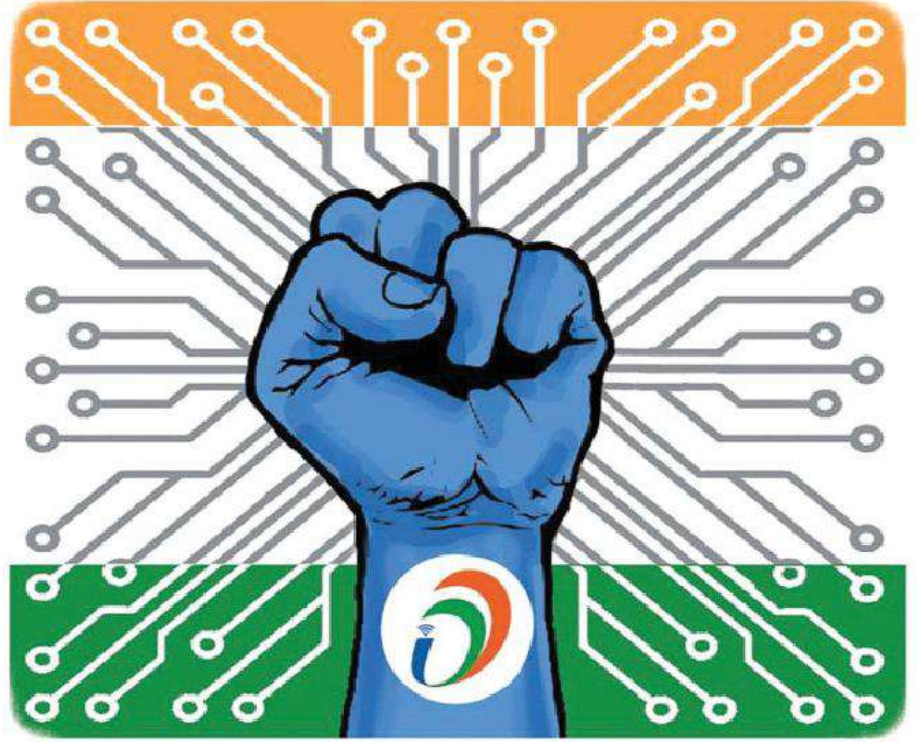
श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री अजमेरसिंह गौड़
(भारसाधक अधिकारी)

श्री एल.डी. सुखवानी
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
धामनोद, जिला धार (म.प्र.)

चौथी क्रांति के जरूरी हथियार



प्रांजल शर्मा » डिजिटल नीति विशेषज्ञ

वक्त आ गया है, भारत आत्मनिर्भरता के लिए अपनी तकनीकी बुनियाद तैयार करे। भारत को तकनीकी संप्रभुता की ओर तेजी से बढ़ना होगा। इस बात का क्या मतलब है? आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं, जहां 3डी प्रिंटिंग, ऑटोमेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन जैसे कनेक्टेड डिवाइस सभी तरह की गतिविधियों के लिए मौलिक हो गए हैं। ये सब चौथी औद्योगिक क्रांति के आधार तत्व हैं। जो देश इन तकनीकों का उपयोग अपने खुद के प्लेटफॉर्म बनाने के लिए नहीं करेगा, उसे समाधान की तलाश में बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ेगा। प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता हमारी आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

भारत को अपनी तकनीकी क्षमताओं के निर्माण के लिए अपने निवेश और कोशिशों को तेज कर देना चाहिए। हमें गौर करना चाहिए कि चीन ने अमेरिका के तकनीकी मुकाबले के लिए क्या-क्या कदम उठाए थे? वह 2030 तक अमेरिका की तकनीकी बराबरी कर लेने के लक्ष्य के साथ बढ़ रहा है। अनेक मामलों में चीन की आलोचना हो सकती है, लेकिन हमें सीखना चाहिए कि दूरगामी रणनीति बनाकर तकनीकी संप्रभुता को कैसे हासिल किया जा सकता है। दवा क्षेत्र पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करना होगा। ज्यादातर दवाओं के लिए 60 से 80 प्रतिशत सामग्री चीन से आयात की जाती है। ऐसा पिछले 15 वर्ष में हुआ है, जब हमने आयात को मंजूरी देते हुए अपने देश में निर्माण को खत्म या कम होने दिया।

आज तकनीकी संप्रभुता का मोल बहुत अधिक है, हमारा उद्देश्य भारत को डिजिटल बुनियादी ढांचे के मामले में आत्मनिर्भर बनाना होना चाहिए। हमारे व्यवसायों और सरकारी कामकाज में लगे अधिकांश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर हमारा अपना नियंत्रण होना चाहिए। आइए, हम कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेते हैं, जहां संप्रभु नियंत्रण की जरूरत है। संप्रभु नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि सरकार ही डिजिटल बुनियादी ढांचे की मालिक हो जाए। इसका मतलब है, सरकार को व्यापक जनहित के लिए इस क्षेत्र या काम को विनियमित करने में सक्षम होना चाहिए।

हमें सबसे पहले डाटा और साइबर सुरक्षा चाहिए। भारत दुनिया में सबसे बड़े खुले बाजार वाला लोकतंत्र है। एक अरब से अधिक नागरिकों से जुड़े डाटा को घरेलू संस्थानों द्वारा ही नियंत्रित और विनियमित किया जाना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में डाटा के स्थानीयकरण और गोपनीयता पर जीवंत बहस चली है और एक अच्छे लोकतंत्र में यह बहस होनी चाहिए। भारत को डाटा के उपयोग को लेकर स्पष्ट कानून बनाने होंगे। डाटा संरक्षण कानून पर अभी भी संसद में चर्चा चल रही है और उम्मीद है, इसी साल एक सशक्त और व्यावहारिक कानून बन जाएगा। इसी से जुड़ा है साइबर सुरक्षा का मामला। आज नकद सब्सिडी देने से लेकर करोड़ों के कारोबार तक ऑनलाइन हो गए हैं। व्यवसाय के हर आयाम को साइबर सुरक्षा की जरूरत है। आज की दुनिया में साइबर हमला सीमा पर हमले की तुलना में अधिक हानिकारक हो सकता है। फिलहाल भारत को साइबर सुरक्षा प्रबंधन के लिए भारतीय या मित्र देशों द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना होगा। हमें समान विचारधारा वाली कंपनियों के साथ ठीक

उसी तरह काम करना चाहिए, जैसे हमने आतंकवाद विरोधी गठबंधन बनाया है। सरकार साइबर सुरक्षा नवाचार के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बना रही है। आगामी वर्षों में करोड़ों लोग डिजिटल मुख्यधारा में शामिल होंगे, उन्हें डिजिटल माहौल के हिसाब से प्रशिक्षित करने का काम हो सकेगा।

दूसरी जरूरत है सुरक्षित सामाजिकता और संवाद विकसित करना। इंटरनेट ऐंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईएएमएआई) की ताजा रिपोर्ट में भारत में डिजिटल बाजार पर प्रकाश डाला गया है। देश में 50 करोड़ से अधिक सक्रिय इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 50 प्रतिशत से अधिक गांवों में हैं। लगभग 14 प्रतिशत यूजर्स 5 से 11 वर्ष की आयु वर्ग में हैं। इसका मतलब है, 7.10 करोड़ नाबालिग मोबाइल या होम वाई-फाई का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी भी यूजर्स असुरक्षित श्रेणी में हैं। चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाने से इन लाखों यूजर्स की सुरक्षा हुई है। रोपोसो और चिनगारी जैसे भारतीय सोशल वीडियो ऐप का तेजी से उदय हुआ है।

तीसरी जरूरत है डिजिटल ढांचा और विनिर्माण पर ध्यान

कोविड बाद की दुनिया में भारत आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। तकनीक हमारे भविष्य का नेतृत्व करे, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना देश की सीमाओं की रक्षा। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियां खुली और समतावादी हैं। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास करना ही होगा।

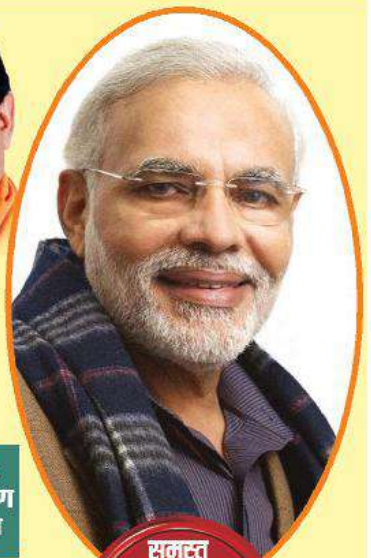
देना। मोबाइल फोन संचार के हार्डवेयर से लेकर रक्षा विनिर्माण तक, पेमेंट गेटवे से ऊर्जा उत्पादन उपकरण तक, सभी क्षेत्रों में भारत को आत्मनिर्भरता का विकास करना चाहिए। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने मास्टरकार्ड और वीजा जैसे वैश्विक दिग्गजों के एकाधिकार का मुकाबला करने के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) ऐप और रूपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत की है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) का निर्माण, जिस पर भीम और रूपे काम करते हैं, भारत की आत्मनिर्भरता की ओर उठाया गया शानदार कदम है। यूपीआई के तहत जून 2020 में 35 अरब डॉलर से भी अधिक के 1.34 अरब लेन-देन हुए हैं।

भारत को अपनी नीतियों में सुधार करने के साथ ही उपयोगी शिक्षा में

निवेश बढ़ाना चाहिए। अच्छी खबर है कि सरकार सभी मोर्चों पर उत्सुकता से आगे बढ़ रही है। 'इंटरनेट ऑफ थिंग्स' और 'मशीन लर्निंग' जैसे पद अब सरकार की चिंता का हिस्सा हैं। पिछले बजट में यह वादा किया गया था कि पांच साल में 80 अरब रुपये खर्च करके डाटा सेंटर पार्क, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी और अप्लिकेशंस बनाए जाएंगे। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों को भारत नेट फाइबर-टू-होम कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए 60 अरब रुपये का प्रावधान भी कर रखा है। उम्मीद है, त्रुटिपूर्ण डाटा संग्रह प्रणालियों को नई प्रक्रियाओं के साथ तेजी से ठीक किया जाएगा।

कोविड बाद की दुनिया में भारत आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध दिख रहा है। हालांकि यही पर्याप्त नहीं है। शी जिनपिंग ने चीन और उसके संस्थानों में 2025 तक एक ट्रिलियन डॉलर से अधिक के निवेश की घोषणा कर रखी है। इसके साथ ही, भारत को समान विचारधारा वाले देशों के साथ गठबंधन बनाना चाहिए। भारत और अन्य देशों को चीन के नेतृत्व वाले नियमों में फंसने से बचने के लिए प्रौद्योगिकी के अपने मानक गढ़ने होंगे। तकनीक हमारे भविष्य का नेतृत्व करे, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना देश की सीमाओं की रक्षा। आज सीमाएं आभासी हो गई हैं, जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति तोपखाने की मारक क्षमता से भी अधिक मायने रखती है। चौथी औद्योगिक क्रांति की प्रौद्योगिकियां खुली और समतावादी हैं। भारत को एक वैश्विक नेता के रूप में चमकने के लिए अपनी तकनीकी क्षमताओं का विकास करना ही होगा। ●





स्वतंत्रता
दिवस की
73
वीं वर्षगांठ पर
हार्दिक
शुभकामनाएँ

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान
क्रेडिट
कार्ड

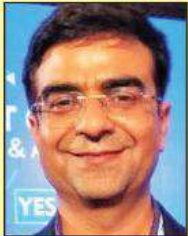
कृषि यंत्र
के लिए
ऋण

दुग्ध डेयरी
योजना
(पशुपालन)

मत्स्य
पालन हेतु
ऋण

स्थायी विद्युत
कनेक्शन
हेतु ऋण

खेत पर
रोड निर्माण
हेतु ऋण



श्री चंद्रमौलि शुक्ला
(कलेक्टर एवं प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(प्रशासक एवं उपायुक्त)

श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री के.एन. त्रिपाठी
(बैंक सीईओ)

सौजन्य से : श्री कमलसिंह तंवर (शा.प्र. सतवास) श्री सुखलाल मौर्य (शा.प्र. काँटाफोड़)

समस्त
किसानों को
0%
दराज पर ऋण

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
गोदना, जि.देवास
श्री यशवंत पंवार
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
सतवास, जि.देवास
श्री गणेश प्रसाद वर्मा
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
नामवपुर, जि.देवास
श्री सुरेश कर्मा
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
डाबरी, जि.देवास
श्री जगदीश यादव
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
जिनयाली, जि.देवास
श्री रमजान शेख
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
अतवास, जि.देवास
श्री तुलसीराम यादव
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
निमासा, जि.देवास
श्री कैलाश मालवीय
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
काटाकोटा, जि.देवास
श्री यशवंत पंवार
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
तोहार्दा, जि.देवास
श्री ज्ञानेन्द्र जोशी
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
पीपलकोटा, जि.देवास
श्री संतोष तिवारी
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
खारिया, जि.देवास
श्री गोविन्द यादव
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
बेड़गाँव, जि.देवास
श्री मोतीलाल गेहलोत
(प्रबंधक)

सेवा
सहकारी संस्था मर्या.
भैसूत, जि.देवास
श्री राजेश मीणा
(प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

किसानों की मेहनत के बलबूते पर ही सफल होगा 'आत्मनिर्भर भारत अभियान'



(योगेंद्र कौशिक)

इसमें दो राय नहीं कि किसानों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में कोई कसर छोड़ी। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि सरकारों के पास खरीदे गए किसानों के उत्पाद को भंडारण करने की क्षमता नहीं है। हवाई अड्डों, मंडी प्रांगण और अन्य स्थानों पर बरसाती ढँककर कृषि उत्पाद को रखा देखा जाता है लेकिन अभी भी देश के किसानों की स्थिति चिंताजनक है। ऐसे में सवाल उठता है कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की बारी कब आएगी? पैदावार तो बंपर होती है लेकिन लागत मूल्य में वृद्धि किसान के मार्ग में रोड़ा है। गौरतलब है कि किसानों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आजादी के सात दशक बाद भी धरातल पर ज्यादा काम नहीं हुआ, और नतीजा यह कि आज 'कर्ज किसानों का मर्ज' बन गया है। नीति नियंता ऐसी स्थिति कब पैदा करेंगे कि किसान को उसके उपज का अच्छा और पूरा दाम मिले और कर्ज लेने की नौबत ही नहीं आए।

भारतीय अर्थव्यवस्था का कड़वा सच यह है कि देश के आबादी का बड़ा हिस्सा (लगभग 54%) आजीविका के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है लेकिन कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) कृषि और उसके जुड़ी गतिविधियों का योगदान राष्ट्रीय स्तर कम होता जा रहा है। उदारीकरण के दौर में किसानों व खेतिहरों की आबादी की आमदनी, दूसरे पेशेवर तबकों की तुलना में ना के बराबर ही बढ़ी है। यह बात पिछले वर्षों में जारी नाबार्ड के प्रतिवेदन में कृषि क्षेत्र और गैर कृषि उपक्रमों की आय में दर्शाया गया है।

वर्तमान में देश भर में लघु सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। वर्तमान के परिदृश्यों को छोड़कर, आजादी के बाद जो भी घोषणाएं हुईं कोरी घोषणा ही साबित हुई है। हाँ, वर्तमान की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए हितकारी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से भी किसानों को संबल मिला। कृषि में स्टार्टअप योजना में सरलीकरण की संभावना है उस पर भी चिंतन करना चाहिए। जैसे किसी किसान का बेटा खाद्य प्रसंस्करण की कोई इकाई या फिर पशुपालन की योजना लेकर आता है तो बैंक ऋण में काफी परेशानी होती है। अतः बैंकों में एक हेक्टर से अधिक के किसान के लिए 15-20 लाख का लोन दे देना चाहिए क्योंकि एक हेक्टर भूमि की कीमत लगभग हर क्षेत्र में 50 लाख से कम नहीं है।

आत्मनिर्भर भारत अभियान में कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इसी क्षेत्र में रोजगार और विकास की सर्वाधिक अवसर की गुंजाइश है। देश का किसान एवं कृषि क्षेत्र में जिन समस्याओं से जूझ रहा है उसका समाधान भी इस अभियान के माध्यम से हो सकता है, जैसे मनरेगा के माध्यम से किसानों के खेतों पर काम देकर रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना जिससे किसानों की लागत मूल्यों में कमी होगी और वह आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो सकेगा।

हमारे देश के गांव गौ आधारित व परम्परागत कृषि योजनाओं एवं लाभकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के माध्यम से जैविक खेती के महान प्रयोग स्थल बनकर उभर सकते हैं। इससे कृषि में लागत मूल्य में कमी के कारण किसान का सशक्तिकरण भी होगा और देश दुनिया के सामने खड़ी पर्यावरण कि चुनौतियाँ भी कम होंगी। किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिले, बाजार मिले, उत्पादकता बढ़े और उत्पादन लागत में कमी हो जिससे किसान खुशहाल हो।

आज भले ही किसान अपनी उपज देश भर के अन्य प्रदेशों की मंडियों में बेचने का कानून बनाया है लेकिन हर आम छोटे किसानों के लिए यह असंभव सा होगा। किसानों की उपज का हर उत्पाद समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) पर ही उत्पादन बिके और प्राकृतिक आपदा से कृषि उपज की गुणवत्ता के नाम पर मंडियों में किसानों का शोषण रुके। इस पर भी नीति नियंता को चिंतन करना चाहिए क्योंकि कोई भी किसान अपनी उपज की गुणवत्ता कभी खराब नहीं करता है। यह सब प्रकृति के प्रकोप जैसे खंडवर्षा-अतिवर्षा, ओला, पाला आदि से उसकी उपज खराब होती है। उस समय किसान असहाय और एक मूकदर्शक की तरह देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकता। इस परिस्थिति पर भी चिंतन हो कि कृषि उत्पाद एम.एस.पी. से कम बिकने पर सरकारें भावांतर भुगतान योजना के रूप में प्रतिपूर्ति करें। प्रतिवर्ष बैंकों के माध्यम से कृषि ऋण में वृद्धि करना इसका निदान नहीं होगा। नीतियाँ ही ऐसी बने कि किसान स्वयं आत्मनिर्भर हो सके और वह ऋण ही नहीं ले। तभी देश के किसानों का लगाव खेती से रहेगा और खेती लाभ का धंधा बनेगी।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को कृषि के क्षेत्र में गंभीरता से साकार स्वरूप प्रदान करने से ही समृद्ध और संपन्न भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके लिए कृषि क्षेत्र में जो भी योजनाएं बनाएं वह धरातल पर उतरे ताकि भारत का किसान, आत्मनिर्भर किसान बन सके।

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान...! ●

मप्र कृषि उपज मंडी अधिनियम संशोधन विधेयक 2020 के मुख्य बिंदु

- मंडी क्षेत्र के स्थान पर मंडी प्रांगण के नियमन की अवधारणा।
- मंडी प्रांगण में शासकीय मंडियां/उप मंडियों, सभी प्रकार के प्राइवेट मार्केट यार्ड/मार्केट सब यार्ड, डायरेक्ट खरीदी केन्द्र और डीमंड मार्केट शामिल।
- मंडी प्रांगण के बाहर ट्रेड एरिया में होने वाले समस्त कृषि संव्यवहारों का नियमन भारत सरकार के अध्यादेश के अनुसार।
- संचालक, कृषि विपणन की पदस्थापना और शासकीय/ प्राइवेट/ डीमंड मंडियों तथा व्यापारियों की लाइसेंसिंग एवं नियमन के समस्त अधिकार।
- समस्त मंडी समितियों के अधिकार संबंधित मंडी प्रांगण/उपमंडी प्रांगण तक सीमित।
- मंडी प्रांगण में केवल व्यवस्था के सुचारू संचालन के अधिकार मंडी समिति को। नियमन के समस्त अधिकार संचालक, कृषि विपणन को।
- मंडी प्रांगण के बाहर के समस्त जांच/चैकिंग/नाके समाप्त।
- मंडी बोर्ड का अधिकार क्षेत्र मंडी प्रांगण केविकास एवं कार्मिक संबंधी गतिविधियों तक सीमित।
- मार्केट फीस का निर्धारण राज्य शासन द्वारा।
- आयातित कृषि उपज पर मंडी शुल्क नहीं।
- सीधी खरीदी केन्द्र के अतिरिक्त अन्य सभी शासकीय/अशासकीय/डीमंड मंडियों में नीलामी के माध्यम से ही कृषि उपज का क्रय-विक्रय।

निजी मंडी व्यापार लाइसेंस एवं पंजीकरण के प्रमुख प्रावधान :

- राज्य में अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रणाली की व्यवस्था।
- संचालक, कृषि विपणन या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी, लाइसेंसिंग प्राधिकारी।
- व्यापारिक और संबद्ध गतिविधियों के नियमन की समस्त शक्ति, संचालक में निहित।

व्यापार लाइसेंस - आवेदन शुल्क 500 रुपये, लाइसेंस शुल्क 5000 रुपये, अवधि 10 वर्ष होगी।

परफॉर्मेंस गारंटी - न्यूनतम 3 लाख रुपये या एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के बराबर, जो भी अधिक हो।

फल-सब्जी के लिए परफॉर्मेंस गारंटी न्यूनतम 50 हजार रुपये या एक दिन की अधिकतम क्रय क्षमता के बराबर, जो भी अधिक हो।

लाइसेंस जारी करने की अवधि - सात दिवस तथा नवीनीकरण की अवधि - एक कार्य दिवस। लाइसेंसधारी अधिसूचित कृषि उपज के प्रत्येक क्रय-विक्रय एवं भंडारण के नियमित लेखों का संधारण करेगा। कृषक से क्रय की गई कृषि उपज का उसी दिन भुगतान। मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (प्राइवेट मार्केट यार्ड, प्राइवेट मार्केट उप-यार्ड और डायरेक्ट क्रय केन्द्र की स्थापना)।

नियम 2020 के प्रमुख प्रावधान : प्राइवेट मार्केट यार्ड,

प्राइवेट मार्केट उप-यार्ड और डायरेक्ट क्रय केन्द्र (विपणन संग्रहण केन्द्र) की स्थापना और संचालन के लिए लाइसेंस का प्रावधान। 'प्राइवेट मार्केट सब-यार्ड' अर्थात् गोदाम, सायलो, कोल्ड स्टोरेज या ऐसी अन्य संरचना या स्थान, जो किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित, संचालित और प्रबंधित किया जाता है, जिसमें निर्धारित बुनियादी अधोसंरचना और सुविधाएं हैं। 'डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र' अर्थात् ऐसे केन्द्र जिनका संचालन और प्रबंधन किसी व्यक्ति या फर्म द्वारा इन नियमों के अंतर्गत प्रदान की गई स्वीकृति से, आपसी सहमति के आधार पर, किसानों की कृषि उपज की खरीदी के लिए किया जाएगा।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी - संचालक, कृषि विपणन।

लाइसेंस अवधि - प्राइवेट यार्ड तथा प्राइवेट मार्केट सब-यार्ड के लिए 20 वर्ष तथा डायरेक्टर क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र के लिए 10 वर्ष। एफपीओ/कृषि सहकारी समितियों द्वारा संचालित डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र के लिए परफॉर्मेंस गारंटी 50 प्रतिशत ली जाएगी।

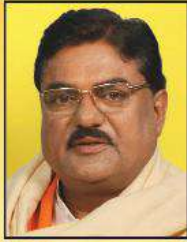
लाइसेंस आवेदन के निराकरण की अवधि - प्राइवेट मार्केट यार्ड/मार्केट सब यार्ड के लिए - 30 दिवस। नियत अवधि में लाइसेंस स्वीकृति/रद्द का निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में लाइसेंस स्वीकृत माना जाएगा। लाइसेंस स्वीकृति के दिनांक से निर्माण कार्य पूरा करने के लिए तीन वर्ष का समय दिया जाएगा तथा तीन वर्ष के भीतर मंडी प्रारंभ करने के लिए, परफॉर्मेंस गारंटी के साथ आवेदन करना होगा। डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र के लाइसेंस के लिए आवेदन निराकरण की अवधि - सात दिवस। लाइसेंसी द्वारा प्राइवेट मार्केट यार्ड, प्राइवेट मार्केट सब यार्ड और डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र के लिए जरूरी अधोसंरचना/ बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना होगा।

मूल्य निर्धारण प्रक्रिया - प्राइवेट मार्केट यार्ड तथा प्राइवेट मार्केट सब यार्ड में - घोष विक्रय द्वारा की जाएगी तथा डायरेक्ट क्रय (विपणन संग्रहण) केन्द्र में - क्रेता-विक्रेता की आपसी सहमति से होगी।

निरीक्षण के अधिकार - संचालक या उसके द्वारा अधीनस्थ अधिकृत अधिकारी को होंगे। मंडी बोर्ड/मंडी समितियों द्वारा वर्तमान में जारी समस्त निजी डायरेक्ट क्रय केन्द्रों के लाइसेंस इन नियमों के प्रभावी होने के दिनांक से समाप्त नहीं होंगे, बल्कि इन नियमों के तहत जारी किये गए माने जाएंगे तथा इनका नवीनीकरण नए नियमों के अंतर्गत होगा। लाइसेंसधारी मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण एवं प्रदर्शन करेगा तथा कृषक को भुगतान उपरांत ही कृषि उपज का परिवहन सुनिश्चित करेगा। ●



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

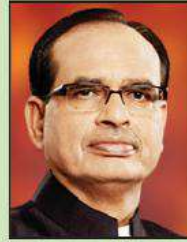


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री बी.एस. कलेश
(भारसाधक अधिकारी)

श्री चिमनसिंह मंडलोई
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
कुशी, जिला धार (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हमाल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हमाल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

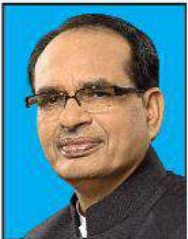


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

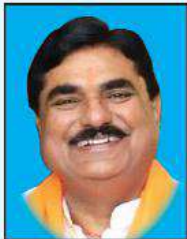
श्री महेश बडोले
(भारसाधक अधिकारी)

श्री एच.एल. पाटीदार
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
राजगढ़, जिला धार (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

श्री संजीव पाण्डे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री भगतसिंह डाबर
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

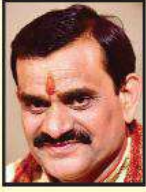


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री अभयसिंह खरारी
(भारसाधक अधिकारी)

श्री के.के. दिनकर
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
झाबुआ, जिला झाबुआ (म.प्र.)



सौजन्य से
श्री जितेन्द्रसिंह चौहान (शा.प्र. गंधवानी)

श्री प्रवीण बर्वे (शा.प्र. निसरपुर)

श्रीमती कुमुद मोरे (शा.प्र. सिंघाना)

श्री भेरूलाल पाटीदार (शा.प्र. तिरला)

श्री सुरेन्द्रसिंह पंवार (शा.प्र. बाकानेर)

श्री भुवानसिंह नर्मेश (शा.प्र. धामनोद)

श्रीमती प्रतिभा शुक्ला (शा.प्र. धरमपुरी)



भारत के मानवीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ
74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

किसान
क्रेडिट
कार्ड
कृषि यंत्र
के लिए
ऋण
दुग्ध डेयरी
योजना
(परुपालन)
मत्स्य
पालन हेतु
ऋण



श्री जगदीश कचौज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री अम्बरीश वैद्य
(प्रशासक एवं उपायुक्त)



श्री गणेश यादव
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री आर.एस. वसुनिया
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गंधवानी, जि.धार
श्री गोविन्द आर्य (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. अवल्दामाव, जि.धार
श्री अशोक सवनेर (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बिल्दा, जि.धार
श्री नारायण चोयल (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. जीराबाद, जि.धार
श्री अमरसिंह भदोरिया (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पीपली, जि.धार
श्री रामलाल चौहान (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. तिरला, जि.धार
श्री अशोक पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. आहू, जि.धार
श्री राजेन्द्र व्यास (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. सिंघाना, जि.धार
श्री बाबूलाल गेहलोत (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. लंगूर, जि.धार
श्री लक्ष्मण परिहार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. देदला, जि.धार
श्री लोकेन्द्रसिंह तंवर (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. करोली, जि.धार
श्री दिनेश मलतारे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. निसरपुर, जि.धार
श्री दशरथ पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. चिखल्दा, जि.धार
श्री मोहम्मद मंसूरी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मुसारी, जि.धार
श्री प्रवीण उपाध्याय (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. बाकानेर, जि.धार
श्री तुलसीराम वर्मा (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. मिर्जापुर, जि.धार
श्री वीरेन्द्र कानूनगो (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. धरमपुरी, जि.धार
श्री निलेश जोशी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. उमरवन, जि.धार
श्री अनिल मंडलोई (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. काली वावड़ी, जि.धार
श्री महेश दुबे (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. तुल्हेरा बुजुर्ग, जि.धार
श्री इकबाल खान (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. भवाल्या बुजुर्ग, जि.धार
श्री राम वर्मा (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. धामनोद, जि.धार
श्री भूपतसिंह चौहान (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. गुजरी, जि.धार
श्री राजेश पारीख (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. खलघाट, जि.धार
श्री देवीसिंह चौधरी (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सहकारी संस्था मर्या. धामनोद, जि.धार
श्री अजय पाटीदार (प्रबंधक)

आ.जा.सेवा सह. संस्था मर्या. पटलावद, जि.धार
श्री मुन्नालाल वर्मा (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से



वायुसेना का आत्मबल बढ़ा

प्रमोद भार्गव » आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ

आखिरकार दुश्मनों का पसीना छुड़ा देने वाले पांच फ्रांसीसी फाइटर जेट राफेल भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन गए। चीन से तनाव के चलते राफेल का सेना में शामिल होना सैनिकों का मनोबल बढ़ाएगा। ये लड़ाकू विमान लड़ाख की ऊंची पहाड़ियों की छोटी जगह पर भी उतर सकते हैं। इसे समुद्र में चलते हुए युद्धपोत पर भी उतारा जा सकता है। इन विमानों को आसमान से युद्ध के लिए विलक्षण माना जाता है। दरअसल राफेल अनेक खूबियों से भरा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मिनट में 60,000 किमी की ऊंचाई पर न केवल पहुंच जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला भी करने में सक्षम होता है। मिसाइलों से लैस ऐसे विमान फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं हैं। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली तीन तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। तय है, राफेल का भारतीय धरती पर आगमन दुश्मनों को सबक भी है। वैसे भी चीन और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि उनकी कोई भी हरकत प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व और ठोस सामरिक क्षमता के चलते उन पर भारी पड़ सकती है।

देरी और दलाली से अभिशात रहे रक्षा सौदों में राजग सरकार

के वजूद में आने के बाद से लगातार तेजी दिखाई दी है। मिसाइलों और रॉकेटों के परीक्षण में भी गतिशीलता दिखाई दे रही है। वरना रक्षा उपकरण खरीद के मामले में संप्रग सरकार ने तो लगभग हथियार डाल दिए थे। बावजूद सवाल उठता है कि इस विमान की खरीद में विपक्ष और राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक बेबुनियाद आरोप-प्रत्यारोप लगाकर अड़गे लगाते रहे। इस कारण खरीद में जरूरत से ज्यादा देर ही हुई। जबकि इनके खरीदे जाने का फैसला मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में ही हो जाना चाहिए था। किंतु रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार के चलते तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटनी तो इतने मानसिक अवसाद में आ गए थे कि उन्होंने हथियारों की खरीद को टालना ही अपनी उपलब्धि मान लिया था। नतीजतन, हमारी तीनों सेनाएं शस्त्रों की कमी का अभूतपूर्व संकट झेल रही थीं। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस गतिरोध को तोड़ा है और राफेल विमानों की खरीद सुनिश्चित की। अन्य हथियारों व उपकरणों की खरीद का सिलसिला भी आगे बढ़ रहा है। फ्रांस की द सॉल्ट कंपनी से 36 राफेल विमानों का सौदा तय हुआ है। जबकि इस सौदे से पहले 17 साल तक केंद्र की कोई भी सरकार लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा ही नहीं कर पाई थी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में फ्रांस यात्रा के दौरान फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट से जो राफेल जंगी जहाजों का सौदा किया है, वह अर्सें से अधर में लटका था। इस सौदे को अंजाम

तक पहुंचाने की पहल वायु सैनिकों को संजीवनी देकर उनका आत्मबल मजबूत करने का काम करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद और नरेंद्र मोदी से सीधे हुई बातचीत के बाद सौदे को अंतिम रूप दिया गया था। इस लिहाज से इस सौदे के दो फायदे देखने में आ रहे हैं। एक तो ये युद्धक विमान जल्दी से जल्दी हमारे वायुसेना के जहाजी बेड़े में शामिल होना शुरू हो गए, दूसरे इस खरीद में कहीं भी दलाली की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सौदे को दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने सीधे संवाद के जरिए अंतिम रूप दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री एके एंटनी की साख ईमानदार जरूर थी, लेकिन ऐसी ईमानदारी का क्या मतलब, जो जरूरी रक्षा हथियारों को खरीदने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए? जबकि ईमानदारी तो व्यक्ति को साहसी बनाने का काम करती है। हालांकि यह सही है कि जंगी जहाजों का जो सौदा हुआ है वह संप्रग सरकार द्वारा चलाई गई बातचीत की ही अंतिम परिणति है। बहरहाल मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान सौदे में जो भी अड़चनें थीं, उन्हें एक झटके में दूर किया। चीन से जो युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, उसने राफेल खरीद की प्रासंगिकता को उसी तरह रेखांकित कर दिया है, जैसा राजीव गांधी के कार्यकाल में खरीदी गई बोफोर्स तोपों ने कारगिल युद्ध के समय किया था। तब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह ने कारगिल की जीत का श्रेय बोफोर्स तोप को दिया था।

भारत को प्रदाय किए जाने वाले सभी विमान पुराने हैं। इन विमानों को पहले से ही फ्रांस की वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, लेकिन विडंबना है कि ज्यादातर लड़ाकू विमान निर्माता देश पुराने विमान ही जरूरतमंद देशों को बेचते हैं। हालांकि 1978 में जब जागुआर विमानों का बेड़ा ब्रिटेन से खरीदा गया था, तब ब्रिटिश ने हमें वही जंगी जहाज बेचे थे, जिनका प्रयोग ब्रिटिश वायुसेना पहले से ही कर रही थी। इस लिहाज से जब तक हम विमान निर्माण के क्षेत्र में स्वावलंबी नहीं होंगे, लाचारी के समझौतों की मजबूरी झेलनी ही होगी। इस सौदे की एक अच्छी खूबी यह है कि सौदे की आधी धनराशि भारत में फ्रांसीसी कंपनी को निवेश

दरअसल राफेल अनेक खूबियों से भरा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक मिनट में 60,000 किमी की ऊंचाई पर न केवल पहुंच जाता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियारों से हमला भी करने में सक्षम होता है। मिसाइलों से लैस ऐसे विमान फिलहाल चीन और पाकिस्तान के पास भी नहीं हैं। राफेल में हवा से हवा में मार करने वाली तीन तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती हैं।



करना अनिवार्य है। इस सौदे में राहुल गांधी के सदेह का प्रमुख आधार इस खरीद की सुरक्षा मामलों की समिति से अनुमति नहीं लेना है। दूसरे गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर देश हित से समझौता करने का आरोप लगाया था। उनका कहना था कि यूपीए सरकार के दौरान इसी सौदे में विमान निर्माण की तकनीक हस्तांतरण करने की बाध्यकारी शर्त रखी गई थी, जो इस सरकार ने विलोपित कर दी। हालांकि राज्यसभा में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक लिखित जबाब में स्पष्ट कर दिया था कि इस सौदे को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुए अंतर-सरकारी अनुबंध के दसवें अनुच्छेद के तहत इस सौदे में सूचनाओं और वस्तुओं के आदान-प्रदान का मामला 2008 में दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते के हिसाब से ही है।

राहुल गांधी ने तो इस सौदे को बेमतलब और भ्रष्टाचार से ग्रस्त बताते हुए इतने झूठ बोले कि जब उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के सामने अवमानना झेलने की नौबत आई तो उन्होंने न्यायालय से माफी मांगने में भी कोई लज्जा अनुभव नहीं की। इस नाते राहुल गांधी के साथ-साथ उन

लोगों को भी शर्म से सिर झुकाने पड़े थे, जो बिना किसी तथ्य और साक्ष्य के सरकार पर मनगढ़ंत आरोप लगा रहे थे। जबकि राष्ट्र के प्रति सजग और जिम्मेदार नेता को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संयम और मर्यादा का पालन करना चाहिए। सीमा पर चीन से चल रहे विवाद पर भी राहुल बेवजह प्रलाप करने में लगे हैं। इन सब तोहमतों के बावजूद ये विमान खरीदना इसलिए जरूरी था, क्योंकि हमारे लड़ाकू बेड़े में शामिल ज्यादातर विमान पुराने होने के कारण जर्जर हालत में हैं। अनेक विमानों की उड़ान अवधि समाप्त होने को है और पिछले 19 साल से कोई नया विमान नहीं खरीदा गया है। इन कारणों के चलते आए दिन जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इन दुर्घटनाओं में वायु सैनिकों के बिना लड़े ही शहीद होने का सिलसिला बना हुआ है। खैर, अब राफेल की आमद ने लड़ाकू विमानों की कमी को तो पूरा करने का सिलसिला शुरू कर ही दिया है, सेना का आत्मबल बढ़ाने का काम भी किया है। ●

लीक से हटकर काम करने वाले जनप्रिय नेता



नरेन्द्र मोदी का जन्म तत्कालीन बॉम्बे राज्य के महेसाना जिला स्थित वडनगर ग्राम में हीराबेन मोदी और दामोदरदास मूलचन्द मोदी के एक मध्यम-वर्गीय शाकाहारी परिवार में 17 सितंबर 1950 को हुआ। भारत-पाकिस्तान के बीच द्वितीय युद्ध के दौरान किशोरावस्था में उन्होंने स्वेच्छा से रेलवे स्टेशनों पर सफर कर रहे सैनिकों की सेवा की। युवावस्था में वह छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी नवनिर्माण आन्दोलन में हिस्सा लिया। एक पूर्णकालिक आयोजक के रूप में कार्य करने के पश्चात् उन्हें भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत किया गया। किशोरावस्था में अपने भाई के साथ एक चाय की दुकान चला चुके मोदी ने अपनी स्कूली शिक्षा वडनगर में पूरी की। उन्होंने आरएसएस के प्रचारक रहते हुए 1980 में गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर परीक्षा दी और मास्टर डिग्री प्राप्त की।

अपने माता-पिता की कुल छः संतानों में तीसरे पुत्र नरेन्द्र ने बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता का हाथ बंटया। वडनगर के ही एक स्कूल मास्टर के अनुसार नरेन्द्र हालांकि एक औसत दर्जे का छात्र था, लेकिन वाद-विवाद और नाटक प्रतियोगिताओं में उसकी बेहद रुचि थी। इसके अलावा उसकी रुचि राजनीतिक विषयों पर नयी-नयी परियोजनाएं प्रारम्भ करने की भी थी।

13 वर्ष की आयु में नरेन्द्र की सगाई जसोदा बेन चमनलाल के साथ कर दी गई और जब उनका विवाह हुआ, वह मात्र 17 वर्ष के थे। उनकी शादी जरूर हुई परंतु वे दोनों एक साथ कभी नहीं रहे। शादी के कुछ बरसों बाद नरेन्द्र मोदी ने घर त्याग दिया।

राजनीतिक जीवन

नरेन्द्र जब विश्वविद्यालय के छात्र थे तभी से वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में नियमित जाने लगे थे। इस प्रकार उनका जीवन संघ के एक निष्ठावान प्रचारक के रूप में प्रारम्भ हुआ। उन्होंने शुरुआती जीवन से ही राजनीतिक सक्रियता दिखाई और भारतीय जनता पार्टी का जनाधार मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई। गुजरात में शंकरसिंह वाघेला का जनाधार मजबूत बनाने में नरेन्द्र मोदी की ही रणनीति थी।

अप्रैल 1990 में जब केन्द्र में मिलीजुली सरकारों का दौर शुरू हुआ, मोदी की मेहनत रंग लाई, जब गुजरात में 1995 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने बलबूते दो तिहाई बहुमत प्राप्त कर सरकार बना ली। इसी दौरान दो राष्ट्रीय घटनाएं और इस देश में घटीं। पहली घटना थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की रथयात्रा जिसमें आडवाणी के प्रमुख सारथी की भूमिका में नरेन्द्र का मुख्य सहयोग रहा। इसी प्रकार कन्याकुमारी से लेकर सुदूर उत्तर में स्थित काश्मीर तक की मुरली मनोहर जोशी की दूसरी रथयात्रा भी नरेन्द्र मोदी की ही देखरेख में आयोजित हुई। इसके बाद शंकरसिंह वाघेला ने पार्टी से त्यागपत्र दे दिया, जिसके परिणामस्वरूप केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया गया और नरेन्द्र मोदी को दिल्ली बुला कर भाजपा में संगठन की दृष्टि से केन्द्रीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया।

1995 में राष्ट्रीय मंत्री के नाते उन्हें 5 प्रमुख राज्यों में पार्टी संगठन का काम दिया गया जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। 1998 में उन्हें पदोन्नत करके राष्ट्रीय महामंत्री (संगठन) का उत्तरदायित्व दिया गया। इस पद पर वह अक्टूबर 2001 तक काम करते रहे।



भारतीय जनता पार्टी ने अक्टूबर 2001 में केशुभाई पटेल को हटाकर गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान नरेन्द्र मोदी को सौंप दी।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में

नरेन्द्र मोदी अपनी विशिष्ट जीवन शैली के लिए समूचे राजनीतिक हलकों में जाने जाते हैं। उनके व्यक्तिगत स्टाफ में केवल तीन ही लोग रहते हैं, कोई भारी-भरकम अमला नहीं होता। लेकिन कर्मयोगी की तरह जीवन जीने वाले मोदी के स्वभाव से सभी परिचित हैं इस नाते उन्हें अपने कामकाज को अमली जामा पहनाने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती।

वे एक लोकप्रिय वक्ता हैं, जिन्हें सुनने के लिये बहुत भारी संख्या में श्रोता आज भी पहुंचते हैं। कुर्ता-पायजामा व सदरी के अतिरिक्त वे कभी-कभार सूट भी पहन लेते हैं। अपनी मातृभाषा गुजराती के अतिरिक्त वह राष्ट्रभाषा हिन्दी में ही बोलते हैं।

मुख्यमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारम्भ कीं। मोदी ने आदिवासी व वनवासी क्षेत्र के विकास हेतु गुजरात राज्य में व एक अन्य 10 सूत्री कार्यक्रम भी चला रखा है।

आतंकवाद पर मोदी के विचार

आतंकवाद युद्ध से भी बदतर है। एक आतंकवादी के कोई नियम नहीं होते। एक आतंकवादी तय करता है कि कब, कैसे, कहाँ और किसको मारना है। भारत ने युद्धों की तुलना में आतंकी हमलों में अधिक लोगों को खोया है।

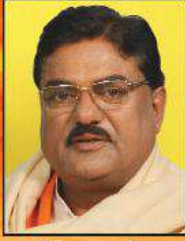
पहली बार लोकसभा चुनाव 2014 और मोदी एक सांसद प्रत्याशी के रूप में उन्होंने देश की दो लोकसभा सीटों वाराणसी

तथा वडोदरा से चुनाव लड़ा और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुए। न्यूज एजेंसीज व पत्रिकाओं द्वारा किए गए तीन प्रमुख सर्वेक्षणों ने नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बताया था। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी क्रांति ने दूसरे दलों को बहुत पीछे छोड़ दिया। नरेन्द्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त कर अभूतपूर्व जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की है। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना, और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया है। मोदी लहर कहो या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। मोदी की वाहवाही चारों ओर थी। नरेन्द्र मोदी जी के पिछले पांच सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्नत भारत के लिए लोगों को मोदी जी से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास = विजयी भारत'। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल बोला।

अपनी मां के प्रति विशेष स्नेह और आदर के लिए भी वह जाने जाते हैं। उनका स्वच्छता अभियान देश भर में पसंद किया गया। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता खासी लोकप्रिय है। उनकी जीवनशैली अक्सर चर्चा में रहती है। कभी महंगे कोट, कुर्ते, घड़ी के लिए तो कभी विदेशों में लोक संगीत का मजा लेने के लिए। कभी अपने लिए बने मंदिर के लिए तो कभी प्रशंसकों के साथ लिए सेल्फी के लिए। प्रधानमंत्री मोदी हर काम लोक से हटकर करते हैं इसीलिए जनता के बीच उनकी छबि एक कुशल नेता की है। ●



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

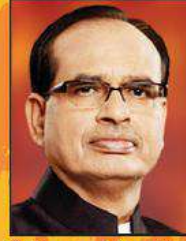
मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री जुबानसिंह बघेल : श्रीमती लक्ष्मी भँवर
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
थांदला, जिला झाबुआ (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्रीमती रंजना पाटीदार : श्री भगवानसिंह परिहार
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

किसान भाइयों से अपील

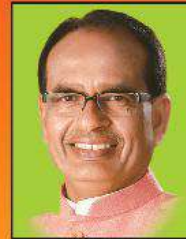
किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौर एवं समय पर भुगतान पाएँ।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री मिलिंद ढोके : श्रीमती रचना टिकेकर
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
बड़वाह, जिला खंडवा (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री अनिल गोरे : श्री अनिल कुमार उजले
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
करही, जिला खरगोन (म.प्र.)



आर्थिक विकास में विपणन संस्थाओं का योगदान

धर्मसिंह वर्मा » राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सहकार भारती

सहकारी आंदोलन के विकास में विपणन की अवधारणा उत्पादकर्ता एवं उपभोक्ता के बीच में समन्वय स्थापित कर उपभोक्ता को उसकी आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराना एवं उत्पादकों को लागत के अनुरूप मूल्य उपलब्ध कराना रहा है। इसी से विपणन सहकारी आंदोलन की अवधारणा हुई है। उपभोक्ताओं के मन में उत्पादों के प्रति सजगता का भाव पैदा करना तथा बाजार की प्रतिस्पर्धा में तुलनात्मक रूप से कीमतों को स्थिर रखने तथा उपलब्धता बनाए रखने में सहकारी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारिता आंदोलन में विपणन सहकारी संस्थाओं की भूमिका इस मामले में भी महत्वपूर्ण रही है कि सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा अपने सदस्यों के कृषि उत्पाद को उचित मूल्य पर क्रय करते हुए सही कीमत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है।

कृषि प्रसंस्करणों एवं प्रक्रिया इकाइयों के माध्यम से कच्चे माल को

उपभोक्ताओं के अनुरूप आवश्यकतानुसार तैयार कर उपलब्ध कराने की प्राथमिकता रही है। ग्रामीण अंचलों एवं दूरदराज के क्षेत्र में वस्तुओं की उपलब्धता बनाए रखने में विपणन सहकारी संस्थाओं की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सहकारी आंदोलन द्वारा कृषि उपज की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर कृषकों को उनकी उपज का सही भाव दिलाना एक ज्वलंत उदाहरण है। दूरदराज के इलाकों में उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछले दिनों समर्थन मूल्य के अंतर्गत दूरदराज के क्षेत्रों में चना, सरसों गेहूँ आदि जिसों की खरीदी की जाकर कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने में

सहकारी संस्थाएँ सदैव अग्रणी रही है। चालू वर्ष में ही सहकारिता के माध्यम से 5 लाख टन से अधिक गेहूँ का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाकर कृषकों को उचित मूल्य दिलाया गया है। यद्यपि वर्तमान में सहकारी संस्थाओं के समक्ष आर्थिक संकट है। उनकी व्यावसायिक निरंतरता का अभाव है। इसको ध्यान में रखकर कृषि विपणन के नए क्षेत्र खोजने की आवश्यकता है। कृषि उपज के प्रसंस्करण के विकास से भी इस समस्या के समाधान को ढूँढा जा सकता है। कृषि

सार्व आंदोलन वर्तमान में एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। यदि इसका विपणन से समन्वय कर दिया जाए एवं ऋणों की वसूली कृषि उत्पादकों के माध्यम से की जाएँ तो इसका लाभ सहकारी सार्व संस्थाओं के साथ विपणन सहकारी संस्थाओं को भी हो सकता है।

विपणन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम विपणन का साख के समन्वय से भी किया जा सकता है। साख आंदोलन वर्तमान में एक निरंतर प्रक्रिया बन चुका है। यदि इसका विपणन से समन्वय कर दिया जाए एवं ऋणों की वसूली कृषि उत्पादनों के माध्यम से की जाएँ तो इसका लाभ सहकारी साख संस्थाओं के साथ विपणन सहकारी संस्थाओं को भी हो सकता है। जिससे कृषि उत्पादकों को भी उचित मूल्य दिलाने में सहकारी विपणन संस्थाएँ अपनी महत्वपूर्ण सार्थक भूमिका निभा सकती है तथा आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। सहकारिता से जुड़े हुए सभी क्षेत्र के लोगों को इस विषय पर विचार कर अपना ठोस विचार रखना चाहिए ताकि विपणन सहकारी संस्थाएँ आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। अभी भी विपणन संस्थाओं के माध्यम से कृषकों को कृषि ऋण के रूप में रासायनिक खाद, बीज, कृषि उपकरण उचित मूल्य पर उपलब्ध कराकर बाजार को प्रतिस्पर्धा में निजी क्षेत्र के शोषण से राहत दिलाने की कार्यवाही की जा रही है। निजी क्षेत्र की लाभप्रदता पर अंकुश लगाते हुए बाजार मूल्य को स्थिर रखने तथा सामग्री की उपलब्धता निरंतर बनाए रखने में सहकारी संस्थाएँ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर आर्थिक विकास में योगदान दे रही है। पिछले 2 वर्षों से जहाँ सारे देश में रासायनिक खाद की उपलब्धता को लेकर संकट रहा है वहीं प्रदेश में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से रासायनिक खाद की भरपूर उपलब्धता बनाकर कृषकों के मध्य सहकारी संस्थाओं एवं सहकारी आंदोलन के प्रति आज भी अटूट विश्वास है। यह विश्वास समाज के आर्थिक रूप से पिछले वर्ग में भी है कि संकट के समय सहकारी संस्थाएँ ही उनकी आवश्यकता की पूर्ति का सशक्त माध्यम बनकर उभरती है। सहकारी संस्थाओं से प्राप्त होने वाली सामग्री की किस्म एवं गुणवत्ता को लेकर वे पूरी तरह आश्वस्त हैं और इस तरह समाज के आर्थिक विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे समाज के इस विश्वास को पूरी मेहनत एवं लागत से कायम रखते हुए हैं।

वर्तमान समय में जहाँ एक ओर आर्थिक मंदी का वातावरण है वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र व्यापार व्यवसाय के उन क्षेत्रों में भी प्रवेश कर रहा है जो किसी समय में छोटे व्यापारियों के कार्य क्षेत्र हुआ करते थे। ऐसी परिस्थिति में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि वे जहाँ एक ओर उपभोक्ताओं को सही मूल्य पर उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ खासतौर पर कृषि संसाधन से संबंधित सामग्री एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से दिन प्रतिदिन की आवश्यकता की वस्तुएँ उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करें। इस परिस्थिति में सहकारी संस्थाओं की भूमिका एक समन्वयकर्ता की है वे इस वातावरण में उपभोक्ता एवं कृषि उत्पादक का सहारा देकर उनका आर्थिक आधार मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। ●

सदस्यता फॉर्म

राष्ट्रीय मासिक पत्रिका

हरियाली के रास्ते

कृषि, सहकारिता एवं स्थानीय प्रशासन पर केन्द्रित
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़-उत्तरप्रदेश का प्रवक्ता

नियमित अंकों सहित विशेषांक भी

सदस्यता शुल्क

480/-

वार्षिक

850/-

द्विवार्षिक

9000/-

आजीवन

नाम :

पिता :

पता :

.....

.....

पिनकोड :

फोन :

मोबाइल :

ई-मेल :

सम्पर्क करें

हरियाली के रास्ते

306/ए-ब्लॉक, शहनाई-॥ रेसीडेसी, कनाइया रोड, इंदौर
मो. 8989179472, 9752558186

सदस्यता शुल्क जमा करने हेतु बैंक अकाउंट विवरण

» खाता नाम : हरियाली के रास्ते

» बैंक : भारतीय स्टेट बैंक » शाखा : गोयल नगर

» खाता संख्या : 31450697620 » SBIN0030412

» PAN Card No. AHGPT7845K

अनुरोध : सदस्यों से अनुरोध है कि सदस्यता प्राप्त करने के बाद रसीद अवश्य प्राप्त करें।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

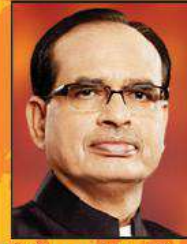
किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

श्री पी.एल. देवड़ा
(भारसाधक अधिकारी)

श्री कमलेश मीणा
(प्रभारी सचिव)

**सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
जावद, जिला नीमच (म.प्र.)**



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

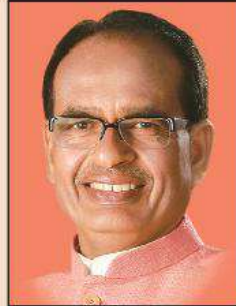
सुश्री नेहा शिवहरे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री श्रीराम साधा
(प्रभारी सचिव)

**सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
कसरवावद, जिला खरगोन (म.प्र.)**

**किसान भाइयों
से अपील**

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)



**74वें स्वाधीनता दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएँ**

श्री एच.एस. चौधरी
(भारसाधक अधिकारी)

श्री संजीव श्रीवास्तव
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति हरदा, जिला हरदा (म.प्र.)



आलू की उन्नत खेती

आलू की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका को माना जाता है, लेकिन भारतवर्ष में आलू प्रथम बार सत्रहवीं शताब्दी में यूरोप से आया। चावल, गेहूँ, गन्ना के बाद क्षेत्रफल में आलू का चौथा स्थान है। आलू एक ऐसी फसल है जिससे प्रति इकाई क्षेत्रफल में अन्य फसलों (गेहूँ, धान एवं मूँगफली) की अपेक्षा अधिक उत्पादन मिलता है तथा प्रति हेक्टर आय भी अधिक मिलती है। आलू में मुख्य रूप से 80-82 प्रतिशत पानी होता है और 14 प्रतिशत स्टार्च, 2 प्रतिशत चीनी, 2 प्रतिशत प्रोटीन तथा 1 प्रतिशत खनिज लवण होते हैं। वसा 0.1 प्रतिशत तथा थोड़ी मात्रा में विटामिन्स भी होते हैं।

जलवायु

आलू समशीतोष्ण जलवायु की फसल है। इसकी खेती उपोष्णीय जलवायु की दशाओं में रबी के मौसम में की जाती है। सामान्य रूप से अच्छी खेती के लिए फसल अवधि के दौरान दिन का तापमान 25-30 डिग्री सेल्सियस तथा रात्रि का तापमान 4-15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। फसल में कन्द बनते समय लगभग 18-20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम सर्वोत्तम होता है। कन्द बनने के पहले कुछ अधिक तापक्रम रहने पर फसल की

वानस्पतिक वृद्धि अच्छी होती है, लेकिन कन्द बनने के समय अधिक तापक्रम होने पर कन्द बनना रुक जाता है। लगभग 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापक्रम होने पर आलू की फसल में कन्द बनना बिलकुल बन्द हो जाता है।

भूमि एवं भूमि प्रबन्ध

आलू की फसल विभिन्न प्रकार की भूमि, जिसका पी.एच. मान 6 से 8 के मध्य हो, उगाई जा सकती है, लेकिन बलुई दोमट तथा दोमट उचित जल निकास की भूमि उपयुक्त होती है। 3-4 जुताई डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से करें। प्रत्येक जुताई के बाद पाटा लगाने से ढेले टूट जाते हैं तथा नमी सुरक्षित रहती है। वर्तमान में रोटावेटर से भी खेत की तैयारी शीघ्र व अच्छी हो जाती है। आलू की अच्छी फसल के लिए बोने से पहले पलेवा करना चाहिए।

कार्बनिक खाद

यदि हरी खाद का प्रयोग न किया हो तो 15-30 टन प्रति है. सड़ी गोबर की खाद प्रयोग करने से जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, जो कन्दों की पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है।

खाद तथा उर्वरक प्रबन्ध

सामान्य तौर पर 180 किग्रा नत्रजन, 80 किग्रा फास्फोरस तथा 100 किग्रा पोटैश की संस्तुति की जाती है। मृदा विश्लेषण के आधार पर यह मात्रा घट-बढ़ सकती है। 180:80:100 किग्रा नत्रजन, फास्फोरस व पोटैश/है. की पूर्ति हेतु उर्वरकों के विभिन्न विकल्प हो सकते हैं। मिट्टी परीक्षण की संस्तुति के अनुसार अथवा 25 किग्रा जिंक सल्फेट एवं 50 किग्रा फेरस सल्फेट प्रति है. की दर से बुआई से पहले कम वाले क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहिए तथा आवश्यक जिंक सल्फेट का छिड़काव भी किया जा सकता है।

बीज

बोने के लिए 30-55 मिमी. व्यास का अंकुरित (चिटिंग) आलू बीज का प्रयोग करना चाहिए। एक हेक्टेयर के लिए 30-35 कुन्तल बीज की आवश्यकता पड़ती है। प्रजातियों का चयन क्षेत्रीय आवश्यकताओं एवं बुआई के समय यथा अगेती फसल, मुख्य फसल अथवा पिछेती फसलों के अनुसार किया जाना उचित होता है। जलवायु स्थितियों के अनुसार संस्तुति प्रजातियों का विवरण निम्नवत है :-

क्र.	प्रजाति का नाम	परिपक्वता अवधि (दिन)	5 सिन्दूरी	90-110
			6 सतलुज जे-5857	90-110
			7 लालिमा	90-110
1	चन्द्रमुखी	80-90	8 अरुण	90-110
2	पुखराज	60-75	9 सदाबहार	90-110
3	सूर्या	60-75	10 पुखराज	90-110
4	ख्याति	60-75		
			अगेती फसल	
5	अलंकार	65-70	1 सतलुज जे.-5857	110-120
6	बहार 3792ई.	90-110	2 बादशाह	110-120
7	अशोका पी.376जे.	60-75	3 आनन्द	110-120
8	जे.एफ.-5106	75-80		
			प्रसंस्करण योग्य प्रजातियाँ	
			1 सूर्या	100-120
1	नवताल जी 2524	90-110	2 चिप्सोना-1	100-120
2	बहार 3792 ई.	90-110	3 चिप्सोना-3	100-120
3	आनन्द	90-110	4 चिप्सोना-4	100-120
4	बादशाह	90-110	5 फ्राईसोना	100-120

बुआई का समय

आलू तापक्रम के प्रति सचेतन प्रकृति वाला होता है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिन का तापमान आलू की वानस्पतिक वृद्धि और 15-20 डिग्री सेंटीग्रेड आलू कन्दों की बढ़वार के लिए

उपयुक्त होता है। सामान्यतः अगेती फसल की बुआई मध्य सितम्बर से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक, मुख्य फसल की बुआई मध्य अक्टूबर के बाद हो जानी चाहिए।

बीज की बुआई

यदि भूमि में पर्याप्त नमी न हो तो, पलेवा करना आवश्यक होता है। बीज आकार के आलू कन्दों को कूड़ों में बोया जाता है तथा मिट्टी से ढककर हल्की मेंड़ें बना दी जाती है। आलू की बुआई पोटेटो प्लान्टर से किये जाने से समय, श्रम व धन की बचत की जा सकती है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए निराई-गुड़ाई आवश्यक है।

सिंचाई प्रबन्ध

पौधों की उचित वृद्धि एवं विकास तथा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 7-10 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आलू की बुआई से पूर्व पलेवा नहीं किया गया है तो बुआई के 2-3 दिन के अन्दर हल्की सिंचाई करना अनिवार्य है। भूमि में नमी 15-30 प्रतिशत तक कम हो जाने पर सिंचाई करनी चाहिए। अच्छी फसल के लिए अंकुरण से पूर्व बलुई दोमट व दोमट मृदाओं में बुआई के 8-10 दिन बाद तथा भारी मृदाओं में 10-12 दिन बाद पहली सिंचाई करें। अगर तापमान के अत्यधिक कम होने और पाला पड़ने की संभावना हो तो फसल में सिंचाई अवश्य करें। आधुनिक सिंचाई पद्धति जैसे स्पिंकलर और ड्रिप से पानी के उपयोग की क्षमता में वृद्धि होती है। कूँड़ों में सिंचाई की अपेक्षा स्पिंकलर प्रणाली से 40 प्रतिशत तथा ड्रिप प्रणाली से 50 प्रतिशत पानी की बचत होती है और पैदावार में भी 10-20 प्रतिशत वृद्धि होती है।

कीट एवं व्याधि रोकथाम

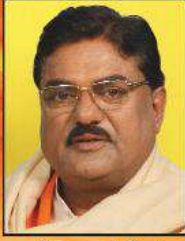
आलू फसल को बहुत सी बीमारियों तथा कीट हानि पहुँचाते हैं। यहाँ मुख्य-मुख्य बीमारियों एवं कीटों का विवरण दिया जा रहा है, जो आलू की उपज तथा कन्दों की गुणवत्ता को अधिक हानि पहुँचाते हैं

पिछेता सुलझा (लेट ब्लाइट) : यह आलू में फफूंद से लगने वाली एक भयानक बीमारी है। इस बीमारी का प्रकोप आलू की पत्ती, तने तथा कन्दों, सभी भागों पर होता है। जैसे ही मौसम बदली युक्त हो और तापमिम 10-20 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तथा आपेक्षित आर्द्रता 80 प्रतिशत हो, तो इस बीमारी की संभावना बढ़ जाती है। अतः तुरन्त ही सिंचाई बन्द कर दें। यदि आवश्यक हो तो बहुत हल्की सिंचाई ही करें तथा लक्षण दिखाई देने से पूर्व ही बीमारी की रोकथाम की लिए 0.20 प्रतिशत मैकोजेब दवा के घोल का छिड़काव 8-10 दिन के अन्तराल पर करना चाहिए।

अगेता झुलसा : अगेता झुलसा बीमारी से पत्तियों और कन्द दोनों प्रभावित होते हैं। आरम्भ में इस बीमारी के लक्षण निचली



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

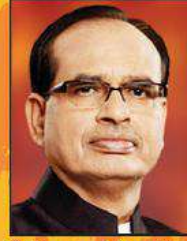
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री आर.के. यादव
(भारसाधक अधिकारी)

श्री अशोक जैन
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
भानपुरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावदी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावदी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

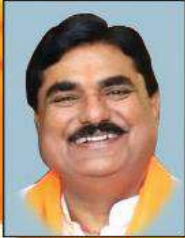
श्री संजय मालवीय
(भारसाधक अधिकारी)

श्री जगदीश नारायण ओझा
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ठेर पर उपरिधत रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

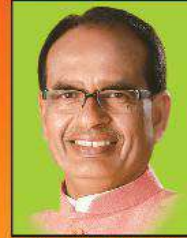
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

सुश्री शिराली जैन
(भारसाधक अधिकारी)

श्री एम.एल. वारसे
(प्रभारी सचिव)

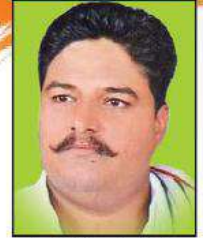
सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

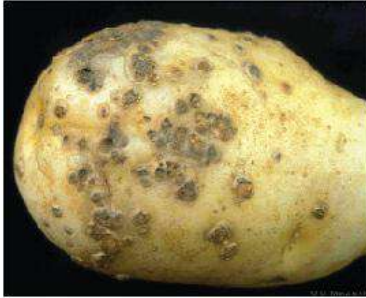
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री राहुल धोटे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री किशोर नरगावे
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
जावरा, जिला रतलाम (म.प्र.)

तथा पुरानी पत्तियों पर छोटे गोल से अण्डाकार भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इस बीमारी से प्रभावित कन्दों पर दबे हुए धब्बे तथा नीचे का गूदा भूरा एवं शुष्क हो जाता है। अतः रोग अवरोधी किस्मों का चयन किया जाये। इस बीमारी की रोकथाम के लिए 0.3 प्रतिशत कॉपर आक्सीक्लोराइड फफूँदनाशक के घोल का प्रयोग किया जाये।



आलू की पत्ती मुड़ने वाला रोग (पोटेटो लीफ रोल)

: यह एक वायरल बीमारी है जो (पी.एल.आर.वी.) वायरस के द्वारा फैलती है। इस बीमारी की

रोकथाम के लिए रोग रहित बीज बोना चाहिए तथा इस वायरस के वाहक एफिड की रोकथाम दैहिक कीटनाशक यथा फास्फोमिडान का 0.04 प्रतिशत घोल मिथाइलऑक्सीडिमीटान अथवा डाइमिथोएट का 0.1 प्रतिशत घोल बनाकर 1-2 छिड़काव दिसम्बर, जनवरी में करना चाहिए।

दीमक : दीमक का प्रकोप ज्यादातर अगेती फसल में होता है। इससे प्रभावित आलू के पौधों की पत्तियां नीचे की ओर मुड़ जाती है। अधिक प्रकोप की अवस्था में पत्तियों स्मंजीमतल हो जाती हैं तथा पत्तियों की निचली सतह पर तांबा के रंग जैसे धब्बे दिखायी पड़ते हैं। दीमक की रोकथाम के लिए डाइकोफाल 18.5 ई.सी. या क्यूनालफॉस 25 ई.सी. की 2 लीटर मात्रा प्रति है 0 की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें तथा 7-10 दिन के अन्तराल पर पुनः दोहराये।

आलू की खुदाई

अगेती फसल से अच्छा मूल्य प्राप्त करने के लिए बुआई के 60-70 दिनों के उपरान्त कच्ची फसल की अवस्था में आलू की खुदाई की जा सकती है। फसल पकने पर आलू खुदाई का उत्तम समय मध्य फरवरी से मार्च द्वितीय सप्ताह तक है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आने से पूर्व ही खुदाई पूर्ण कर लेना चाहिए।

आलू का भण्डारण

आलू की सुषुप्ता अवधि भण्डारण को निर्धारित करती है। भिन्न-भिन्न प्रजातियों के आलू की सुषुप्ता अवधि भिन्न-भिन्न होती है, जो आलू खुदाई के बाद 6-10 सप्ताह तक होती है। यदि आलू को बाजार में शीघ्र भेजना है तो शीतगृह में भण्डारित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कच्चे हवादार मकानों, छायादार स्थानों में आलू को स्टोर किया जा सकता है। ●

सितंबर माह के कृषि कार्य

■ **धान फसल :** धान का भंडारण करते समय आर्द्रता स्तर 10-12 प्रतिशत से कम होनी चाहिए। धान के भण्डारण कक्ष को तथा जूट के बोरो को विसंक्रमित करके ही भंडारण करें। धान भण्डारण के कीड़ों के नियंत्रण के लिए फोस्टोक्सीन दवा का प्रयोग करें। कीड़ों से बचाव के लिए स्टॉक को तरपोलिन से ढक दें।

■ **सब्जियाँ :** गोभी की पूसा सुक्ति, पूसा पौषजा प्रजातियों की नर्सरी तैयार करें। बन्द गोभी की किस्म गोल्डन एकर, पूसा कैबेज हार्डबिड 1 की नर्सरी तैयार करें। पालक की पूसा भारती किस्म की बुआई आरम्भ कर सकते हैं। बैंगन की पौध पर 3 ग्राम मैकोजेब और 1 ग्राम कार्बेन्डाजिम को एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। अगेती गाजर की पूसा वृष्टि किस्म की बुवाई करें। गाजर को पर्ण अंगमारी रोग से बचाव के लिए धीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बोएँ। गाजर को स्क्लेरोटिनिया विगलन से बचाव के लिए 15 ग्राम प्रति तीन लीटर पानी में घोलकर मृदा को सींचें।

■ **फल फसलें :** वयस्क आम के पौधों में बची हुई उर्वरक की मात्रा (500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम फॉस्फोरस व 500 ग्राम पोटाश) को मानसून की बारिश के पश्चात डालें। नींबू वर्गीय फलों में यदि डाइबैक, स्कैब तथा सूटी मोल्ड बीमारी का प्रकोप हो तो 3 ग्राम कापर ओक्सीक्लोराइड दवा एक लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। नींबू वर्गीय फलों में कैंकर बीमारी की रोकथाम के लिए 5 ग्रा.

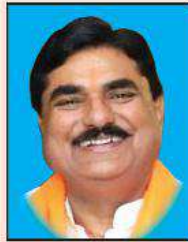


स्ट्रेप्टोसाइक्लीन तथा 10 ग्रा. कॉपर सल्फेट दवा को 100 लीटर पानी में घोलकर या 3 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को प्रति 1 लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों में डालें।

■ **सरसों :** इस माह में सरसों की अगेती किस्मों जैसे कि पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 28, पूसा सरसों 27 व पूसा तारक की बुवाई करें। सरसों में सफेद रतुआ के बचाव के लिए मेटालैक्सल (एप्रॉन 35 एसडी) 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज दर से या बैविस्टिन 2 ग्रा./किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। सरसों में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई से पहले 2.2 लीटर/ हैक्टेयर की दर से फ्लूक्लोरोलिन का 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि बुवाई से पहले खरपतवार नियंत्रण नहीं किया गया है तो 3.3 लीटर पेंडीमिथालिन (30 ई.सी.) को 600 से 800 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 1-2 दिन बाद छिड़काव करें।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

सुश्री अंशु चावला
(भारसाधक अधिकारी)

श्री भीकला बड़ोले
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सैंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री वीरसिंह चौहान
(भारसाधक अधिकारी)

श्री एच.एस. जमरा
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
अंजड़, जिला बड़वानी (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73^{वीं} वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री सुमेरसिंह मुजाल्दा
(भारसाधक अधिकारी)

श्री ओ.पी. खेड़े
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
खेतिया, जिला बड़वानी (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74^{वें} स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

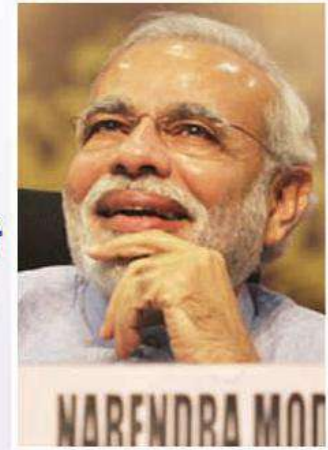
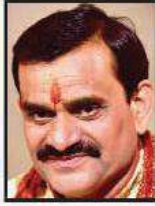


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री एस.आर. यादव
(भारसाधक अधिकारी)

श्री देवीसिंह थनवार
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
बलवाड़ी, जिला बड़वानी (म.प्र.)



**किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर रोड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण**



**भारत के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की
हार्दिक बधाइयाँ**

**स्वतंत्रता
दिवस की
73^{वाँ} वर्षगांठ पर
हार्दिक
शुभकामनाएँ**



श्री बी.एस. शुक्ला
(प्रशासक एवं संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री बी.एस. परते
(अग्रयुक्त सहकारिता)



श्री एम.ए. कमाली
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री आर.के. दुबे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)



श्री राजीव रिछरिया
(वित्त प्रबंधक)

सौजन्य से : श्री राजेन्द्र शर्मा (शा.प्र. हरदा) । श्री चतुर्भुज भाटी/श्री विष्णुप्रसाद आगुलें (पर्य. हरदा) । श्री के.सी. सारन (मोडल अधिकारी)

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
अबगाँवकलां, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
खेड़ा, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
नीमगाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
अबगाँवखुर्द, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
मांगरूल, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
पलासनेर, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
धनगाँव, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
रूपी पटेरिया, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
कडोला, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
भुवनेश्वरी, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
बालागाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
मसनगाँव, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
हंडिया, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
महाल, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
पीपलघटा, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
नादरा, जि.हरदा
श्री विष्णुप्रसाद आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
मोहनपुर, जि.हरदा
श्री विष्णुकुमार आगुलें (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह. संस्था मर्या.
सोनवलाई, जि.हरदा
श्री सी.पी. भाटी (प्रबंधक)**

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से



जल, जंगल, जमीन और वन प्राणियों के रक्षक आदिवासी समाज

प्राचीनकाल से आदिवासियों का जंगल एवं वन प्राणियों से गहरा लगाव रहा है। आदिवासी प्राचीनकाल से वन क्षेत्रों में निवास करते हुए जल, जंगल, जमीन और वन प्राणियों की रक्षा करते रहे हैं। इसे देखते हुए भारतीय संस्कृति में आदिवासियों को धरती पुत्र कहा गया है। आदिवासी बाहुल्य मध्यप्रदेश राज्य में 43 जनजाति समूह निवास करते हैं। जो मध्यप्रदेश की कुल जनसंख्या का 5वां हिस्सा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में एक करोड़ 53 लाख के करीब जनजाति वर्ग की आबादी है।

देश में स्वतंत्रता के पश्चात केन्द्र सरकार ने आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिये संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की और संविधान में उनकी समस्याओं को दूर करने के लिये अनेक प्रावधान भी किये। इसी के अनुरूप मध्यप्रदेश में आदिवासी वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाते हुए विभिन्न विकास विभागों के माध्यम से आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक उत्थान एवं अनेक विकास कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में जनजाति जनसंख्या के अनुपात में 21.09 प्रतिशत से अधिक बजट प्रावधान करके आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों के माध्यम से

योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिया जा रहा है। आदिवासी भाई-बहनों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं ऑनलाइन करने के लिये MPTAAS सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।

आदिवासी वर्ग के शैक्षणिक विकास के लिये छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। पिछले वर्ष 2019-20 में प्रदेश के करीब 25 लाख आदिवासी विद्यार्थियों को 465 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की गयी। इस वर्ष छात्रवृत्ति का लाभ 27 लाख 57 हजार आदिवासी विद्यार्थियों को दिया जा रहा है। इसके लिये राज्य सरकार ने अपने विभागीय बजट में 475 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आदिम जाति कल्याण विभाग की 34 हजार 440 शैक्षणिक संस्थाओं में 25 लाख 64 हजार विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के मकसद से आवासीय सुविधा के साथ 2629 छात्रावास आश्रम संचालित किये जा रहे हैं। इनमें डेढ़ लाख विद्यार्थियों की रहने की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में संचालित 126 विशिष्ट संस्थाओं में करीब 27 हजार 586 अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी अध्ययन प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में इस वर्ष नवीन छात्रावास और उच्चतर माध्यमिक शाला

के उन्नयन के लिये बजट में प्रावधान किया गया है। प्रदेश में वर्ष 2020-21 में अनुसूचित जनजाति के 24 सीनियर छात्रावास और 15 महाविद्यालयीन छात्रावास प्रारंभ किये जाएंगे। इस वर्ष आदिवासी बहुल क्षेत्र के 50 हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन कर संचालित किया जाएगा।

आदिवासी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिन्हें छात्रावासों में स्थान नहीं मिल पाता है। उनके लिये आवास सहायता योजना संचालित की जा रही है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन नगरों में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2 हजार रुपये, जिला मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 1250 एवं तहसील विकासखण्ड मुख्यालय पर प्रति विद्यार्थी एक हजार रुपये की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष आवास सहायता योजना में करीब 69 हजार विद्यार्थियों को 110 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गयी। इस योजना में इस वर्ष आदिवासी वर्ग के 70 हजार विद्यार्थियों को 165 करोड़ रुपये वितरित किये जाएंगे। आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी विदेशों में प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश कर अध्ययन कर सकें। इसके लिये विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है। योजना में चयनित विद्यार्थियों को दो वर्ष के लिये अधिकतम 75 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान रखा गया है। पिछले वर्ष 4 विद्यार्थियों को इस योजना में करीब 198 लाख रुपये की मदद दी गई। इस वर्ष योजना में 2 करोड़ 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी यूपीएससी की कोचिंग प्राप्त कर सकें इसके लिये नई दिल्ली में 100 विद्यार्थियों को कोचिंग उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 100 विद्यार्थियों की कोचिंग पर 5 करोड़ रुपये का विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में रहने वाले आदिवासियों की संस्कृति के संरक्षण और उनके कुल एवं ग्राम देवी-देवता के स्थानों में निर्मित देवठान के निर्माण और जीर्णोद्धार पर विशेष व्यवस्था किये जाने के लिये 8 करोड़ 40 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस राशि से इन स्थानों पर सामुदायिक भवन, सभाकक्ष, पेयजल, विद्युत व्यवस्था आदि की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी वर्ग के लिये चलाई जा रही योजनाओं का कम्प्यूटीकरण कर ऑनलाइन लाभ देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रोफाईल पंजीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 9 लाख 40 हजार आदिवासी हितग्राहियों का ऑनलाइन प्रोफाईल पंजीकरण किया गया है। पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति में डीव्हीटी द्वारा उनके आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान किये जाने की व्यवस्था की गयी है। आदिवासी वर्ग के 78 हजार 688 विद्यार्थियों को उनके बैंक खातों में 115 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की गयी है। शिक्षक प्रोफाईल पंजीकरण में अध्यापक संवर्ग के 55 हजार अध्यापकों का विभाग में ऑनलाइन सवलियन आदेश जारी किये गये है। छात्रावास योजना में विभाग के 1563 छात्रावासों में 57 हजार 274 विद्यार्थियों को करीब 75 करोड़ रुपये की राशि ऑनलाइन

भुगतान के लिये ऑनबोर्ड की गई है। आकांक्षा योजना में आदिवासी वर्ग के विद्यार्थी जेईई, नीट और क्लेट की प्रवेश परीक्षा की तैयारी प्रदेश के चार महानगरों जबलपुर भोपाल ग्वालियर इंदौर में कर सकें। इसके लिये इस वर्ष एक हजार विद्यार्थियों को कोचिंग दिये जाने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये 11 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सह्रिया, बैगा और भारिया विशेष पिछड़ी जनजातियों के संरक्षण और विकास के लिये पोषण शक्ति, सोलर स्टेट लाईट, बैगा जनजाति महिलाओं के लिये आजीविका कार्यक्रम, हॉस्टल में अतिरिक्त सुविधाएँ, पीव्हीटीजी विकासखण्ड मुख्यालयों में 10 कम्प्यूनिटी सेंटर का निर्माण और हाई सेकण्डरी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की सुविधा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये विभाग द्वारा इस वर्ष 140 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिये परिवार की महिला मुखिया के खाते में एक हजार रुपये की राशि प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा जमा कराई जा रही है। इस वर्ष इस योजना में 218 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

राज्य सरकार अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के हितों के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। प्रदेश में वर्ष 2006 से अब तक दो लाख 30 हजार वन निवासियों को व्यक्तिगत और करीब 28 हजार सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किये गये है। वन अधिकार अधिनियम में पूर्व के निरस्त दावों के निराकरण के लिये एम.पी. वन मित्र सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। अब तक तक 20 हजार 830 ग्राम पंचायत सचिव की प्रोफाईल अपडेट की जा चुकी है। 36 हजार 711 ग्राम वन अधिकार समितियों को पोर्टल में दर्ज किया जा चुका है। ग्राम वन अधिकार समितियों द्वारा 2 लाख 56 हजार 491 पूर्व के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। उपखण्ड स्तरीय समितियों द्वारा परीक्षण के पश्चात 33 हजार 707 दावों का निराकरण कर अनुशंसा के साथ जिलास्तरीय समितियों को भेजा गया है। जिलास्तरीय समितियों द्वारा 4540 दावों का निराकरण कर 2136 दावों को मान्य किया गया है।

आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य क्षेत्रों को विकसित करने के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता मद में इस वर्ष 292 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। इनमें बैतूल में 200 बिस्तर अस्पताल के लिये 5 करोड़ रुपये, बालिका छात्रावासों के लिये 7 करोड़ 78 लाख रुपये, शंकर शाह म्यूजियम की स्थापना के लिये 3 करोड़ रुपये और प्रदेश के 12 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सीट वृद्धि और उन्नयन पर करीब 25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जाएगी।

राज्य सरकार आदिवासियों के हितों के संरक्षण के लिये कृत-संकल्पित है और इसी भावना के साथ उनके निरंतर विकास के लिये लगातार कार्य कर रही है। ●



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
बीतामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
हमाल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हमाल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें। किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

श्री अभिषेक गहलोद
(भारसाधक अधिकारी)

श्री रामवीर किरार
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति खरगोन, जिला खरगोन (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)



श्री देवकीनंदन सिंह
(भारसाधक अधिकारी)

श्री साहबलाल चौरे
(प्रभारी सचिव)

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति बानापुरा, जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

आवास योजना को बनाया इन्द्रधनुषी : प्रधानमंत्री



नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'गृह प्रवेशम्' का शुभारंभ कर मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के पौने दो लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश करवाया। ऑन लाइन गृह प्रवेश कार्यक्रम के माध्यम से मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के शानदार क्रियान्वयन का साक्षी पूरा देश बना। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को अनावश्यक सरकारी दखल से बचाकर इन्द्रधनुषी स्वरूप दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि योजना में लाभान्वित हितग्राहियों के लिए इस वर्ष त्योहारों की खुशियाँ ज्यादा होंगी। आपके जीवन की इतनी बड़ी खुशी में शामिल होने मैं स्वयं प्रत्यक्ष आता, लेकिन कोरोना ने विवश कर दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार जिले के श्री गुलाब सिंह आदिवासी, सिंगरौली जिले के श्री प्यारेलाल यादव और ग्वालियर के श्री नरेन्द्र नामदेव से बातचीत की।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि आवास योजना में आमतौर पर एक मकान के निर्माण में 125 दिन लगते हैं। मध्यप्रदेश में बहुत से मकान सिर्फ 45 से 60 दिन में बन गए। मध्यप्रदेश में जिस गति से यह कार्य हुआ है, वह अपने आप में एक रिकार्ड है। मध्यप्रदेश में 1.75 लाख आवासों का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि है। यह गति रही तो वर्ष 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्यप्रदेश का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

इस मौके पर मुरैना से कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंस द्वारा शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत किया। वर्चुअल कार्यक्रम में मध्यप्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, मध्यप्रदेश के पंचायत एवं

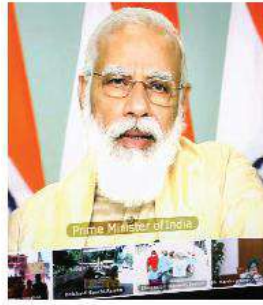
ग्रामीण विकास मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। मध्यप्रदेश के आवास पाने वाले हितग्राहियों से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आत्मीयता पूर्वक बातचीत भी की। भोपाल में मंत्रालय से वीसी द्वारा मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस भी कार्यक्रम में उपस्थित थे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज मध्यप्रदेश के 1.75 लाख लोग आनंद के माहौल में हैं, जिन्हें आवास मिले हैं। प्रदेश में उत्सव का माहौल है। इसके साथ ही अन्य लोग जिनके पास अपना मकान नहीं है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने धार जिले के गुलाब सिंह आदिवासी से स्थानीय बोली में संवाद आरंभ किया। उन्होंने हितग्राही श्री गुलाब सिंह की अच्छा घर बनाने के लिए तारीफ की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सिंगरौली जिले के बेढ़न के ग्राम पंचायत गडेरिया के श्री प्यारेलाल यादव और ग्वालियर जिले के योजना के हितग्राही श्री नरेन्द्र नामदेव से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हितग्राहियों से बातचीत के बाद उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज से इन सभी हितग्राहियों का नया जीवन प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आव्हान किया कि कोरोना के संक्रमण की समस्या समाप्त नहीं हुई है। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो स्वच्छता का पूरा ध्यान रखे। कोरोना संक्रमण को दूर करने की दवाई अर्थात वैक्सीन जब तक नहीं आती तब-तक ढिलाई नहीं होना चाहिए। मास्क का उपयोग करें। परस्पर दो गज की दूरी अवश्य रखें।

सूदखोरों से बचाकर स्ट्रीट वेंडर्स को मदद दिलवाई

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मध्यप्रदेश ने स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण के लिए बहुत कम समय में बेहतरीन कार्य कर दिखाया है। पीएम स्वनिधि योजना में हुए इस कार्य से अन्य राज्य प्रेरणा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस अवसर पर घोषणा की कि स्ट्रीट वेंडर्स के



प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी, मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह, केन्द्र सरकार के सचिव शहरी विकास मंत्रालय श्री दुर्गाशंकर मिश्र, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश श्री इकबाल सिंह बैस और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कल्याण की एक अन्य योजना पर भी विचार किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत शीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने लघु व्यवसायियों से डिजिटल लेन-देन को अपनाकर अपने कारोबार को कई गुना बढ़ाने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्यप्रदेश की उपलब्धि और लॉकडाउन के दौरान अच्छा कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान को बधाई दी। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा की मध्यप्रदेश में पीएम स्वनिधि योजना की सफलता श्रम की ताकत का परिचायक है जिसे मैं आदरपूर्वक नमन करता हूँ। मध्यप्रदेश के एक लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ सुनिश्चित कर पहचान-पत्र और अन्य लाभ देने का कार्य प्रशंसनीय है। महामारी के समय गरीबों को इस योजना में मिली यह राहत वरदान सिद्ध हुई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल संवाद के बाद योजना में पांच लाख हितग्राही को लाभान्वित करने का लक्ष्य नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दिया है।

वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के साथ केन्द्रीय आवास एवं शहरी कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश की 130 करोड़ जनता के लिए 1 लाख 75 हजार करोड़ का गरीब कल्याण राहत पैकेज प्रदान कर, गरीब की थाली, खाली न रहने देने के संकल्प के साथ 80 करोड़ जनता तक अनाज पहुंचाया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सबसे पहले इन्दौर जिले के सांवेर के पीएम स्वनिधि योजना के हितग्राही श्री छगन लाल वर्मा से बात की। श्री छगनलाल झाड़ू बेचने का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री छगनलाल को झाड़ू के निर्माण में लगने वाली सामग्री, प्राप्त हो रहे लाभ के बारे में चर्चा की।

कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों से कहा कि पीएम स्वनिधि योजना में पांच लाख स्ट्रीट वेंडर्स हितग्राही लाभान्वित करने का लक्ष्य पूर्ण किया जाए। स्वनिधि संवाद में आज प्रधानमंत्री श्री मोदी का संबोधन मध्यप्रदेश के पौने चार सौ स्थानों पर सुना गया। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इसके सीधे प्रसारण की व्यवस्था से योजना के बारे में नागरिक अवगत हो सके।

देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरू

नई दिल्ली। देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री वाय.एस. जगनमोहन



रेड्डी के मुख्य अतिथि में हुआ। रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश सी. अंगड़ी ने अध्यक्षता की। दक्षिण मध्य रेलवे के गुंतकल मंडल के अंतर्गत, यह विशेष गाड़ी के रूप में अनंतपुर (आंध्र प्रदेश) से आदर्श नगर (दिल्ली) के लिए रवाना हुई। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि किसान रेल से कृषि की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं श्री रेड्डी ने कहा कि इसके माध्यम से आंध्र प्रदेश के मशहूर फल देश में सुगमता से पहुंचेंगे। श्री तोमर ने कहा कि बजट में किसान रेल व किसान उड़ान की सुविधाओं की घोषणा

की गई थी, ताकि फल-सब्जियां कम समय में एक से दूसरे स्थान पर भेजे जा सकें। गत 7 अगस्त को देवलाली से दानापुर तक पहली किसान रेल प्रारंभ की गई, जिसकी मांग बढ़ने पर रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने इसके फेरे भी बढ़ा दिए

हैं। अब दूसरी किसान रेल चलने से आंध्रप्रदेश से दिल्ली तक रास्ते के सभी राज्यों के किसानों को भी इसका लाभ होगा। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परपोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी, आंध्र प्रदेश के मंत्री श्री बी. सत्यनारायण, श्री एम. शंकरनारायण व श्री के. कन्नाबाबू, अनंतपुर के सांसद श्री टी. रंगव्या, क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल, साउथ सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक श्री गजानन मलैया भी उपस्थित थे।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

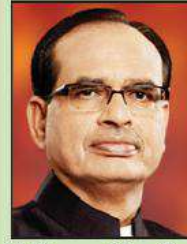


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री संजीव केशवपांडे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री जे.के. चौधरी
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
खंडवा, जिला खंडवा (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

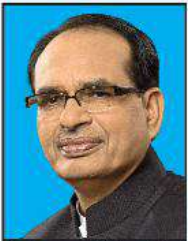


श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

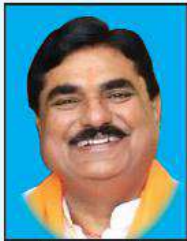
डॉ. परीक्षित झाडे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री मोहनलाल भदनेकर
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
हरसूद, जिला खंडवा (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का कय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ठेक पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

श्रीमती अनुभा जैन
(भारसाधक अधिकारी)

श्री आपसिंह किराड़े
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
पंधाना, जिला खंडवा (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

श्री के.आर. बडोले
(भारसाधक अधिकारी)

श्री जयराम वानखड़े
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)

किसानों के लिए 3805 करोड़ की ऋण परियोजनाएँ मंजूर

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि केंद्र सरकार ने 5 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 100 लाख हेक्टेयर भूमि कवर करने का लक्ष्य रखा है। कृषि में



जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म सिंचाई कवरेज पर आयोजित वेबिनार में श्री तोमर ने कहा कि वर्ष 2019-20 में ड्रिप व स्प्रींकलर सिस्टम अपनाने से 11 लाख किसानों को लाभ हुआ है। माइक्रो इरिगेशन फंड कॉर्पस की स्टियरिंग कमेटी व नाबार्ड ने राज्यों में 3,805.67 करोड़ रु. ऋण की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका क्षेत्र कवरेज 12.53 लाख हेक्टेयर है।

श्री तोमर ने कहा कि कृषि में उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के साथ ही लागत कम करना भी जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना मिशन मोड पर चल रही है, जिससे

निश्चित रूप से पानी व केमिकल की बचत होगी तथा मृदा स्वास्थ्य बढ़ाने में भी कामयाबी मिलेगी। कार्ड से किसानों में जागरूकता पैदा हुई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से चल रहे कार्यक्रमों का लाभ भी किसानों को मिल रहा है।

योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों का भी अच्छा सहयोग मिल रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि क्षेत्र में कई रिफार्म्स किए हैं, उनका लाभ भी किसानों को मिलने वाला है, इस दिशा में राज्य उत्तरोत्तर प्रगति कर रहे हैं।

कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री परषोत्तम रूपाला व श्री कैलाश चौधरी तथा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। वेबिनार के विभिन्न सत्र हुए, जिनमें श्री रूपाला व श्री चौधरी तथा नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद्र, कृषि मंत्रालय के सचिव श्री संजय अग्रवाल, राज्यों के प्रमुख सचिव (कृषि) तथा अन्य विशेषज्ञों ने विचार व्यक्त किए।

खरीफ की 1045.18 लाख हेक्टेयर में रिकॉर्ड बुवाई

नई दिल्ली। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार खरीफ फसलों के तहत लगभग 59 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों में बुवाई हुई। पिछले वर्ष की इसी अवधि में 1045.18 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस बार 1104.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुवाई के साथ रिकॉर्ड प्रगति दर्ज की गई है। धान (चावल) की बुवाई अब भी जारी है जबकि दलहन, मोटे अनाज और तिलहन की बुवाई लगभग हो चुकी है। खरीफ सीजन के लिए बुवाई के अंतिम आंकड़े 1 अक्टूबर 2020 को आने की उम्मीद है।

चावल : चावल की बुवाई पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 373.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस बार 402.25 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है अर्थात् बुवाई क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। **दलहन :** पिछले वर्ष के 131.76 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल के मुकाबले इस बार 137.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन की खेती हुई है, अर्थात् 4.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **मोटे अनाज :** पिछले वर्ष के 177.43 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस बार 179.70 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती हुई अर्थात् 1.28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

तिलहन : पिछले साल के 176.91 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की तुलना में इस बार 195.99 लाख हेक्टेयर क्षेत्र तिलहन की बुवाई हुई अर्थात् तिलहन बुवाई क्षेत्र में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **गन्ना :** पिछले साल के 51.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस बार 52.46 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ने की बुवाई हुई यानी बुवाई क्षेत्र में 1.37 प्रतिशत की वृद्धि हुई। **कपास :** पिछले वर्ष के 126.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के मुकाबले इस बार 129.30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती की गई अर्थात् कपास बुवाई क्षेत्र में 2.12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

कोविड-19 महामारी का खरीफ फसलों के अंतर्गत बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी पर आज तक कोई प्रभाव नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राज्य सरकारों ने मिशन कार्यक्रमों और फ्लैगशिप योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए सभी प्रयास किए हैं। भारत सरकार द्वारा समय पर बीज, कीटनाशक, उर्वरक, मशीनरी और ऋण जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की वजह से कोविड-19 महामारी की लॉकडाउन स्थितियों में भी बुवाई क्षेत्र में बढ़ोतरी संभव हो पाया है।

नौजवानों के लिए रोजगार के अन्य अवसर भी खोलेंगे

भिंड। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी खोलेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार ने पुलिस में भर्ती शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही अटल एक्सप्रेस-वे जैसी वृहद योजनाओं को गति दी है, जिससे चंबल क्षेत्र का चहुँमुखी विकास होगा। साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान भिंड जिले के मेहगाँव में आयोजित हुए विकास कार्यों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, केन्द्रीय कृषि, पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर तथा राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगभग 206 करोड़ रुपये लागत के विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भिंड व मुरैना जिले के नौजवान अब सैन्य बलों में केवल सिपाही ही नहीं, अफसर भी बनेंगे। इसके लिये भिंड जिले में सैन्य स्कूल खुलने जा रहा है।



मेहगाँव व गोहद क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिये 160 करोड़ रुपये लागत की वृहद सिंचाई परियोजना की सौगात दी है। इस परियोजना के मूर्तरूप लेने के बाद कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएगा।

केन्द्रीय मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रदेश सरकार

ने अटल एक्सप्रेस-वे को गति देने की पहल कर चंबल अंचल को खुशहाली का नया पैगाम दिया है। श्री तोमर ने कहा कि 8 हजार करोड़ रुपये लागत के अटल एक्सप्रेस-वे के मूर्तरूप लेने के बाद इस क्षेत्र की तस्वीर व तकदीर दोनों बदलेंगी। राज्यसभा सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा खुशी की बात है कि मध्यप्रदेश सरकार के मुखिया श्री शिवराज सिंह चौहान एक सच्चे जनसेवक हैं। जिसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विकास कार्यों की बड़ी-बड़ी सौगातें देकर मेहगाँव क्षेत्र के विकास के लिये नए दरवाजे खोले हैं। नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।

विन्ध्यावैली के उत्पाद ऑनलाइन पर भी उपलब्ध : श्री भार्गव

भोपाल। कुटीर एवं खादी-ग्रामोद्योग मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि "लोकल फॉर व्होकल" के अन्तर्गत विन्ध्यावैली के उत्पाद बेस्ट प्राइज, डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश, प्रियदर्शनी जैसे मार्डन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी उपलब्ध होंगे। साथ ही एमेज़ोन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन भी उपलब्ध रहेंगे। इसके लिए म.प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा मार्केटिंग की नई रणनीति तैयार की गई है।



गोपाल भार्गव

मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग के प्रबन्ध संचालक श्री गौतम सिंह ने बताया है कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके तहत खादी वस्त्रों एवं कबीरा ब्राण्ड के प्रमोशन के लिए मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए खादी की जाकेट रियायती दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। विन्ध्यावैली ब्राण्ड के पैकड ड्रिंकिंग वाटर और मसाले मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटल और रेस्टोरेंट में उपयोग किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि विन्ध्यावैली उत्पादों की ऑनलाइन उपलब्धता एमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, इत्यादि के माध्यम से सुनिश्चित

किये जाने के लिए इन संस्थानों के साथ चर्चा प्रारंभ की गई है। प्रदेश में विन्ध्यावैली/कबीरा खादी का एक्सक्लूसिव शोरूम प्रारंभ किये जाने का निर्णय भी लिया गया है। प्रदेश में खादी के उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने एवं अधिक से अधिक संख्या में कस्बियों एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से देवास, इन्दौर, नीमच एवं सीहोर में नवीन खादी उत्पाद केन्द्रों का संचालन प्रारंभ किया जाना।

विन्ध्यावैली उत्पाद आमजन को सुगमता से उपलब्ध हो, इसके लिये प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 200 ग्रामोद्योग इकाइयों/स्व-सहायता समूहों के द्वारा उत्पादित एफएमसीजी उत्पादों को "लोकल फॉर व्होकल" अन्तर्गत विन्ध्यावैली ब्राण्ड से सम्बद्ध किया जाकर खुले बाजार में उपलब्ध कराया जावेगा, जिसके लिए प्रदेश के प्रत्येक संभाग में एक-एक सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इसी के तहत मार्डन ट्रेड अन्तर्गत प्रतिष्ठित व्यावसायिक संस्थान यथा बेस्ट प्राइज, डी-मार्ट, रिलायंस फ्रेश, प्रियदर्शनी इत्यादि के स्टोर्स के माध्यम से विक्रय किया जावेगा।

गड़बड़ी करने वालों की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही करें



भोपाल। सहकारिता विभाग की गतिविधियों व योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये। सिस्टम में तकनीकी व पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाये। प्रत्येक स्तर पर कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो। सहकारी संस्थाओं में यदि गबन व घोटाले प्रकाश में आते हैं तो उनमें संबंधित अधिकारियों/ कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाये तथा उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही हो। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने सहकारिता विभाग के मैदानी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभागीय समीक्षा में यह निर्देश दिये।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं में गड़बड़ियां क्षम्य नहीं हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि इन मामलों में जीरो टालरेन्स की नीति अपनाई जाये। उन्होंने कहा कि सिस्टम में अच्छा काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाये और उनका सावर्जनिक सम्मान भी किया जाये। मंत्री डॉ. भदौरिया ने सहकारिता की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया। उन्होंने तकनीकी के इस युग में कम्प्यूटाइजेशन को बढ़ावा देने के निर्देश दिये। डॉ. भदौरिया ने अधिकारियों को टीम भावना के साथ जनहित में संवेदनशीलता के साथ काम करने की सीख दी। उन्होंने विभाग में नवाचार और सहकार की भावना को भी बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता जताई।

मंत्री डॉ. भदौरिया ने गेहूँ उपार्जन कार्य में विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष रिकार्ड 129 लाख मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन किया गया है। उन्होंने उपार्जन कार्य के लिए नोडल अधिकारी व संयुक्त आयुक्त श्री बृजेश शुक्ला को सम्मानित भी किया।

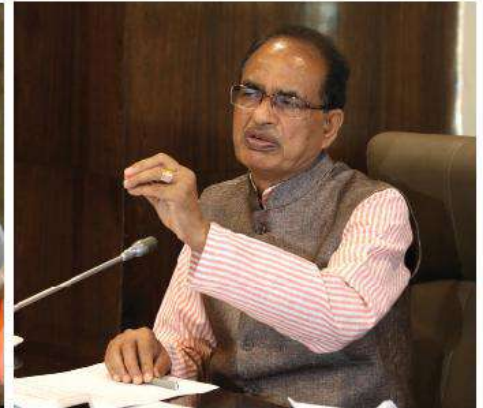
मंत्री डॉ. भदौरिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि शीघ्र ही

उनके द्वारा संभाग व जिलों का दौरा कर विभागीय कार्यों व योजनाओं की समीक्षा के साथ ही का मौका मुआयना भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि सहकारिता सिस्टम को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाये, जिससे कि गड़बड़ी न हो। मंत्री डॉ. भदौरिया ने प्रधानमंत्री की 'आत्मनिर्भर भारत' व मुख्यमंत्री की 'आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश' योजना के तहत सहकारिता के क्षेत्र में वायवल प्रोजेक्ट लेने पर जोर दिया, जिससे कि उनके आर्थिक रूप से सफल होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो।

वीडियो कॉन्फ्रेंस में आत्मनिर्भर भारत कृषि अधोसंरचना कोष अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोजेक्ट, आगामी कार्ययोजना, पी.एम. किसान योजना में पात्र किसानों को जारी के.सी.सी. में ऋण वितरण, पशुपालक कृषकों को कार्यशील पूँजी साख् सीमा, खरीफ 2020 में ऋण वितरण, कृषि ऋणों की वसूली, रबी 2020-21 के लिये उर्वरकों का अग्रिम भंडारण, खरीफ 2020 के लिये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत प्रीमियम प्रेषण की भी समीक्षा की गई। उन्होंने मैदानी अधिकारियों को निर्देश दिये कि उपार्जन केन्द्रों पर प्लेटफार्म निर्माण के लिये भूमि के चिन्हांकन एवं विभाग को भूमि के ट्रांसफर कराये जाने की प्रक्रिया 15 सितम्बर 2020 तक पूर्ण की जाए।

यह भी कहा कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से सम्पर्क कर प्लेटफार्म निर्माण का कार्य भी मनरेगा अन्तर्गत स्वीकृत करवा कर काम शुरू कराये। सोसायटियों के अंकेक्षण की प्रगति, अंकेक्षण शुल्क की वसूली की भी विस्तार से समीक्षा की। सहकारिता न्यायालयीन केस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में भी अवगत कराते हुए बताया कि इस नवीन सिस्टम की अभी परीक्षण स्तर पर शुरूआत की जा रही है। सोसायटियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की जानकारी भी दी गई।

पंचायतों को कार्यों के लिए मिलेगी पर्याप्त धन राशि



भोपाल। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा है कि देश की सत्तर प्रतिशत आबादी गांवों में निवास कर रही है। गांवों की तस्वीर बदलने का दायित्व पंचायत प्रतिनिधियों का है। राज्य सरकार इन कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। पंचायत प्रतिनिधि विकास कार्यों का पूरी प्रतिबद्धता, पारदर्शिता और ईमानदारी से संचालन करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 15वें वित्त आयोग अनुदान की 996 करोड़ राशि, पंचायतों को सिंगल क्लिक से ई-ट्रांसफर की। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित भी किया। मंत्रालय से आयोजित इस वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा की गई व्यवस्थाओं और कार्यों के लिए उनकी सराहना की।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि पंच परमेश्वर योजना के

**मुख्यमंत्री श्री चौहान
ने पंचायतों को
पंद्रहवें वित्त आयोग
की राशि जारी की**

अंतर्गत प्राप्त 996 करोड़ रूपए पंचायतों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे पेयजल और स्वच्छता से संबंधित कार्य कराये जाना है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक पंचायतों को 15 वें वित्त आयोग से तीन हजार 984 करोड़ रूपए उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इससे ग्रामों की तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर बताया गया कि कुल राशि का 85 प्रतिशत ग्राम पंचायत, 10 प्रतिशत जनपद पंचायत और 5 प्रतिशत जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी जिला व जनपद पंचायतें एन.आई.सी. से तथा सभी ग्राम पंचायतों को वैब लिंक के माध्यम से जोड़ा गया था। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

कृषक मित्रों को आर्गेनिक स्टेट बनाने का दिलाया संकल्प

भोपाल। संस्कृति एवं आध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर ने कहा कि मानव स्वास्थ्य के लिये रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नुकसानदायक है। सुश्री ठाकुर ने रासायनिक खेती से मुक्ति दिलवाकर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये कल महू में किसानों और कृषक मित्रों को आर्गेनिक स्टेट बनाने का संकल्प दिलाया। सुश्री ठाकुर ने कृषि अधिकारियों से कहा कि जैविक खेती बहुत लाभदायक है। कृषकों को इसकी अधिक से अधिक जानकारी दें।



उषा ठाकुर

सुश्री ठाकुर ने कहा कि जैविक खाद के उपयोग से भूमि की गुणवत्ता में सुधार, जलधारण क्षमता बढ़ने के साथ वाष्पीकरण कम होता है। जैविक खेती से मृदा की उर्वरता और

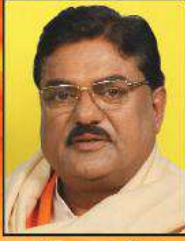
उत्पादन बढ़ता है। सुश्री ठाकुर ने आर्गेनिक स्टेट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर किसानों को जैविक खेती का प्रशिक्षण देने के निर्देश दिये। सुश्री ठाकुर ने बताया कि आर्गेनिक खेती के लिये विभिन्न शासकीय योजनाओं में सब्सिडी का प्रावधान है। किसानों को इन लाभों के बारे में बताये। जागरूकता के अभाव में किसान योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।

किसानों को 4600 करोड़ की मिलेगी बीमा राशि

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के 21 लाख किसानों को वन क्लिक से 4600 करोड़ रूपए की बीमा राशि उनके खातों में ट्रांसफर करेंगे। खरीफ 2019 की बीमित फसलों की बीमा राशि किसानों के खाते में 18 सितम्बर को अंतरित की जाएगी। पूर्व में यह कार्यक्रम 8 सितम्बर को प्रस्तावित था।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

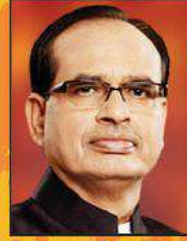
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

सुश्री अनु जैन
(भारसाधक अधिकारी)

श्री पन्नलाल भरतुनिया
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
उन्हेल, जिला उज्जैन (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री सत्येन्द्र बेरवा
(भारसाधक अधिकारी)

श्री भगवानसिंह मालवीय
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
हाटपीपल्या, जिला देवास (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

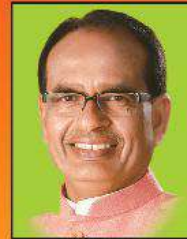
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री नरेन्द्रसिंह धुर्वे
(भारसाधक अधिकारी)

श्री सुजानसिंह भँवर
(प्रभारी सचिव)

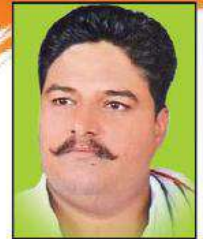
सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
कन्नौद, जिला देवास (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री एस.एल. सोलंकी
(भारसाधक अधिकारी)

श्री डी.सी. राजपूत
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.)



भारत के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ



74वें स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक बधाइयाँ



किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि रज के लिए ऋण	खेत पर रोड निर्माण हेतु ऋण
दुग्धा देवरी योजना (परुपातन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	त्यादी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण

सौजन्य से



श्री जगदीश कन्नोज
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री एम.एल. गजभिये
(प्रशासक एवं उपायुक्त)



श्री गणेश यादव
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री एस.के. खरे
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

श्री ओमप्रकाश श्रोत्रिय (शा.प्र. राऊ)
श्री लक्ष्मणसिंह वर्मा (पर्य. राऊ)
श्री कैलाश परिहार (शा.प्र. अटाहेड़ा)
श्री कैलाश चौधरी (पर्य. अटाहेड़ा)
श्री सुनील सतवासकर (शा.प्र. संयोगितागंज)
श्री महेन्द्र कुमार बनोधा (पर्य. संयोगितागंज)
श्री देवकरण चौधरी (शा.प्र. मानपुर)
श्री राजेन्द्र पटेल (पर्य. मानपुर)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. निरंजनपुर, जि.इंदौर
श्री नारायण प्रसाद निर्मल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. भँवरासला, जि.इंदौर
श्री नारायण प्रसाद निर्मल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. पिगडम्बर, जि.इंदौर
श्री धर्मेन्द्रसिंह भाटी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. राऊ, जि.इंदौर
श्री प्रदीप कुमार नागर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रंगवासा, जि.इंदौर
श्री रमेशचंद पाण्डे (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कैलोद कर्ताल, जि.इंदौर
श्री ओमप्रकाश पाटीदार (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. रालामंडल, जि.इंदौर
श्री ओमप्रकाश पाटीदार (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. दूधिया, जि.इंदौर
श्री भारतसिंह जाट (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. विजलपुर, जि.इंदौर
श्री महेन्द्र कुमार बनोधा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. तिल्लौर खुर्द, जि.इंदौर
श्री किरण इंगले (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कनवासा, जि.इंदौर
श्री कैलाश चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. राई, जि.इंदौर
श्री कैलाश चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. नाव्द्रा, जि.इंदौर
श्री प्रेमसिंह राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. अटाहेड़ा, जि.इंदौर
श्री प्रेमसिंह राठौर (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. उजाल्या, जि.इंदौर
श्री घनश्याम पंवार (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. मानपुर, जि.इंदौर
श्री सुमित शर्मा (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. यशवंत नगर, जि.इंदौर
श्री राजेन्द्र पटेल (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. खुर्दी, जि.इंदौर
श्री बहादुरसिंह गौड़ (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. कमदपुर, जि.इंदौर
श्री सदाशिव परसावदिया (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. शेरपुर, जि.इंदौर
श्री सुदामा चौधरी (प्रबंधक)

सेवा सहकारी संस्था मर्या. हासलपुर, जि.इंदौर
श्री राजेन्द्र पटेल (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे

भोपाल। प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारी अब मंडी बोर्ड के कर्मचारी होंगे। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की टेंशन भी खत्मा। आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपए का फण्ड पेंशन के लिए रहेगा।



कृषि मंत्री श्री कमल पटेल की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 135वीं बैठक में मंडी बोर्ड के कर्मचारियों के हित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने बोर्ड की बैठक में प्रदेश की सभी मंडी समितियों के कर्मचारियों को मंडी बोर्ड के कर्मचारी बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने इसके लिये आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए समग्र प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री पटेल ने कहा किसी भी मंडी समिति के कर्मचारी को अब सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मण्डी बोर्ड में आरक्षित निधि में 200 करोड़ रुपये की राशि का फण्ड सुरक्षित रखा जायेगा। इससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी। श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की चिंताओं से भली-भाँति वाकिफ है। मण्डी के कर्मचारी बेहतर कार्य करते रहें, किसी प्रकार की चिंता न करें।

मण्डियों को बाजार की प्रतिस्पर्धा में लाने के लिये स्मार्ट मण्डियों के रूप में विकसित किया जायेगा। इससे मण्डियों की

आय में वृद्धि होगी। स्मार्ट मण्डियाँ बनने से किसान भी लाभान्वित होंगे। बैठक में प्रमुख सचिव कृषि श्री अजीत केसरी के सुझाव पर मंत्री श्री पटेल ने मण्डी समिति के सदस्यों से मण्डियों को उत्कृष्ट बनाने

और प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिये उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने मण्डियों की आय में गिरावट आने पर भी चिंता व्यक्त करते हुए सुधारों के लिये आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिये। इसके लिये सदस्यों से सुझाव भी आमंत्रित किये।

मण्डी में खरीदी की जिम्मेदारी मण्डियों की

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मण्डी प्रांगण के भीतर किसानों से होने वाली खरीदी एवं भुगतान की जिम्मेदारी मण्डियों की है। उन्होंने कहा कि मण्डी में अपनी उपज को विक्रय करने के बाद किसानों को भुगतान के लिये अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े, इसके लिये सभी आवश्यक प्रबंध किये जायें। किसानों को लंबित भुगतान करने के लिये खरीदी करने वाले व्यापारियों और जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों से भी वसूली करने के लिये कड़े कदम उठाये जायें। बैठक में प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड श्री संदीप यादव, उप सचिव एवं प्रभारी संचालक सुश्री प्रीति मैथिली, अपर संचालक श्री केदार सिंह और अपर संचालक श्री अमर सेंगर मौजूद थे।

बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित

हरदा। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने हरदा जिले के हंडिया का दौरा कर ग्रामीणों और किसानों को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके साथ है। उन्होंने कहा कि समाज का कमजोर तबका हमारे कलेजे का टुकड़ा है। इनके विकास के बगैर समाज का विकास संभव नहीं है।



उन्होंने हंडिया में बाढ़ प्रभावित चार सौ से अधिक परिवारों को राहत सामग्री और सहायता राशि के रूप में 5000 भी प्रदान किए।

कृषि मंत्री श्री पटेल ने कहा कि शासन की निर्देशानुसार प्रशासन घरों का सर्वे कर रहा है। वीडियोग्राफी की जा रही है। सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। सभी कच्चे घरों में रहने

वाले परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित कर 2024 तक पक्का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करेगी और गलत कार्य करने वालों को दंडित करने से भी पीछे नहीं हटेगी।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि जब शासन की भावना के अनुसार प्रशासन कार्य करने लग जाता है तो जनता को उसका लाभ मिलता है। जब जनता लाभान्वित होने लगती है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास लोकतंत्र की उपलब्धि है। भ्रमण के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि गण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गण मौजूद रहे।

बैंक अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहें

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैंक अपने सामाजिक दायित्व के प्रति सजग और सक्रिय रहें। कोरोना काल से उपजी परिस्थितियों के कारण पथ विक्रेता से लेकर उद्यमियों तक के जीवन को पटरी पर



लाना हम सब का दायित्व है। इसमें बैंक अपनी भूमिका पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही से निभाएं। स्ट्रीट वेंडर, किसानों, दुग्ध उत्पादकों, मछुआरों, स्व-सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिये संचालित योजनाओं में बैंकों का रूख हितग्राहियों के लिये सहयोगात्मक हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैंकों के राज्य प्रमुखों से चर्चा कर रहे थे। मंत्रालय में आयोजित इस कान्फ्रेंस में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जिन बैंकों का रवैया सहयोगात्मक नहीं होगा, उन्हें राज्य शासन की ओर से देय सहयोग पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। इसके साथ ही उनके परफार्मेंस के संबंध में केन्द्रीय वित्त मंत्री तथा संबंधित बैंक के चेयरमैन को अवगत कराया जाएगा।

वीडियो कान्फ्रेंस में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स स्वनिधि योजना

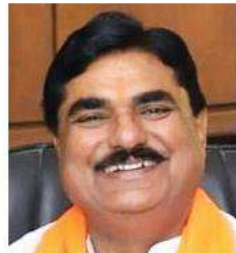
(शहरी), मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, पी.एम. किसान योजना के अंतर्गत छूटे हुए किसानों को, डेयरी कृषकों, अन्य दुग्ध उत्पादक कृषकों और मछुआरों को क्रेडिट कार्ड जारी करने तथा स्व-सहायता समूहों के वित्त

पोषण की स्थिति की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे इन योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में प्रतिमाह भाग लेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा सहकारी बैंकों को बेहतर परफार्मेंस के लिए बधाई दी।

वीडियो कान्फ्रेंस में किसान कल्याण तथा कृषि विकास राज्यमंत्री श्री गिरिराज दंडोतिया, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री के.के. सिंह, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव वित्त श्री मनोज गोविल, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री एस.डी. माहूरकर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

पंजीयन के लिए ई-उपार्जन पोर्टल शीघ्र होगा प्रारम्भ

भोपाल। प्रदेश में सोयाबीन सहित अन्य खरीफ फसलों के उपार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव पर कृषि मंत्री श्री कमल पटेल ने सैद्धांतिक सहमति प्रदान कर दी है। उन्होंने कहा है कि ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन की कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जाएगी।



कमल पटेल

श्री पटेल ने बताया है कि भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम के तहत खरीफ फसलों के उपार्जन की तैयारी पूरी कर ली गई है। पंजीयन के लिए विगत वर्ष के सभी पंजीयन केंद्र यथावत रखे जाएंगे, जिससे किसानों को परेशान न होना पड़े। प्रदेश में सोयाबीन, अरहर, उड़द, मक्का के अतिरिक्त 34 जिलों में मूंग, 30 जिलों में तिल,

13 जिलों में रामतिल, 20 जिलों में मूंगफली, 9 जिलों में कपास की खरीद की जाना है।

श्री पटेल ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर तुअर के लिए 376 करोड़, उड़द के लिए 760 करोड़, मूंग के लिए 24 करोड़ कुल 1160 करोड़ रुपए की राशि उपार्जन के लिए अनुमानित है। शेष फसलों के उपार्जन के लिए चौथे पूर्वानुमान की जानकारी प्राप्त होने के बाद अनुमानित राशि का आंकलन हो सकेगा। श्री पटेल ने कहा है कि ई पोर्टल प्रारम्भ होते ही किसान भाई पंजीयन करा लें ताकि बगैर किसी परेशानी के सुगमतापूर्वक उपज का उपार्जन हो सके।

गुणवत्ताविहीन चावल प्रदाय के लिए जिला प्रबंधक निलंबित

भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट एवं मंडला जिलों में कुछ स्थानों पर गुणवत्ताविहीन चावल प्रदाय के प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रकरण में बालाघाट एवं मंडला जिलों के चावल की गुणवत्ता कार्य के लिए जिम्मेवार गुणवत्ता

नियंत्रकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। वहीं बालाघाट के जिला प्रबंधक को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित मिलर्स के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। चावल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए भारतीय खाद्य निगम एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के 51 संयुक्त दल बनाए गए।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

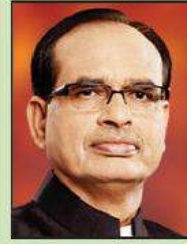
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री प्रकाश कश्वाई
(भारसाधक अधिकारी)

श्री हरगोविंद सोनगरा
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

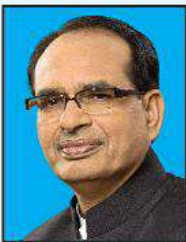
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

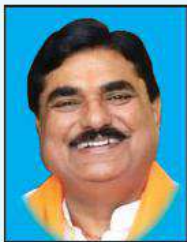
श्री अनिल कुशवाह
(भारसाधक अधिकारी)

श्री प्रमोद राजगुरु
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
बड़ोद, जिला आगर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

श्री वीर प्रताप सिंह
(भारसाधक अधिकारी)

श्री पर्वतसिंह सिसोदिया
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री मुकेश शर्मा
(भारसाधक अधिकारी)

श्री आत्माराम विजयवर्गीय
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
पिपल्या, जिला मंदसौर (म.प्र.)



**74वें स्वतंत्रता दिवस
की हार्दिक बधाइयाँ**

**भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ**



सौजन्य से

**स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण • खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड • कृषि यंत्र के लिए ऋण • दुग्ध डेयरी योजना**

**श्री रामनिवास सोनी (शा.प्र. बघाना)
श्री अशोक कुमार जोशी (शा.प्र. मनासा)
श्री रामकिशन पाटीदार (शा.प्र. रामपुरा)
श्री गोपाल प्रसाद शर्मा (शा.प्र. सावन)**



श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री भारत सिंह चौहान
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)



श्री रवि ठक्कर
(संभालीय शाखा प्रबंधक)



श्री पी.एन. यादव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. विलवासकलां, जि.नीमच
श्री राजेन्द्र रावल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जमुनियाकलां, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दारु, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धनोरियाकलां, जि.नीमच
श्री कारुलाल राठौर (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. वामनवडी, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रनाथ रावल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. वधाना, जि.नीमच
श्री कारुलाल राठौर (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मनासा, जि.नीमच
श्री मुकेश पाटीदार (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पिपल्या रावजी, जि.नीमच
श्री संतोष ओझा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. भाटखेडी, जि.नीमच
श्री मुकेश पाटीदार (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कंजार्डा, जि.नीमच
श्री मुकेश पाटीदार (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हासपुर, जि.नीमच
श्री श्यामलाल शर्मा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अल्हेड़, जि.नीमच
श्री संतोष कुमार ओझा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. गालीनेर, जि.नीमच
श्री संतोष कुमार ओझा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बेसला, जि.नीमच
श्री रामगोपाल शर्मा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पचोर, जि.नीमच
श्री रामगोपाल शर्मा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रामपुरा, जि.नीमच
श्री मुकेश सारु (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बरलई, जि.नीमच
श्री रामगोपाल शर्मा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. देवरान, जि.नीमच
श्री परसराम धनगर (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सावन, जि.नीमच
श्री हरिशंकर नागदा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सिरखेड़ा, जि.नीमच
श्री मुकेश पाटीदार (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जवासा, जि.नीमच
श्री हरिशंकर नागदा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सेमली मेवाड़, जि.नीमच
श्री मुकेश पाटीदार (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. बोरदियाकलां, जि.नीमच
श्री राजेन्द्रसिंह तंवर (प्रबंधक)**

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

प्रदेश में जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार

गुना। प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया ने कहा है कि प्रदेश में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के हित में कार्य करने वाली सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास और जनकल्याण के कार्य सरकार की प्राथमिकता में है। मंत्री श्री सिसौदिया ने यह बात बमोरी क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क एवं 9 करोड़ लागत से ज्यादा विभिन्न निर्माण कार्यों के आयोजित



भूमिपूजन के कार्यक्रमों में कही।

बमोरी क्षेत्र के भ्रमण के दौरान पूनमखेड़ी, जमरा, सगोरिया, खजुरी, संधुआ, शाहपुर, नसीरा, पदमनखेड़ी, म्याना तथा रीछई में जनसंपर्क किया एवं विकासीय कार्यों का भूमिपूजन किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा उनका शीघ्र निराकरण कराये जाने का आश्वासन दिया।

50 हेक्टेयर में बोई जाने वाली फसलों का भी होगा बीमा

भोपाल। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वनग्रामों के किसानों के साथ अन्य छोटे और सीमांत किसानों को लाभान्वित करने के लिये सरकार महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने बताया कि बीमा योजना में प्रावधानित पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर की बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के निर्देश दिये हैं।

श्री पटेल ने कहा कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित किसानों को राहत देने के लिये सभी आवश्यक उपाय और प्रावधान कर रही है। प्रदेश में गरीबों और किसानों को लाभ पहुँचाने के लिये सीहोर और हरदा जिले के वन ग्रामों को

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल कराया गया है। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि छोटे किसानों के हित में अब एक और प्रभावी पहल की जाकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिये पटवारी हल्का स्तर पर 100 हेक्टेयर बुआई क्षमता को घटाकर 50 हेक्टेयर करने के लिये कृषि विभाग के आला अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं। उन्होंने कहा है कि इससे छोटे, मझौले और गरीब किसानों को अधिकतम राहत पहुँचाई जा सकेगी।

मंत्री श्री पटेल ने रबी वर्ष 2020-21 तथा आगामी समस्त फसलों को बीमा योजना में लाने के लिये सभी आवश्यक पुख्ता कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं, जिससे कि प्रदेश के अधिकतम किसान लाभान्वित हो सकें।

भाप्रसे के 4 अधिकारियों की नवीन पदस्थापना

भोपाल। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नई पदस्थापना आदेश जारी किये गये हैं। श्रीमती अलका श्रीवास्तव सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश खाद्य आयोग को सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पदस्थ किया जाकर सदस्य सचिव मध्यप्रदेश खाद्य आयोग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री अनिल सुचारी सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को अपर सचिव गृह एवं परिवहन, श्री रामराव भोंसले अपर सचिव गृह को अपर सचिव खनिज साधन और श्री उमेश कुमार उप सचिव नगरीय विकास एवं आवास को सचिव माध्यमिक शिक्षा मण्डल पदस्थ किया गया है।

20 रु. प्रति गौवंश की दर से मिल रही राशि

भोपाल। मध्यप्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में गौशालाओं को प्रतिदिन 20 रुपये प्रति गौ-वंश के मान से ही राशि प्रदाय की जा रही है। मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के अन्तर्गत गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता का आदेश यथावत है। अप्रैल 2020 में प्रदेश की पंजीकृत गौशालाओं के गौवंश के चारे-भूसे के लिये 29 करोड़ 85 लाख रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इसके अलावा लगभग 28 करोड़ रुपये की राशि और जारी की जा रही है। गौशालाओं के गौवंश के चारा-भूसा अनुदान के लिये सरकार द्वारा किये गये बजट प्रावधान के अतिरिक्त भी यदि राशि की आवश्यकता होती है तो शासन द्वारा व्यवस्था की जाएगी। उपसंचालक राज्य गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड ने बताया कि मुख्यमंत्री गौसेवा योजना के तहत नवीन 1000 गौशालाओं के लिये 2 माह का चारा-भूसा अनुदान राशि 11 करोड़ 68 लाख रुपये कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला समितियों को पहले ही प्रदाय कर दी गई थी ताकि जिला प्रशासन को गौशाला संचालन में कठिनाई न हो।

प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू होगी नई शिक्षा नीति

ग्वालियर। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के चलते नवीन शिक्षा सत्र में ऑन लाइन पढ़ाई कराएंगे, जिससे छात्रों का वर्ष एवं पढ़ाई प्रभावित ना हो सके। उन्होंने कहा कि अतिथि विद्वानों के कई पदों को राज्य सरकार ने भर दिया है, वहीं अन्य बचे अतिथि विद्वानों को पीएससी के माध्यम से भरेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य में ओपन बुक से परीक्षा पद्धति को लागू किया गया है। वहीं अन्य राज्यों ने भी इसे कोरोना संकट के चलते अपनाया। उन्होंने कहा कि आगे आने वाला सत्र की शुरुआत कर दी है। लेकिन कोरोना संकट के चलते छात्र को प्रवेश तो दिया जा रहा है लेकिन अभी कालेजों में जाकर पढ़ाई नहीं



140 फर्जी कालेजों को किया बंद

विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक-एक कमरे में चलने वाले कालेजों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री यादव ने कहा कि लगभग 140 फर्जी कालेजों को बंद किया गया है। अब राज्य में 15 विवि और 33 निजी विवि हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल परीक्षा कराने वाले ही नहीं बने रहें इसके लिए विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक कार्य तथा साथ ही रिसर्च को बढ़ावा देने के प्रयास होंगे। अतिथि शिक्षकों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 4274 सेल्फ फायनेंस कोर्स के हैं तथा 1700 शासन के इनमें से 800 को कालेज में नियुक्ति दे दी गई है। 732 और बचे हैं उसके लिये होमवर्क किया जा रहा है। न्यायालय में भी मामला है, उसका समाधान होते ही इन सभी को पीएससी के माध्यम से या फिर कोई अलग से कुछ परीक्षा कराकर नियुक्ति दे दी जाएगी।

कराई जाएगी। वहीं वर्चुअल से लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। मंत्री यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी डीड कालेजों को डीड विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया जाएगा। अपनी योजना के बारे में उन्होंने बताया कि उनका प्रयास है कि प्रदेश में भवन विहीन महाविद्यालयों में से 50 को भवन युक्त किया जाएगा। वहीं कालेजों द्वारा नए कोर्स खोलने की अनुमति भी तत्काल प्रभाव से दी जा रही है जिससे अधिक से अधिक छात्रों को प्रवेश मिल सके।

पत्रकारों से चर्चा के दौरान मप्र बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष महेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष कमल माखाजानी, भाजपा मीडिया के प्रदेश सह प्रभारी उदय अग्रवाल, जीवाजी विवि के डीसीडीसी

डॉ.केशव सिंह गुर्जर उपस्थित थे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा

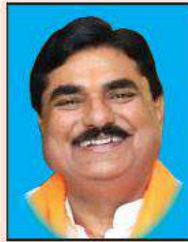
इंदौर। इंदौर जिले में वर्ष 2019-2020 के दौरान खेती-किसानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों को सर्वोत्तम कृषक/कृषक समूह पुरस्कार दिया जायेगा। इस पुरस्कार के लिये किसानों और समूहों के चयन के लिये कलेक्टर की अध्यक्षता में चयन समिति का गठन किया गया है। इस समिति में उप संचालक सह परियोजना संचालक आत्मा सदस्य सचिव रहेंगी। इसके अलावा समिति में पशु चिकित्सा, उद्यानिकी तथा मत्स्य पालन विभाग के उप संचालक तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र सदस्य रहेंगे। यह समिति विकासखंडों से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण कर मूल्यांकन कर सर्वोत्तम कृषक/कृषक समूह का चयन पुरस्कार के लिये करेगी।

संयुक्त कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन

इंदौर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तीन संयुक्त कलेक्टरों के मध्य कार्य विभाजन किया है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार संयुक्त कलेक्टर श्री सुनील झा को राऊ क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी बनाया गया है। इसी तरह संयुक्त कलेक्टर श्री सोहन कनाश को हातोद एवं श्री रविकुमार सिंह को कनाड़िया क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी बनाया गया है। इन अधिकारियों को पूर्व में सौंपे गये शाखाओं का प्रभार यथावत रहेगा। श्री झा को कोविड के लिये थाना क्षेत्र अन्नपूर्णा, चंदन नगर, राजेन्द्र नगर तथा द्वारकापुरी, श्री कनाश को हातोद और श्री रविकुमार सिंह को थाना क्षेत्र खजराना, कनाड़िया तथा तिलक नगर का दायित्व दिया गया है।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

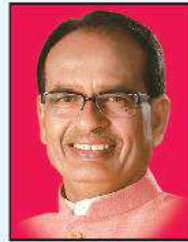
किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री रामलाल मुनिया : श्री अरविंद दिखीत
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
शामगढ़, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ठेर पर उपरिस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

डॉ. एस.बी. सिंह
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री सुनील डाबर : श्री सुरेन्द्र भिलाला
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सुवासरा, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की 73^{वीं} वर्षगाँठ पर शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

डॉ. एस.बी. सिंह
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

श्री बिहारी सिंह : श्री रमेशचंद्र मुजावदिया
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सीतामऊ, जिला मंदसौर (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74^{वें} स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

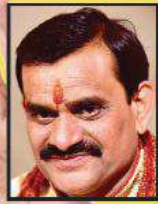
किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री आर.पी. वर्मा : श्री पन्नालाल भरतुनिया
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.)



**भारत के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी को जन्मदिवस
की हार्दिक शुभकामनाएँ**



**किसान क्रेडिट कार्ड
कृषि यंत्र के लिए ऋण
खेत पर रोड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण**



श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्रीमती सुनीता गोडवाल
(प्रशासक एवं उपायुक्त)



श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री के.के. रायकवार
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

**श्री शक्तिसिंह राणा (शा.प्र. सुसनेर)
श्री नारायण प्रसाद गायरी (पर्य. सुसनेर)**

**श्री दिलीप देशमुख (शा.प्र. अकोदिया)
श्री प्रहलादसिंह यादव (पर्य. अकोदिया)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
सुसनेर, जि.आगर
श्री छत्रपालसिंह राणा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
गेलाना, जि.आगर
श्री मानसिंह यादव (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
मकोड़ी, जि.राजापुर
श्री तँवरसिंह गोयल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
रतेराना, जि.आगर
श्री महेन्द्रसिंह काबल (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
लदूरी गेहलोत, जि.आगर
श्री कालूसिंह सिसोदिया (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
हल्डायकला, जि.राजापुर
श्री पदमसिंह मेवाड़ा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
मैना, जि.आगर
श्री जब्बार खान (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
गणेशपुरा, जि.आगर
श्री सौरभ जैन (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बोलाई, जि.राजापुर
श्री शैलेन्द्रसिंह यादव (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
जामुन्या, जि.आगर
श्री देवीलाल बैरागी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
अकोदिया, जि.राजापुर
श्री मनोहर सिंह मेवाड़ा (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बोसाली, जि.राजापुर
श्री आत्मराम गुर्जर (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
मालनवासा, जि.आगर
श्री कालूसिंह सिसोदिया (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
खादसुर, जि.राजापुर
श्री प्रेमनारायण मंडलोई (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
कैथलाय, जि.राजापुर
श्री मनोहरसिंह सिसोदिया (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
मोड़ी, जि.आगर
श्री देवेन्द्र जोशी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
सखेड़ी, जि.राजापुर
श्री गोजनसिंह सोलंकी (प्रबंधक)**

**प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
पोलायखुर्द, जि.राजापुर
श्री ओमप्रकाश सोनी (प्रबंधक)**

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

हिंदुस्तान में इंदौर अद्भुत शहर : मुख्यमंत्री श्री चौहान



इंदौर। इंदौर हिंदुस्तान का अद्भुत शहर है। यहां की परंपरा और संस्कृति की एक अलग पहचान है। अब यहां की जनता देश को स्वच्छता की परंपरा और स्वभाव सीखा रहा है। इंदौर की जनता ने न सिर्फ शहर का नाम दुनिया में रोशन किया बल्कि अपने नाम और काम को दुनिया के सामने रखा है। यह बात मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर के ट्रेचिंग ग्राउंड पर गीले कचरे के निष्पादन के लिए 550 टीडीपी बायोमेथेनाइजेशन प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान भी इंदौर ने सेवा का दायित्व सिखाया है। यहां की जनता ने मजदूरों और प्रवासियों की जो सेवा की है वो विश्व में मिसाल बन गई है।

महापौर एवं विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ ने कहा कि प्रथम चरण में 200 टन और द्वितीय चरण में 500 टन गीले कचरे का

निष्पादन पीपीपी मोड के तहत किया जाएगा। ट्रेचिंग ग्राउंड पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बरगद का पौधा भी रोपा। कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसी सिलावट, संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सांसद श्री शंकर लालवानी, पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक श्री आकाश विजयवर्गीय, श्री महेंद्र हार्डिया, श्री रमेश मेंदोला, श्री सुदर्शन गुप्ता, श्री मनोज पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

लगातार चार वर्षों से देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का यह अनोखा और अद्भुत सार्थक प्रयास है। जहां कभी गंदगी इस कदर फैली थी कि इसके आसपास के 2-2 किमी तक कोई गुजरना पसंद नहीं करता था। आज यहां उत्पादित बेहतरीन और उपजाऊ उर्वरक युक्त मिट्टी को इस ग्राउंड पर बिछाया गया है। इस पर सुंदरता का घना जंगल सबका मन मोह रही है।

दूध क्रय दरों में 40 रु. प्रति किलो फेट की वृद्धि

इंदौर। इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर अपने स्थापना वर्ष 1976 से कार्यक्षेत्र के सभी जिलों में दूध उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रति सजग है और अपने दूध उत्पादकों को उनके उत्पादित दूध का हर संभव उचित से उचित मूल्य देने हेतु सदैव प्रयत्नशील है।



मोतीसिंह पटेल

दुग्ध संघ के अध्यक्ष श्री मोतीसिंह पटेल ने बताया कि संचालक मण्डल ने किसानों को दूध के व्यवसाय में हो रहे नुकसान को ध्यान में रखते हुए, दूध क्रय भाव में वृद्धि की है। 'कोरोना महामारी' की वजह से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए दुग्ध संघ के संचालक मण्डल द्वारा आगामी माहों में दूध क्रय भाव में और वृद्धि की जायेगी। वर्तमान में 06 सितम्बर, 2020 से दुग्ध क्रय दरों में 40 रुपये प्रति किलोग्राम फेट की वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के पश्चात भैंस के दूध हेतु 580 रुपये प्रति किलोग्राम तथा गाय के दूध हेतु 216 रुपये प्रति किलो ठोस पदार्थ का भुगतान दुग्ध उत्पाद को प्राप्त

होगा। यह भाव वृद्धि संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों के नीति निर्धारण में सक्रिय भागीदारी एवं प्रबंधकीय सहयोग का प्रतिफल है।

इंदौर दुग्ध संघ द्वारा भारतीय खाद्य एवं मानक प्राधिकरण के मापदण्ड अनुसार ही दूध का क्रय समिति से जुड़े दुग्ध उत्पादों से किया जाता है, ताकि संकलित दूध गुणवत्ता से भरपूर हो और निर्बाध रूप से उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाला दूध एवं

दुग्ध उत्पाद मिल सके। संघ उच्च गुणवत्ता के दूध से विभिन्न दुग्ध उत्पादों का निर्माण साँची ब्राण्ड नाम से अपने आई.एस.ओ. संयंत्र में पूर्ण हाईजेनिक रूप से करता है। इस कारण सभी डेयरी उत्पाद उपभोक्ताओं की पहली पसंद बन गये हैं। डिजिटल मार्केटिंग के सपोर्ट से संघ ने अपनी रियल मिल्क आईस्क्रीम को ऑनलाइन विक्रय प्रारंभ किया है। आने वाले समय में शीघ्र संघ अपनी विपणन गतिविधियों को डिजिटलाइज्ड कर रहा है, जिसका परोक्ष लाभ संघ के ग्राहकों को मिलेगा।

2400 करोड़ रु. के नर्मदा जल योजना की देंगे सौगात



इंदौर। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिये 155 करोड़ रुपये लागत के कार्यों का शिलान्यास किया। इनमें सड़क, बिजली, पानी आदि के विकास कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान अगले महिने सितम्बर माह में 2400 करोड़ रुपये लागत के नर्मदा जल योजना के लिये भूमिपूजन करेंगे। इससे सांवेर विधानसभा क्षेत्र के गाँव-गाँव में पेयजल, सिंचाई तथा उद्योग के लिये पानी पहुंचेगा।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, पर्यटन मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सांसद श्री शंकर लालवानी, विधायकगण श्री रमेश मेंदोला, श्री आकाश

विजयवर्गीय, श्रीमती मालिनी गौड़, श्री महेन्द्र हार्डिया, पूर्व विधायक श्री सुदर्शन गुप्ता तथा श्री मनोज पटेल, श्री राजेश सोनकर, श्री गौरव रणदीवे, श्री मधु वर्मा, सुश्री कविता पाटीदार सहित अन्य जनप्रतिनिधि विशेष रूप से मौजूद थे।

श्री चौहान ने कहा कि इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र में विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया जायेगा। विकास का यह सिलसिला अनवरत चलेगा। जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अब सांवेर के विकास में कोई कोर-कसर नहीं रखी जायेगी। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचायी जायेगी। श्री सावन सोनकर ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद थे।

सहकारी बैंक अकृषि ऋण की वसूली में तेजी लाएँ

भोपाल। सहकारी बैंकों की माली हालत सुधारने के लिए शीघ्र ही अकृषि ऋण की वसूली करें। संभाग में लंबित पड़े अकृषि ऋण की वस्तुस्थिति बैंकों की ऑडिट बैलेंस शीट के माध्यम से तैयार करें। तत्काल ऐसे व्यक्तियों की सूची तैयार कर आरआरसी में प्रकरण दर्ज कर जिला कलेक्टरों (प्रशासक) से संबंधितों के खातों सीज करने की कार्यवाही करें। यह सख्त निर्देश भोपाल संभागयुक्त श्री कवीन्द्र कियावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के सभी जिलों के उपायुक्त सहकारिता सहित बैंक प्रबंधकों को दिए। इस मौके पर संयुक्त आयुक्त श्री अनिल द्विवेदी, उपायुक्त सहकारिता श्री विनोद सिंह, सीईओ दुग्ध संघ श्री के.के.सक्सेना सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

श्री कियावत ने कहा कि प्रायः बैंकों का एनपीए अकृषि ऋण



का लोगों द्वारा जमा नहीं करने से बढ़ा है इसलिए सभी सहकारिता अधिकारी और कर्मचारी बैंकों से ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर कार्यवाही प्रारंभ करें। आगामी 30 सितम्बर तक ऐसे समस्त प्रकरणों का निराकरण करें। जिला कलेक्टर (प्रशासक) के माध्यम से सभी डिफाल्टरों

की आरआरसी कराकर केस दर्ज करायें। जिससे सहकारी बैंकों के एनपीए में सुधार हो सके।

श्री कियावत ने कहा कि किसानों के लिये फसल बीमा अत्यंत जरूरी है। समितियाँ, बैंक, सहकारी संस्थाएं कृषकों के फसल बीमा आवेदनों को रात्रि में भी जमा एवं पंजीयन कराना सुनिश्चित करें। किसानों को समझाईश भी दें कि अपने फसल बीमा के लिये सहकारिता बैंक की नजदीकी शाखा में अपना प्रीमियम जमा करायें।

कृषिमंत्री ने लिया सोयाबीन फसलों का जायजा

देवास। किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने देवास जिले के खातेगांव क्षेत्र के ग्राम कुसमानिया और बागली क्षेत्र के ग्राम बड़कन में खेतों में जाकर अति-वर्षा और कीट से सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विधायक खातेगांव श्री आशीष शर्मा, विधायक बागली श्री पहाड़ सिंह कन्नौजे, पूर्व विधायक श्री ब्रजमोहन धुत सहित कृषकगण उपस्थित थे।

श्री पटेल ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रभावित फसलों का तत्काल सर्वे प्रारंभ कर किसानों को नियमानुसार हरसंभव मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करने के साथ ही किसानों को भी समझाईश दी कि वे प्रदेश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिये बढ़ाई गई आवेदन की तिथि 31 अगस्त तक हर हाल में अपनी फसलों का बीमा करायें।



इंदौर कलेक्टर ने लिया खरीफ फसलों का जायजा



इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ इंदौर जिले के सनावदिया गांव का भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी भी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने सोयाबीन की फसलों में आ रहे स्टेम फ्लाई के प्रकोप को देखा। इससे हुई फसलों की क्षति की जानकारी भी ली। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने अपने भ्रमण के दौरान किसानों से चर्चा की और वर्तमान में फसलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। किसानों ने सोयाबीन की फसल पर हुये प्रकोप की जानकारी दी। कलेक्टर श्री सिंह ने सनावदिया गांव के खेतों का अवलोकन किया और फसलों की स्थिति देखी। उन्होंने पूरे जिले में फसल वार, किस्म वार प्रकोप की जानकारी सकलित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल ने किसानों को जानकारी दी कि राज्य शासन द्वारा फसल बीमा के तहत प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है।

सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन इसी माह बुलाएँ

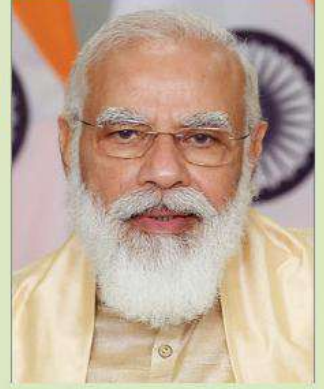
भोपाल। सहकारिता आयुक्त श्री आशीष सक्सेना ने सभी सहकारी संस्थाओं को आदेश दिया है कि सहकारी अधिनियम की धारा 49 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 6 माह के अंदर संस्था का वार्षिक साधारण सम्मेलन बुलाना आवश्यक है। इसलिए सितंबर 2020 में संस्थाओं के वार्षिक सम्मेलन आवश्यक रूप से बुला लें। श्री सक्सेना ने निर्देश दिया है कि वार्षिक साधारण सम्मेलन में कोविड-19 की गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सेनेटाइजर की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यदि आवश्यक हो तो सभा आयोजित करने हेतु कलेक्टर अथवा उसके अधिकृत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की जाए।



आशीष सक्सेना

ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल देश की पहली ऐसी बिजली वितरण कंपनी है जिसमें कंपनी कार्यक्षेत्र के कॉर्पोरेट कार्यालय से लेकर क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक एवं वृत्त कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली से काम किया जा रहा है। कंपनी द्वारा 27 जुलाई से एनआईसी ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से सफलतापूर्वक ई-फाइल एवं पत्राचार किया जा रहा है।



भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदीजी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ



किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि यंत्र के लिए ऋण	खेत पर रोड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेवरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण



श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री पी.एन. गोडरिया
(प्रशासक एवं उपायुक्त)



श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री आलोक कुमार जैन
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री मनोज कुमार मेहता (शा.प्र. आलोट)
श्री वीरेन्द्रसिंह सोनगरा (पर्य. आलोट)

श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (शा.प्र. खारवाकलां)
श्री मोहन चौधरी (पर्य. खारवाकलां)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
कराड़िया, जि.रतलाम
श्री ओमप्रकाश कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
आलोट, जि.रतलाम
श्री हीरेन्द्रसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
निपानिया लिला, जि.रतलाम
श्री मोहन चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
पाटन, जि.रतलाम
श्री ओमप्रकाश कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बड़िया राठौर, जि.रतलाम
श्री हीरेन्द्रसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
खारवाकलां, जि.रतलाम
श्री मोहन चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
बरखेड़ाकलां, जि.रतलाम
श्री ओमप्रकाश कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
विक्रमगढ़, जि.रतलाम
श्री हीरेन्द्रसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
मण्डावल, जि.रतलाम
श्री मोहन चौधरी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
खुजरीदेवड़ा, जि.रतलाम
श्री ओमप्रकाश कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
तालोद, जि.रतलाम
श्री हीरेन्द्रसिंह सोलंकी (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
लसुड़िया सूरजमल, जि.रतलाम
श्री सुरेश गौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
शेरपुर खुर्द, जि.रतलाम
श्री योगेन्द्रसिंह सोनगरा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
पिपलिया सिसोदिया, जि.रतलाम
श्री वीरेन्द्रसिंह सोनगरा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
पंथ पिपलोदा, जि.रतलाम
श्री सुरेश गौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
कीम, जि.रतलाम
श्री योगेन्द्रसिंह सोनगरा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
भोजाखेड़ी, जि.रतलाम
श्री वीरेन्द्रसिंह सोनगरा (प्रबंधक)

प्रा.कृ.साख सह.संस्था मर्या.
कसारी हरोड़, जि.रतलाम
श्री सुरेश गौर (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

गिरदावरी एप में उद्यानिकी फसलों का पूर्ण रकबा शामिल करने के निर्देश

इन्दौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले के सभी तहसीलदारों को निर्देश दिये हैं कि वे राज्य स्तरीय गिरदावरी एप में उद्यानिकी फसलों को पूर्ण रकबा शामिल करवाये। इस एप में



मनीष सिंह

कम से कम 1/4 एकड़ को उद्यानिकी फसलों के लिये शामिल करते हुए उद्यानिकी फसल का नाम, उद्यानिकी फसलों का क्षेत्रफल एवं द्विफसलों का क्षेत्रफल संशोधित करवाये। इस कार्य में विकासखंड स्तरीय उद्यानिकी मैदानी अमले से वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी एवं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी का सहयोग ले। बताया गया कि वर्ष 2019-20 में उद्यानिकी फसलों का कुल क्षेत्रफल (द्वितीय अनुसार) 20.91 लाख हेक्टेयर है। कुल उद्यानिकी फसलों का उत्पादन 308.34 लाख मेट्रिक टन है। जबकि प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप के माध्यम से वर्तमान में वर्ष 2019-20 में कुल उद्यानिकी रकबा 5.99 लाख हेक्टेयर दर्शाया गया है। प्रदेश में राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी एप के माध्यम से एकत्र आंकड़ों में उद्यानिकी फसलों की सही एवं पूर्ण जानकारी परिलक्षित नहीं हो पा रही है। गिरदावरी एप हेतु राजस्व विभाग के निर्धारित फार्म के कॉलम में विशेष उद्यानिकी फसलों का नाम नहीं होने से राजस्व अमले द्वारा कृषि फसलों का ही रकबा शामिल किया जाता है। संभवतः राजस्व अमले द्वारा उद्यानिकी फसलों को छोड़ दिया जाता है।

प्रायवेट डॉक्टरों एवं क्लीनिकों की इंट्री सार्थक एप में अनिवार्य हो

इन्दौर। इंदौर संभागायुक्त डॉ. पवन कुमार शर्मा ने कोविड-19 के संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सभी प्रायवेट डॉक्टरों एवं क्लीनिकों की इंट्री सार्थक एप में अनिवार्य रूप से दर्ज करवाये। एप के माध्यम से सतत मॉनीटरिंग भी सुनिश्चित करें। साथ ही आईसीएमआर की गाइड लाइन के अनुसार सभी प्राथमिक कान्टेक्ट की सैंपलिंग भी अनिवार्य रूप से करवाये।



डॉ. पवन कुमार

डॉ. पवन कुमार शर्मा ने निर्देश दिये हैं कि सभी जिले इंदौर होम लोकेशन एप की ट्रेनिंग कराये, ताकि एप के माध्यम से होम लोकेशन सुनिश्चित की जा सके। सभी जिलों में सार्थक एप में दी गई होम क्वारेन्टाइन संबंधी फेसिलिटी की प्रॉपर स्टडी कर ली जाये तथा एप के माध्यम से मॉनीटरिंग की जाये। समस्त प्रायवेट डॉक्टर एवं प्रायवेट क्लीनिक को सार्थक एप में दर्ज कर लिया जाये। फीवर क्लीनिक में यदि किसी एक एरिया से ज्यादा केसेस आते हैं, तो उस क्षेत्र का सघन सर्वे किया जाये। लॉकडाउन समाप्त हो चुका है एवं बाजार, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल सभी खुल चुके हैं ऐसी स्थिति में पब्लिक की आवाजाही बहुत बढ़ गयी है, इसके मद्देनजर मॉस्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी रूप से पालन कराया जाये। पालन नहीं पाये जाने पर जुर्माने की सतत कार्रवाही की जाये।

संयुक्त संचालक कृषि द्वारा फसल निरीक्षण किया गया

उज्जैन। संयुक्त संचालक कृषि श्री डी.के.पाण्डेय द्वारा गत दिवस रतलाम जिले का दौरा कर शासकीय कृषि क्षेत्र पंचेड़ में उत्पादित सोयाबीन बीज जेएस 95-60 एवं आरबीएस 2001-4 का निरीक्षण किया गया। उन्होंने पलसोड़ा में हरी खाद का उपयोग करने वाले कृषक श्री कालूराम राठौर के खेत का निरीक्षण किया एवं ग्राम पलसोड़ा में मक्का फसल का अवलोकन किया।



मंडी बोर्ड तकनीकी संभाग क्र. 1 भोपाल में पदस्थ वरिष्ठ अंकेक्षक सोहनलाल छापरे की सेवाविपरीत पर विदाई देते हुए सहायक यंत्री श्री मुकेश शर्मा।



ए. दिनेश कुमार ललितपुर के नए कलेक्टर

ललितपुर। ए. दिनेश कुमार अब ललितपुर के नए कलेक्टर होंगे। पूर्व कलेक्टर योगेश कुमार शुक्ल का स्थानांतरण हो गया है।

सोयाबीन कृषकों के लिये सलाह

उज्जैन। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान परिषद द्वारा सोयाबीन कृषकों के लिये साप्ताहिक सलाह जारी करते हुए कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में सोयाबीन की कम समयावधि वाली किस्में जैसे जेएस-95-60, जेएस 20-34, जेएस 93-5 उगाई गई हैं, इस समय परिपक्वता की स्थिति में होकर कटाईयोग्य है। सोयाबीन की फलियों के चटकने से होने वाले नुकसान को बचाने के लिये तथा बारिश से सोयाबीन के बीज की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये शीघ्र-अतिशीघ्र सोयाबीन की फसल की कटाई करें एवं सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा कर तारपोलीन से ढंग दें।

संयुक्त संचालक कृषि श्री डी.के.पाण्डेय ने बताया कि सोयाबीन अनुसंधान परिषद द्वारा जारी की गई एडवायजरी के अनुसार सोयाबीन के भण्डारण के समय भण्डार गृह में पनपने वाले कीटों से सुरक्षा हेतु सोयाबीन की फसल पर प्रोफेनॉस 50 ईसी (1250 मिली) प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। इसी तरह आगामी वर्ष की बोवनी हेतु उपयोगी सोयाबीन बीज के लिये उगाई गई सोयाबीन की गहाई 350 से 400 आरपीएम वाले श्वेसर से करें, जिससे कि बीज अंकुरण पर विपरीत प्रभाव न हो।

बलराम जयंती पर कृषि विपणन

पुरस्कार योजना का झों

खरगोन। बलराम जयंती पर कृषि विपणन पुरस्कार योजना का झों कृषि उपज मंडी खरगोन में खोला गया। किसानों को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय सांसद श्री गजेन्द्र पटेल ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि अधोसंरचना कोष का अधिकाधिक लाभ किसानों को दिलवाने का कार्य करेगी। क्षेत्रीय विधायक श्री रवि जोशी ने कहा कि इस पुरस्कार योजना के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय आने वाले किसानों को जो राशि दी जाती है, उसे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से मिलकर वृद्धि करने की बात कही। मंडी सचिव श्री रामवीर किरार ने कृषि विपणन पुरस्कार योजना, मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना एवं हम्माल-तुलावटी सहायता योजना की जानकारी दी। संगोष्ठी में किसानों को ग्रामीण विस्तार अधिकारी पी.एच. बाचें, कृषि वैज्ञानिक के.सी. त्यागी द्वारा कृषि एवं उद्यानिकी फसलों के अधिक उत्पादन एवं जैविक खाद की जानकारी दी गई। इस अवसर पर सर्वश्री मोहन जायसवाल, राजेश रावत, मोहनलाल पाटीदार, रवि नाईक, किसान प्रतिनिधि सीताराम पाटीदार, कमलेश पाटीदार, बलराम रघुवंशी, अकलीम खान सहित एसडीएम सत्येन्द्र सिंह उपस्थित रहे। मंडी सचिव श्री किरार ने बताया कि इस मौके पर 2 झों खेले गए जिसमें पहला झों नागझिरी के प्रवीण शिवशंकर को 21 हजार रु. की राशि प्रदान की गई।

मनरेगा के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में वृहद वृक्षारोपण का शुभारम्भ

उज्जैन। सीईओ जिला पंचायत श्री अंकित अस्थाना ने मनरेगा के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में किये जाने वाले वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। ग्राम ढेंडिया में वृक्षारोपण के दौरान जानकारी दी गई कि यहां एक हेक्टेयर क्षेत्र में विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जायेगा। इस दौरान ग्राम ढेंडिया के सरपंच ने गांव में नक्षत्र वाटिका और वॉकिंग ट्रेक बनाये जाने की योजना के बारे में अधिकारियों से चर्चा की। उल्लेखनीय है कि इन्दौर रोड स्थित ग्राम ढेंडिया में प्रतिदिन सुबह शहर के काफी लोग साइकलिंग और वॉकिंग करते हुए आते हैं। गांव के समीप वृक्षारोपण किये जाने वाले क्षेत्र का विस्तारीकरण और सौन्दर्यीकरण किये जाने के लिये सीईओ श्री अंकित अस्थाना ने विधिवत प्रस्ताव बनाये जाने के निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को दिये।



मॉडल एक्ट अध्यादेश में संशोधन नहीं होने पर आंदोलन होगा

भोपाल। संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मॉडल एक्ट अध्यादेश में संशोधन को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड के अंतर्गत वर्तमान में कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 प्रावधानित है। प्रस्तावित मॉडल एक्ट में मंडी प्रांगण को सीमित किया जाकर मंडी डीमंड को मंडी प्रांगण में रखा गया किंतु नियमन व्यवस्था संचालक कृषि विपणन के अधीन रखा गया है। साथ ही मंडी शुल्क आदि का प्रावधान का वर्गीकरण भी नहीं किया गया। साथ ही इसमें अनेक प्रकार की विसंगतियाँ मॉडल एक्ट में रखी गई हैं। मोर्चा ने माँग की है कि मंडी समिति एवं मंडी बोर्ड में पदस्थ अमले को संचालक कृषि विपणन में शामिल किया जाए। मंडियों में निर्मित दुकानों-गोदामों को स्व वित्तीय योजना के अंतर्गत आवंटित किया जाए जिससे व्यापारियों को सुविधा मिले। साथ ही वर्तमान मंडी शुल्क को भी कम किया जाए। हम्माल-तुलावटियों को मासिक पेंशन की व्यवस्था की जाए। किसानों को भी मासिक पुरस्कार दिया जाए। उपरोक्त माँगों का निराकरण नहीं होने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।

74वाँ स्वाधीनता दिवस धूमधाम से मनाया



मंडी बोर्ड मुख्यालय में राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते मानवीय कृषिमंत्री श्री कमल पटेल। इस अवसर पर उपस्थित प्रबंध संचालक श्री संदीप यादव सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे।



कृषि उपज मंडी समिति खिरकिया (हरदा) में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण करते मंडी सचिव श्री आर.पी.एस. जैन एवं मंडी समिति के अधिकारी-कर्मचारी।



कृषि उपज मंडी समिति हरदा में स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण करते हुए मंडी सचिव श्री संजीव श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारीगण।



मंडी बोर्ड ऑफिसल कार्यालय इंदौर में ध्वजारोहण अवसर पर संयुक्त संचालक एस.बी. सिंह, कार्यपालन यंत्री मधुकर पवार एवं अन्य अधिकारी।



कृषि उपज मंडी समिति इटारसी में ध्वजारोहण करते भारसाधक अधिकारी श्री सतीश राय, मंडी सचिव श्री उमेश बसेड़िया एवं अधिकारी-कर्मचारी।

यूरिया की कालाबाजारी करने वाले 3 विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज

रीवा। कलेक्टर इलैयाराजा टी ने तीन निजी उर्वरक विक्रेताओं द्वारा यूरिया की कालाबाजारी तथा टाप-20 यूरिया बायर में से अत्यधिक यूरिया वितरण में अनियमितता करते पाये जाने पर इन विक्रेताओं के विरुद्ध संबंधित थानों में एफआईआर दर्ज करायी गयी है। कलेक्टर ने बताया कि गुड़ चौराहा स्थित मेसर्स कन्हैया खाद भण्डार, विकासखण्ड गगेव के ग्राम गड़ के मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता तथा बेलवा पैकन ग्राम के

मेसर्स तेजभान कुशवाहा के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही की गयी है। इसी के साथ जिले के 9 उर्वरक विक्रेताओं के उर्वरक लायसेंस निलंबित किये गये हैं। कृषि उप संचालक यूपी बागरी ने बताया कि जिले के टाप-20 यूरिया बायर की सूची के अनुसार 9 उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक लायसेंस निलंबित किया गया है।

मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में अधिकारियों-कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री संजय कौल 31 अगस्त को सेवानिवृत्त हो गए। प्रदेश की मंडियों में पदस्थ मंडी सचिव, मंडी निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक एवं लेखापाल भी सेवानिवृत्ति हुए जिनकी विस्तृत सूची इस प्रकार है :-

क्र.	नाम	पदनाम	मंडी समिति
1.	ताराचंद पाटीदार	सचिव-ब	श्योपुर बड़ौदा
2.	सुनील कुमार गौर	सचिव-ब	आं.का. भोपाल
3.	नारायण शर्मा	सचिव-स	हनुमना
4.	ओमप्र काश रैकवार	सचिव-स	निवाड़ी
5.	माँगीलाल बसोड़	सचिव-स	गंधवानी
6.	बी.पी. मटकर	मंडी निरीक्षक	सौसर
7.	भरतलाल साहू	मंडी निरीक्षक	बालाघाट
8.	मोतीलाल चौधरी	मंडी निरीक्षक	सैंधवा
9.	आनंदीलाल साहू	लेखापाल	आष्टा
10.	भेरूलाल शर्मा	सहा.उपनिरी.	महू
11.	तारासिंह रघुवंशी	सहा.उपनिरी.	महिदपुर
12.	अनिल कुमार व्यास	सहा.उपनिरी.	जावरा
13.	विनय श्रीवास्तव	सहा.उपनिरी.	निवाड़ी
14.	विद्याधर यादव	सहा.उपनिरी.	बीना

बीमांकन अवधि बढ़ाने के लिये

जताया केन्द्र का आभार

भोपाल। बाढ़ प्रभावित प्रदेश के पांच जिले रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा जिले के किसानों को केन्द्र सरकार ने राहत देते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के प्रीमियम जमा कराने की अवधि बढ़ा दी है। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने इन जिलों के किसानों की ओर से केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।

मंत्री श्री पटेल ने कहा कि प्रदेश में फसल बीमा की अवधि दो बार बढ़ाने के बावजूद अगस्त के अंतिम दिनों में आई भीषण बाढ़ के कारण सभी किसान बीमा नहीं करा सके थे। उन्होंने स्वयं केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री तोमर को पत्र लिखकर प्रीमियम जमा कराने की समय-सीमा 7 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की थी। श्री पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पत्र लिखकर केंद्र सरकार से आग्रह किया था जिसे विशेष प्रकरण मानते हुए प्रदेश के पांच जिले के किसानों को राहत दी है। श्री पटेल ने कहा कि फसल बीमा हो जाने से किसानों के नुकसान की भरपाई की जा सकेगी जिससे वह मजबूती के साथ कृषि कार्य कर सकें।

मंडी बोर्ड में अधिकारियों के स्थानांतरण

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने मंडियों में पदस्थ कुछ मंडी सचिवों, मंडी निरीक्षक, मंडी सहायक, उप निरीक्षक को इधर से उधर किया है। स्थानांतरण किये गये अधिकारियों की सूची इस प्रकार है :-

(मंडी सचिव)

1. किशोर माहेश्वरी	जावरा	सीहोर
(सहायक संचालक)		
2. वीरेंद्र कुमार आर्य	सीहोर	आष्टा
3. योगेश नागले	आष्टा	मुख्यालय
4. श्रीमती ऋतु गढ़वाल	सिलवानी	होशंगाबाद

(मंडी निरीक्षक)

1. प्रेमसिंह मीणा	गुना	कुंभराज
(प्र.सचिव)		
2. उमाशंकर शर्मा	गैरतगंज	बासौदा

(सहायक उप निरीक्षक)

1. सुश्री पूजा सिंह	सोनकच्छ	सीहोर
2. सचिन सक्सेना	बरेली	नरसिंहपुर
3. सुश्री कीर्ति कस्तवार	मकसूदनगढ़	श्योपुर
4. आदित्यवर्धन सिंह	लश्कर	भिंड
5. देवीसिंह केशरिया	पचोर	ब्यावरा
6. केशरीमल चौरसिया	मुलताई	टिमरनी
7. अजयबहादुर सिंह बैस	बंडा	देवरी
8. हनीफ खान	केसली	देवरी
9. नौबद सनोड़िया	केवलारी	सिवी
10. सुरेन्द्र सिंह पटेल	बदनावर	धार
11. हिमांशु यादव	आं.का.भोपाल	ओबेदुल्लागंज
(आदेश निरस्त)		
12. विक्रमसिंह जमरा	गुना	अलीराजपुर
13. सुश्री महिमा सोनकिया	खरगोन	खंडवा
14. दिलीप वास्कले	बदनावर	बड़वानी
15. श्रीमती सुनीता परते	अंजड़	बड़वानी
16. भगवानदास भिलवार	निवाड़ी	बदरवास

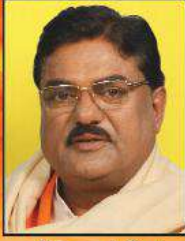
आत्मा परियोजना में एक्सपर्ट

वैज्ञानिक रखा जायेगा

रीवा। कृषकों को कृषि संबंधी सलाह देने, उन्नत कृषि तकनीक बताने एवं कृषि यंत्रीकरण की जानकारी देने के उद्देश्य से आत्मा परियोजना के अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिक को एक्सपर्ट वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त किया जायेगा। उपरोक्त कृषि वैज्ञानिक को 24 हजार रुपये वार्षिक मानदेय दिया जायेगा।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से अपील

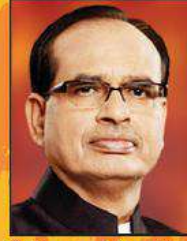
मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

सुश्री कामिनी ठाकुर : श्री किशोर नरगावे
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
सैलाना, जिला रतलाम (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

किसान भाइयों से विनम्र अपील

किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
हम्माल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हम्माल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री रमेशचंद्र सिसोदिया : श्री कैलाशचंद्र परमार
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
ताल, जिला रतलाम (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ

किसान भाइयों से अपील

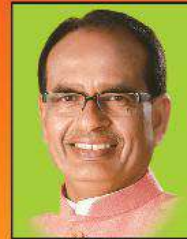
किसान भाई अपनी उपज का क्रय-विक्रय मंडी प्रांगण में ही आकर करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ठेरे पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होने पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।

डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री एम.एल. आर्य : श्री विनोद कुमार जैन
(भारसाधक अधिकारी) (प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

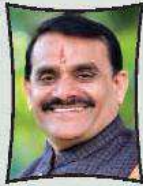
डॉ. एस.बी. सिंह

संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

श्री मनीष जैन
(भारसाधक अधिकारी)

श्री पर्वतलाल
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति
मनासा, जिला रतलाम (म.प्र.)



भारत के माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी
को जन्मदिवस की हार्दिक बधाइयाँ

**स्वाधीनता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ पर
हार्दिक शुभकामनाएँ**



**किसान फेडिट कार्ड
कृषि संघ के लिए ऋण
खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुग्ध डेयरी योजना (पशुपालन)
मत्स्य पालन हेतु ऋण
स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण**



श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)



श्री भारत सिंह चौहान
(प्रशासक एवं उपायुक्त सहकारिता)



श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)



श्री पी.एन. यादव
(वरिष्ठ महाप्रबंधक)

सौजन्य से

श्री कुँवरलाल मारू (शा.प्र. जीरन) श्री सोमदत्त जयंत (शा.प्र. चीताखेड़ा) श्री विनय अग्रवाल (शा.प्र. दड़ौली)
श्री अब्दुल हकीम शेख (शा.प्र. मोरवन) श्री लक्ष्मीनारायण मीणा (शा.प्र. जावद) श्री संजय चेलावत (शा.प्र. कुकड़ेश्वर)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जीरन, जि.नीमच
श्री गौतमलाल अहीर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कोट इश्तमुरार, जि.नीमच
श्री लखतसिंह शक्तावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. हरवार, जि.नीमच
श्री विक्रमसिंह सोनगरा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चल्दू, जि.नीमच
श्री मांगूसिंह शक्तावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. चीताखेड़ा, जि.नीमच
श्री जितेन्द्र कुमार जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कराड़िया महाराज, जि.नीमच
श्री भगवानसिंह राणावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सबड़िया, जि.नीमच
श्री सुनील कुमार जैन (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. दड़ौली, जि.नीमच
श्री गोपालसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. डिकैत, जि.नीमच
श्री विनोद कुमार शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. रामनगर सुठौली, जि.नीमच
श्री गोपालसिंह राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कुकड़ेश्वर, जि.नीमच
श्री तेजपाल कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. पिपघोटा, जि.नीमच
श्री तेजपाल कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. कुण्डालिया, जि.नीमच
श्री तेजपाल कुमावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. मोरवन, जि.नीमच
श्री श्रवण कुमार अहीर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. धामनिया, जि.नीमच
श्री धनराज राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. लासूर, जि.नीमच
श्री धनराज राठौर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सर. महाराज, जि.नीमच
श्री श्रवण कुमार अहीर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. जावद, जि.नीमच
श्री गोपालप्रसाद शर्मा (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. खोर, जि.नीमच
श्री सत्यप्रकाश नागर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. वावल, जि.नीमच
श्री धर्मेन्द्रसिंह चंद्रावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. अठाना, जि.नीमच
श्री सत्यप्रकाश नागर (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. सुवाखेड़ा, जि.नीमच
श्री धर्मेन्द्रसिंह चंद्रावत (प्रबंधक)

प्रा.कृ. साख सह. संस्था मर्या. केशरपुरा, जि.नीमच
श्री धर्मेन्द्रसिंह चंद्रावत (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

प्रत्येक विकास खंड में कृषक उत्पादक संगठन का गठन हो

लखनऊ। उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सहारनपुर मण्डल की 50 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं सहित अन्य विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने परियोजनाओं व विकास कार्यों को समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण ढंग से मानकों के अनुसार पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए शासन स्तर पर धनराशि की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को समय से धनराशि अवमुक्त किए जाने के निर्देश दिए।



मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विकास कार्यों के लिए जनपद स्तर पर भूमि की आवश्यकता है, उससे सम्बन्धित कार्यवाही में विलम्ब न हो। शीघ्र ही भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सामुदायिक शौचालय व ग्राम पंचायत सचिवालय के निर्माण सम्बन्धी कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण कराने की कार्यवाही हो। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत कृषि

भण्डारण के निर्माण कार्यों को भी प्राथमिकता के स्तर पर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे कृषकों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने जनपद स्तर पर बैंकर्स समिति के साथ बैठकें किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में गन्ना विकास मंत्री श्री सुरेश राणा, सांसद व विधायक, मुख्य सचिव श्री आर.के. तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव सिंचाई श्री टी० वेंकटेश, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में जैविक दवाईयाँ बना रही महिलाएँ

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए ग्राम सुराजी योजना तथा गोधन न्याय योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय संसाधन से जैविक खेती और जैविक खाद के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। रासायनिक खाद के बेतरतीब उपयोग से धरती की उर्वरा शक्ति नष्ट हो रही है। ऐसे में जैविक खाद के प्रचलन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन में ग्रामीण महिलाएँ भी पीछे नहीं हैं। जनपद पंचायत छुरा की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रूचि शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) अंतर्गत विकासखण्ड छुरा के ग्राम रानी परतेवा के तिग्गा क्लस्टर के ग्राम संगठन जय गंगा मैया के जय मां सरस्वती समूह की सक्रिय सदस्य श्रीमती गायत्री साहू द्वारा इस कार्य को बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। बिहान के सीएसएमएस परियोजना के तहत जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए एनपीएम शॉप के माध्यम से ग्राम स्तर पर विभिन्न जैविक दवाईयों तथा



खाद का निर्माण और उपयोग किया जा रहा है। सदस्य गायत्री साहू द्वारा बताया गया कि वे नाडेप खाद, केचुआ खाद, घना जीवामृत, नीमास्त्र, अग्नास्त्र, बेसरम पत्रा दवाई, डण्डी दवाई, अमृत पानी तथा अमृत खाद का निर्माण स्वयं कर रही हैं। निर्माण के साथ-साथ इन जैविक दवाईयों का उपयोग स्वयं के बाड़ी एवं खेत में लगे फसल के बीमारी एवं कीटों से बचाव हेतु कर रही हैं। गायत्री ने बताया कि इन दवाईयों का निर्माण स्थानीय संसाधनों से किया गया है तथा निर्माण लागत लगभग नहीं के बराबर है। दवाईयाँ बिहान के दुकान के माध्यम से विक्रय भी हो रहा है, जिससे यह अतिरिक्त आय का स्रोत बन गया है। इन दवाईयों की कीमत प्रति बोतल 50 से 80 रुपये तक है, यह कीमत बाजार में मिलने वाले रासायनिक दवाई से बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि इस एनपीएम शॉप के माध्यम से वे 5-6 हजार रुपये प्रत्येक सीजन में कमा लेती हैं। साथ ही साथ गायत्री द्वारा दूसरे ग्रामों, विकासखण्ड व जिले में इसके निर्माण हेतु प्रशिक्षण भी दे रही हैं।



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)

डॉ. एस.बी. सिंह
संयुक्त संचालक
मंडी बोर्ड उज्जैन

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
नीलामी के समय किसान भाई अपने ढेर पर उपस्थित रहें उचित मूल्य प्राप्त होवे पर ही विक्रय करें।
मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना का लाभ उठाएँ और सही तौल एवं समय पर भुगतान पाएँ।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
हमाल-तुलावटी भाई मुख्यमंत्री हमाल तुलावटी योजना का लाभ अवश्य प्राप्त करें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें। किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।

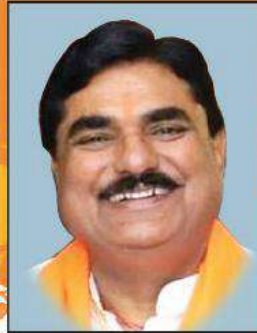
श्री अवि प्रसाद
(भारसाधक अधिकारी)

श्री अश्विन सिन्हा
(प्रभारी सचिव)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन, जिला उज्जैन (म.प्र.)



श्री शिवराजसिंह चौहान
(मुख्यमंत्री)



श्री कमल पटेल
(कृषि मंत्री)



श्री गिराज डंडौतिया
(कृषि राज्यमंत्री)



सुश्री नेहा साहू
(भारसाधक अधिकारी)

श्री ररसु वसुनिया
(प्रभारी सचिव)

किसान भाइयों से अपील

मंडी प्रांगण में प्रवेश करते समय किसान भाई अपनी उपज दर्ज कराएँ और साथ ही प्रवेश पर्ची भी अवश्य प्राप्त करें।
किसान भाई कृषि उपज साफ करके मंडी में लाएँ ताकि उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करें।
किसान ही हमारे सच्चे मित्र हैं।



श्री चंद्रशेखर वशिष्ठ
(संयुक्त संचालक)

सौजन्य से : कृषि उपज मंडी समिति बदनावर, जिला धार (म.प्र.)

● आचार्य पं. रामचंद्र शर्मा 'वैदिक'

अध्यक्ष : म.प्र. ज्योतिष एवं विद्वत् परिषद
376, म.गौ. मार्ग (बड़े गणपति के पास), इंदौर
फोन : 0731-2414181, मो. 9755014181



मेष

राशि के जातक और जातिकाओं को कैरियर व व्यापारिक मामलों को संवारने के अनेक शुभ व अनुकूल अवसर देने वाला रहेगा। रोजगार पाने के प्रयास बाखूब सफल रहेंगे। इस माह आप अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे।

वृषभ

इस राशि के जातक व जातिकाओं को आजीविका के संदर्भों में महती कामयाबी प्राप्त होने के योग रहेंगे। वांछित संस्थाओं के मध्य सेवाएं देने व व्यवसायिक जीवन में बढ़त हासिल करने में कदम-कदम पर मौके मिलेंगे।

मिथुन

इस राशि के जातक व जातिकाओं को कैरियर व व्यवसाय के संबंधित क्षेत्रों में मनोनुकूल परिणाम देने वाला रहेगा। यदि आप प्रतियोगी क्षेत्रों में आगे बढ़ने की तमन्ना रखते हैं, तो इस माह आपको अनेक अवसर उपलब्ध होंगे।

कर्क

इस राशि के जातक व जातिकाओं को इच्छित रोजगार प्राप्त करने में कामयाबी रहेगी। इस मास किसी मित्र से वांछित संस्थान में सेवाओं के अवसरों का पता चलेगा। यदि आप कार्यरत हैं, तो इस मास पदोन्नति के योग हैं।

सिंह

इस राशि के जातक व जातिकाओं को कैरियर को संवारने के अनुकूल अवसर रहेंगे। निजी व सरकारी संस्थाओं में दिया गया साक्षात्कार सफलता के संकेत देने वाला रहेगा। यदि आप सेवारत हैं, तो इस मास खुशखबर मिलेगी।

कन्या

इस राशि के जातक व जातिकाओं को व्यावसायिक जीवन को अधिक सुन्दर व प्रभावशाली बनाने में प्रगति रहेगी। यदि आप निजी व सरकारी क्षेत्रों की संस्थाओं में कार्यरत हैं, तो इस मास आपको नए अवसर मिलेंगे।

तुला

इस राशि के जातक व जातिकाओं को वांछित संस्थाओं में कार्य करने तथा अपनी प्रतिभा का सही प्रदर्शन करने की उत्सुकता साफ तौर पर रहेगी। आप कार्य व व्यापार के संबंधित क्षेत्रों में दबदबा बनाने में कामयाब होंगे।

वृश्चिक

इस राशि के जातक व जातिकाएं वांछित क्षेत्रों में अपने कैरियर को चमकाने में कामयाब रहेंगे। तकनीक, प्रबंधन, चिकित्सा, कानून सहित नेतृत्व के संदर्भों में इस माह मजबूत पकड़ बनाने के आसार हैं।

धनु

इस राशि के जातक व जातिकाओं को रोजगार प्राप्त करने में महती प्रगति रहेगी। प्राप्त रोजगार के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं के बढ़िया प्रदर्शन से आगामी समय में अच्छे कैरियर की राह और आसान होती दिखाई देगी।

मकर

इस राशि के जातक व जातिकाओं को आजीविका से संबंधित प्रत्येक पहलुओं को संवारने की प्रबल तमन्ना रहेगी। वैसे इस माह के दूसरे व चतुर्थ भाग प्रतियोगी, क्रीड़ा, प्रबंधन, फिल्मादि के संबंधित क्षेत्रों में अवसर के योग हैं।

कुम्भ

इस राशि के जातक व जातिकाओं को अच्छी संस्थाओं के मध्य काम करने व कैरियर को चमकाने के अनेक सुनहरे अवसर रहेंगे। यदि आप स्वतः का व्यवसाय करते हैं, तो भी इस माह आप अपने व्यवसाय में प्रगति करेंगे।

मीन

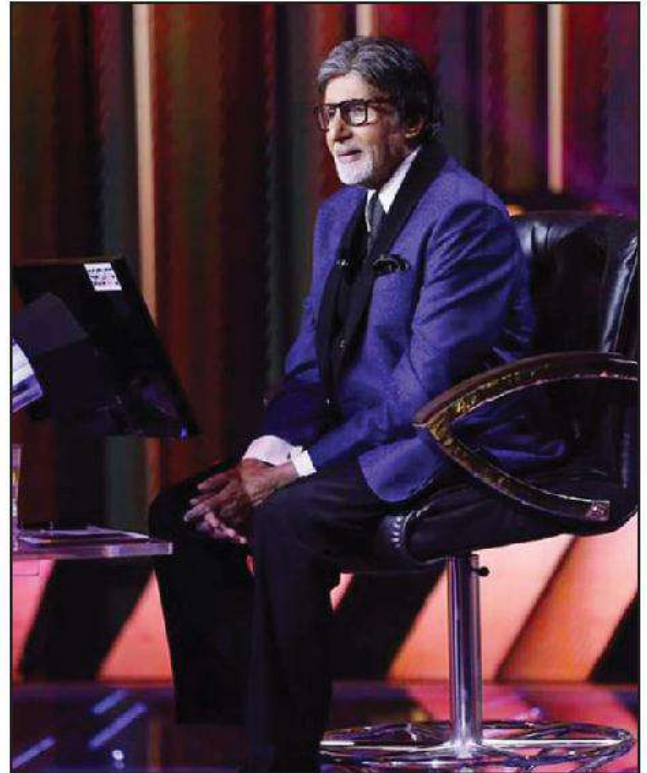
इस राशि के जातक व जातिकाओं को कैरियर को समुन्नत करने में महती प्रगति के योग रहेंगे। इस माह किसी प्रतिष्ठित संस्था के द्वारा आपको सेवाओं हेतु चुने जाने के योग रहेंगे। यदि आप कार्यरत हैं तो पदोन्नति के योग हैं।

देवियों और सज्जनों...! केबीसी की शूटिंग शुरू

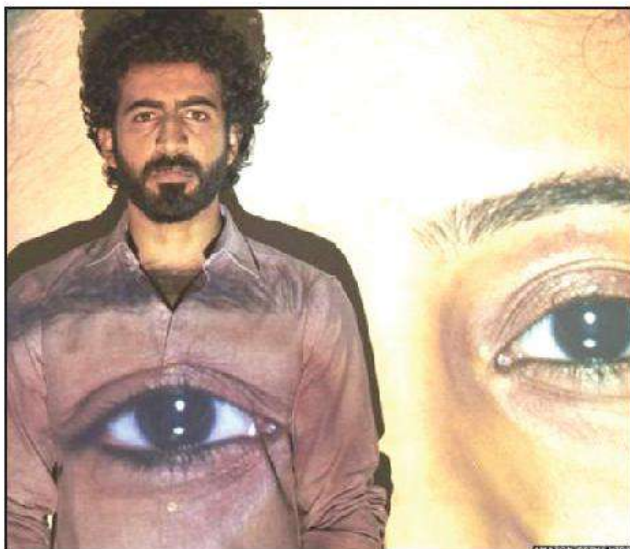
“देवियों और सज्जनों, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत कीजिए...” “तालियां बजती रहनी चाहिए...” कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्राम में इस साल सेट पर दर्शकों की तालियां नहीं बजेंगी क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के से इस बार केबीसी के सेट पर दर्शक नहीं होंगे। अमिताभ के साथ मुंबई में शो की शूटिंग शुरू हो गई। अमिताभ ने कुछ तस्वीरें द्वाँट की और लिखा, “12वां पर्व, केबीसी- कौन बनेगा करोड़पति, आरंभ!”

प्रोग्राम से जुड़े लोगों ने बताया कि नई गाइडलाइन्स के मुताबिक प्रोग्राम में लाइव दर्शक नहीं हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा सेट पर काम करने वालों की संख्या भी बहुत कम कर दी गई है। कुछ दिनों पहले अमिताभ ने सेट की एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें क्रू मेंबर पीपीई किट पहने नज़र आ रहे थे।

कौन बनेगा करोड़पति का यह 12वां सीज़न है, और इस बार इसकी टैगलाइन है- जो भी हो, सेटबैक का जवाब कमबैक से दो। केबीसी कैपेन के डायरेक्टर नितेश तिवारी के मुताबिक, हम सभी के लिए यह साल हर मामले में बहुत अलग और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह सीखने और उन बातों को खोजने का भी साल है जिनके बारे में कभी सोचा नहीं गया।



पहली ‘लॉकडाउन फिल्म’ को मिल रही है तारीफ



जब अप्रैल में भारत में काम और जिंदगी लॉकडाउन की वजह से ठहर गए थे, तब एक युवा निर्देशक ने अपनी अगली फिल्म बनाने की ठानी। लॉकडाउन की वजह से सिनेमा हॉल बंद थे। केरल में 60 फिल्मों लटक गई थी लेकिन निर्देशक महेश

नारायणन के इरादे को इस बात से फर्क नहीं पड़ा। मलयालम में फिल्में बनाने वाले महेश ने स्क्रिप्ट लिखी और एक लोकप्रिय एक्टर को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार किया। इसके लिए उन्होंने 50 लोगों की टीम तैयार की। ये फिल्म महज तीन हफ्ते में शूट कर ली गई और इसके लिए कोच्चि शहर के छह अपार्टमेंट इस्तेमाल किए गए। ये अपार्टमेंट फिल्म का सेट भी थे, दफ्तर भी, प्रोडक्शन हब भी और फिल्म की कास्ट और क्रू के लिए घर भी। सोशल डिस्टेंसिंग ध्यान में रखते हुए ये फिल्म ज्यादातर आई-फोन से शूट की गई है और 22 दिनों में पूरी कर ली गई।

फिल्म का नाम है- ‘सुई सून’ जो एक सस्पेंस ड्रामा है। जैसा की महेश कहते हैं- शायद भारत की पहली घर में बनी लॉकडाउन फिल्म। पिछले हफ्ते ही ये फिल्म अमेज़न प्राइम पर रिलीज की गई है। 90 मिनट की बिना गानों की छोटी सी लेकिन अपने आप में एक असाधारण फिल्म है। एक सिनेमा समीक्षक ने फिल्म के बारे में कहा है कि ये डूब जाने जैसा लाजवाब अनुभव है। दूसरे समीक्षक ने कहा है कि ये एक मौलिक फिल्म है जो दर्शक को अनोखा अनुभव देती है। साथ ही फिल्म की विजुअल सेटिंग को लेकर भी तारीफ हुई है।



माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र मोदीजी को
जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ

स्वाधीनता दिवस की 73वीं वर्षगाँठ
पर हार्दिक शुभकामनाएँ

किसानों को **0%** ब्याज पर ऋण

किसान क्रेडिट कार्ड	कृषि रंग के लिए ऋण	खेत पर शेड निर्माण हेतु ऋण
दुध डेयरी योजना (पशुपालन)	मत्स्य पालन हेतु ऋण	स्थायी विद्युत कनेक्शन हेतु ऋण



श्री चंद्रमौलि शुक्ला
(कलेक्टर एवं प्रशासक)

श्री बी.एल. मकवाना
(संयुक्त आयुक्त सहकारिता)

श्री मनोज गुप्ता
(उपायुक्त)

श्री रवि ठक्कर
(संभागीय शाखा प्रबंधक)

श्री के.एन. त्रिपाठी
(बैंक सीईओ)

सौजन्य से

श्री मुकेश राठौर (शा.प्र. उदयनगर) | श्री लालसिंह बेनना (पर्यवेक्षक उदयनगर)
श्री लक्ष्मीनारायण मिश्रा (शा.प्र. बागली) | श्री कैलाशचंद्र मालवीय (पर्यवेक्षक बागली)

सेवा सह. संस्था मर्या. उदयनगर, जि.देवास
श्री ललित शर्मा (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. बागली, जि.देवास
श्री जीवन गोस्वामी (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. पुंजापुरा, जि.देवास
श्री रामसिंह तोमर (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. बेहरी, जि.देवास
श्री दुलीचंद मिश्रा (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. चट्पूरा, जि.देवास
श्री गंगाराम मौर्य (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. कमलापुर, जि.देवास
श्री वेणीराम राठौर (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. पानकुआ, जि.देवास
श्री कैलाशसिंह सेन्धव (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. चापड़ा, जि.देवास
श्री राजेशसिंह राजपूत (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. देवनालिया, जि.देवास
श्री बट्टीलाल सोलंकी (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. मातमौर, जि.देवास
श्री कैलाशचंद्र मालवीय (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. पांडूतालाब जि.देवास
श्री मुकेश मंडलोई (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. डिगोद, जि.देवास
श्री गणेश राम जाट (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. पीलाखाल, जि.देवास
श्री विष्णुप्र साद मीणा (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. आगुली, जि.देवास
श्री धीरजसिंह सेन्धव (प्रबंधक)

सेवा सह. संस्था मर्या. रतनपुर, जि.देवास
श्री इन्दरसिंह परमार (प्रबंधक)

समस्त संस्थाओं के प्रशासकों की ओर से

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ

शहीदों की चिताओं पर लगे हरे वरस मेले
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा



आत्मनिर्भर व्यक्ति

बुद्धी जीवन व्यतीत करने के लिए
सभी व्यवहारों को कर लेता है।
आत्मनिर्भरता ही उन्नति का आधार है।
हम प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को
आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं।



नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर



महान्याय शाह



शंकर शाह



भीमा नावक



वीर सुरेन्द्र साहू



चन्द्रशेखर आजाद



रानी लक्ष्मीबाई



रघुनाथ सिंह मण्डल



सीताराम कँवर



राणा बख्शर सिंह



तात्या टोपे



टंट्या भील



रानी अवंतीबाई

D-18014



शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

आपका साथ मध्यप्रदेश का विकास

1. संबल योजना - गरीबों को फिर मिला संबल। एक अप्रैल से 31 जुलाई 2020 तक योजना के विभिन्न घटकों में 25 हजार से अधिक हितधारियों को 268 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता स्वीकृत।
2. पथ व्यवसायी योजना - आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण पथ विक्रेताओं को कार्यशील पूंजी का व्याज मुक्त ऋण।
3. श्रम सिद्धि अभियान - प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा रोजगार अभियान। 61 लाख 34 हजार 426 श्रमिकों का नियोजन। 3536 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का मुताबक।
4. श्रमिक आयोग का गठन - श्रमिकों को बेहतर जीवन दिलाने के एकमात्र प्रयासों की दिशा में अहम कदम।

5. रोजगार सेतु पोर्टल - रोजगार के अवसरों का नया आस्मान। 13 लाख 10 हजार से अधिक श्रमिक और 31 हजार से अधिक नियोजता पंजीकृत। 38,900 से अधिक लोगों को रोजगार मिला।
6. श्रम कानूनों में संशोधन - क्रांतिकारी संशोधनों से श्रमिकों के हितों का संरक्षण एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन।
7. पंच परमेष्ठ योजना पुनः प्रारंभ - 52 हजार से अधिक गांवों के विकास के लिये 14वें वित्त आयोग के 1555 करोड़ रुपये तथा 15वें वित्त आयोग के 996 करोड़ रुपये जारी।
8. गेहूँ उपार्जन में सबसे आगे - एक करोड़ 29 लाख 42 हजार मीट्रिक टन गेहूँ का उपार्जन। देश में प्रथम स्थान।
9. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - 16 लाख किसानों को 3100 करोड़ रुपये की फसल बीमा राशि का एक बिलक में मुताबक।

10. मंडी अधिनियम में सुधार - किसानों को घर बैठे देश की किसी भी मंडी में फसल बेचने की सुविधा। किसान एवं व्यापारी दोनों के लाभ की पहल।
11. चंबल प्रोग्रेस-वे - चंबल क्षेत्र को मिली विकास की अभूतपूर्व सीमा।
12. बिजली बिलों में राहत - 97 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 623 करोड़ रुपये से अधिक की राहत।
13. किल कोरोना अभियान - कोरोना संक्रमण की घेन तोड़ने के लिए 15 दिन का डोर-टू-डोर सर्वे अभियान।
14. उद्योगों को रियायतें - कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत उद्योग संवर्धन नीति एवं निवेश प्रोत्साहन योजना में लाभ ले रही औद्योगिक इकाइयों को संचालन तथा मुताबक संबंधी रियायतें।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश से
आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोपाल में आयोजित होने वाले शैलीक स्मारक और माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन को प्रातः 8:50 बजे अप. इन. माध्यमों पर लाइव देख सकते हैं - यूट्यूब, मध्यप्रदेश @DMMMadhyaPradesh, @JasSamparkMP, @DMMMadhyaPradesh, @JasSamparkMP, @DMMMadhyaPradesh, @JasSamparkMP